असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

15 जुलाई, 2019

षोडश विधान सभा — सोमवार, तिथि 15 जुलाई, 2019 ई0
त्रयोदश सत्र — 24 आषाढ़, 1941(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर काल ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी जगह पर खड़े हो गये)

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, पूरा उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में है, लोग डूब रहे हैं लेकिन उनको कोई देखने वाला नहीं है । जो मर रहे हैं उनकी लाश उठाने वाला कोई नहीं है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप अति-महत्वपूर्ण बात की चर्चा कर रहे हैं और आज बिहार के कई जिलों में बाढ़ का रूप भयंकर होता जा रहा है । यह बात आसन के संज्ञान में है और पूरे सदन के संज्ञान में भी है ।

हमारा यह अनुरोध है कि इस विषय को उठाने का जो सही समय है, उस समय उठाइयेगा और देख लीजिये, अगर इससे भी अलग इसपर कोई चर्चा की गुंजाइश बनेगी तो आसन पूर्ण-रूप से आपका सहयोग करेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह ठीक है कि आसन सहयोग करेगा लेकिन जो लोग बाढ़ से मर रहे हैं, उनकी लाश उठाने वाला कोई नहीं है, कहीं एक छटॉक चूड़ा-गुड़ तक नहीं मिल रहा है.....

अध्यक्ष : जो अगर मर गये हैं.....

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सरकार सोयी हुई है, कोई कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय.....

अध्यक्ष : सदानन्द बाबू को बोलने दीजिये ।

(व्यवधान)

महबूब जी, आप वस्त्र पहने हुये हैं, क्यों दूसरा वस्त्र सामने में लपेट रहे हैं ? आप वह हटा दीजिये । आप वह प्लेकार्ड दिखाकर उस बात की महत्ता घटा रहे हैं । यह आप समझिये । प्लेकार्ड दिखाने से वह महत्वपूर्ण हो जाता है ? महत्वपूर्ण सदन में आपका बोलना है । कागज दिखाना कोई महत्व नहीं बढ़ाता है, वह किसी बात

के महत्व या उसकी गम्भीरता घटा देता है । सभी माननीय सदस्य एक साथ बोल रहे हैं, बोलने दीजिये सदानन्द बाबू को ।

श्री सदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा कि बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और बहुत ही कठिनतम घड़ियों से बाढ़ प्रभावित लोग गुजर रहे हैं । इसपर एक विशेष वाद-विवाद करवा देना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, सभी दलीय नेताओं की भी इच्छा होगी और सरकार इस ओर सचेष्ट हो, सजग हो । यही हमलोगों की इच्छा है, यही हमलोगों का आग्रह है ।

अध्यक्ष : मैंने तो आसन की तरफ से यही आपसे अनुरोध भी किया था कि हम सभी इस बात से अवगत हैं और हम सभी इस बात के प्रति चिन्ता रखते हैं, इसलिये हमने कहा कि आज समय पर उठाइयेगा या एक-दो दिन स्थिति देखकर, अगर इसपर कोई चर्चा की गुंजाइश आप सभी चाहेंगे तो आसन को कोई एतराज नहीं है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब मंत्री जी का सुन लीजिये न । भाई वीरेन्द्र जी, आपके अनुशंसा पर तो हमने महत्वपूर्ण शब्द को अति-महत्वपूर्ण कर दिया ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिन बातों की चर्चा विपक्ष के माननीय सदस्यगण कर रहे हैं, आदरणीय सदानन्द बाबू ने जो सुझाव दिया और आसन का भी निदेश है महोदय, तत्काल मैं चाहता यह हूँ कि माननीय सदस्य के संज्ञान में जो क्षेत्र से संबंधित बातें हैं, सरकार को लिखित तौर पर दे दें और उसके बाद आसन का जो निदेश है, उसका पालन किया जायेगा । तत्काल उनको राहत पहुँचाने की दिशा में सरकार कार्रवाई करेगी।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं सदानन्द बाबू की बात का समर्थन करता हूँ लेकिन अभी जो लोग डूब रहे हैं, मर रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष : उसको सरकार देखेगी । आपकी बातों का संज्ञान लेकर डूबने वालों को, मरने वालों का ख्याल रखने के बारे में सरकार विचार करेगी ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-16 : श्री अजीत शर्मा ।

श्री गुलाब यादव : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : क्या है गुलाब जी ?

श्री गुलाब यादव : महोदय, झंझारपुर में बाढ़ में लोग फँसे हुये हैं, कोई देखने वाला नहीं है...

अध्यक्ष : गुलाब जी, झंझारपुर कोई बिहार से बाहर है ? हमलोग तो पूरे बिहार की चर्चा कर रहे हैं ।

श्री गुलाब यादव : झंझारपुर विशेष रूप से प्रभावित है, वहाँ कि स्थिति बहुत खराब है ।

अध्यक्ष : सरकार झंझारपुर का मामला विशेष रूप से देखेगी ।

प्रश्नोत्तरकाल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 16 (श्री अजीत शर्मा)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत जब्त किये गये वाहन कानूनी प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से थाना परिसर में रखे गये हैं ।

2- अस्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि वाहन कानून में वर्णित विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत वाहन जब्त किये जाते हैं । सड़कों पर दुर्घटना घटित होने की स्थिति में दुर्घटनाकारी वाहन एम0वी0आई0 एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जॉच कराकर कांड में साक्ष्य प्राप्त करने हेतु थाना में विधिवत जब्त करके रखे जाते हैं । दुर्घटना के कांडों में जब्त किये गये वाहन एक महत्वपूर्ण प्रदर्श है । इसे विचारण के समय माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित किया जाना अनिवार्य है । कांड के अनुसंधान एवं साक्ष्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कार्य समाप्ति के पश्चात् माननीय न्यायालय के आदेश पर उचित पहचान स्थापित कर उसके असली स्वामी को वाहन सुपुर्द किया जाता है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं और सदन के सभी लोग जानते हैं कि थाना में 20-25 वर्षों से गाड़ियॉ रहकर सड़ जाती हैं, अगर सही समय पर सरकार सचेत रहे और वह नीलाम कर दे तो उस पैसे को भी विकास में लगाया जा सकता है ।

महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनके पास रिपोर्ट है कि पूरे बिहार में थानों में कब से इस तरह के मामले लम्बित हैं और इसके लिए आपने क्या प्रयास किया ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, जैसा मैंने बताया कि जो भी वाहन जब्त किये जाते हैं, थाने में रखे जाते हैं, वह न्यायालय का प्रोपर्टी होता है और वह एवीडेंस के रूप में बड़ा वैल्यूएबल होता है । जबतक न्यायालय में मामले डिसपोजल नहीं होंगे और एवीडेंस जो है, उसका आधार नहीं प्रस्तुत हो जायेगा तबतक अनुमति नहीं मिलती है । इसीलिये ऐसे ही वाहन रखे जाते हैं, नहीं तो जिस ऑनर का है, वे ले जाते हैं ।

श्री अजीत शर्मा : महोदय, 25-30 वर्षों से अगर न्यायालय कोई जजमेंट नहीं देता है तो जनता का जो पैसा बर्बाद हो रहा है, विकास में लगता, उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 4-5 दिन पहले अखबार में एक न्यूज आया था, आपने देखा होगा कि कानून मंत्री, भारत सरकार ने पार्लियामेंट में जवाब में कहा कि 2 करोड़

मुकदमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 20 वर्षों से लम्बित हैं । न्यायालय की अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें हमलोग क्या कर सकते हैं ?

श्री अजीत शर्मा : मंत्री महोदय यह बताना चाहेंगे कि कितने न्यायालय से अभी तक कितने वाहन रिलीज हुये हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ऐसा कुछ फिगर नहीं है ।

अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार जी ।

श्री अशोक कुमार (क्षेत्र सं0 208) : महोदय, सरकार ने माना कि वाहन रोड पर पड़ा है और न्यायालय के लिए उसको साक्ष्य के रूप में रखना है । सरकार क्या यह विचार रखती है कि हर जिले में या जहाँ गाड़ी रखी गई है, रोड पर सड़ रही है, उसको कहीं किनारे ले जाकर डम्प करें और जब सरकार को जरूरत हो, न्यायालय में प्रस्तुत करे । रोड पर जाम करके सड़ाना और पर्यावरण को गंदा करना, ट्रैफिक को जाम करना, इसपर सरकार जवाब दे । इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है, गाड़ियों को सरकार कहीं अलग डम्प करना चाहती है या नहीं ?

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो गाड़ियाँ पकड़ाती हैं, जबतक न्यायालय से कोई फैसला नहीं होता है तबतक वह गाड़ी नीलाम नहीं किया जा सकता है । बहुत अच्छा ! परंतु माननीय मंत्री जी से हम यह जानना चाहते हैं कि न्यायालय से जिनमें फैसला हो गया, उन गाड़ियों की नीलामी की क्या स्थिति है ? बिहार में अभी ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं जिनकी आप नीलामी नहीं करा रहे हैं ? बहुत स्पष्ट प्रश्न है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा प्रावधान के बारे में कि वह नीलामी हम नहीं करते हैं, जिस ऑनर का सीज किया गया है, अगर उसके केस का एक्वीटल हो गया, तो वाहन उनको दे दिया जायेगा । अगर नहीं हुआ है तो मामला चलता रहेगा । सरकार की वह प्रोपर्टी नहीं है कि उसको हमलोग नीलाम कर दें ।

टर्न-2/आजाद/15.7.2019

श्री अवधेश कुमार सिंह : माननीय अध्यक्षजी, हमने बहुत क्लीयर कहा है कि अभी जो न्यायालय से फैसला हो गया, दोषी हो गया, उसकी गाड़ियां थाने में सड़ रही है, माननीय विधायक ने कहा कि रोड पर सड़ रहा है, यह आप स्वयं भी माननीय अध्यक्ष महोदय देखते हैं...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपको कहा कि जिनका फैसला हो गया है, उनको वाहन रिलिज कर दिया जाता है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अवधेश बाबू, सुनिये । अगर इस तरह की सूचना माननीय सदस्य देंगे कि वह सड़क पर अवस्थित है तो उसपर अवलिम्ब कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : आप बैठिए न, अशोक जी ने जो कहा है, माननीय मंत्री जी दो चीज को देखवा लीजियेगा, एक तो सड़क पर डम्प करने से आवागमन बाधित नहीं हो और दूसरी क्या ऐसी संभावना है कि इस तरह की सारी गाड़ियों को जिले स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर एक जगह कर दिया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : यह महोदय विभिन्न थानों में जब्त होती है और उसी थाने के साथ उसका एटैचमेंट है, वही एवीडेन्स का काम करता है, वही से चार्जशीट होता है ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न सं0-445, माननीय सदस्य श्री महबूब आलम । चलिए, आप बैठ जाईए । माननीय सदस्य श्री महबूब आलम ।

तारांकित प्रश्न सं0- 'क'-445 (श्री महबूब आलम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1. वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला के बलरामपुर प्रखंड के रोशनगंज निवासी मो0 खुशदिल की हत्या के संबंध में बलरामपुर थाना कांड सं0-33/19 दिनांक 15.03.19 दर्ज है ।

2. कांड की प्राथमिक अभियुक्त 1. गरीब नवाज 2. मो0 जहुर आलम को हत्या में प्रयुक्त आग्नेयाशास्त्र के साथ गिरफ्तार करके 17.3.19 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है । कांड के तीसरे अभियुक्त संजीव कुमार मिश्रा के विरूद्ध अभियुक्तिकरण पर साक्ष्य इकट्ठा करने तथा संलिप्ता के बिन्दु पर ठोस साक्ष्य संकलन हेतु कांड अनुसंधान अन्तर्गत है ।

3. उपर्युक्त कंडिका-2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री महबूब आलम : महोदय, ये 33 नम्बर केस जो है बलरामपुर कांड संख्या तो सूचक ने महोदय 3 अभियुक्तों का नाम दिया है और उसका भाई जो मृतक है, मरने से पहले अपने भाई को कहा कि गरीब नवाज, जहुर और संजय मिश्रा ने मुझे मारा है और इसके बावजूद भी संजीव मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, यह मैं माननीय मंत्री जी से पूछता हूँ ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, लगता है कि माननीय सुनते नहीं है केवल प्रश्न करने में व्यस्त रहते हैं । मैंने कहा है कि तीन में से दो की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक का जो है कार्रवाई चल रही है, गिरफ्तारी में उपलब्ध नहीं है तो बाकी कार्रवाई होगी न्यायालय से अनुमति लेकर के ।

श्री महबूब आलम : महोदय, कितने दिनों के अन्दर कार्रवाई होगी ? समय सीमा निश्चित होनी चाहिए, अपराध का विषय है । महोदय, ये कार्यकर्त्ता की जो हत्या हुई है, जदयू के जिला उपाध्यक्ष थे महोदय...

अध्यक्ष : महबूब जी, आपने जो प्रश्न में बातें कही है कि उसका नाम हटा दिया गया है केस से, इसका क्या मतलब है, आई0ओ0 किसी का नाम हटाता, जोड़ता है । यह तो कोई सुपरविजन करेगा तब होगा ।

श्री महबूब आलम : महोदय, सुपरविजन में हटाता है ।

अध्यक्ष : सुपरविजन आई0ओ0 थोड़े करता है ?

श्री महबूब आलम : नहीं , सुपरविजन तो ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-450, श्री शाहनवाज । इसके लिए माननीय सदस्य श्री फराज फातमी प्राधिकृत है ।

तारांकित प्रश्न सं0-'ख'-450(श्री शाहनवाज)

अध्यक्ष : इसके लिए माननीय सदस्य श्री फराज फातमी प्राधिकृत है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि अरयिा जिलान्तर्गत जोकिहाट प्रखंड के सिसोला कब्रिस्तान की घेराबंदी का कार्य सांसद स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना अन्तर्गत स्वीकृत है । कार्य संवेदक को निविदा के उपरान्त आवंटित है ।

श्री फराज फातमी : अध्यक्ष महोदय, इस संवेदक को एक साल पहले ही काम मिल चुका है, टेंडर भी हो गया और संवेदक को काम भी मिल गया, उसके बावजूद भी काम शुरू नहीं हुआ, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या उस संवेदक पर कार्रवाई की जायेगी और कब तक उस कब्रिस्तान की घेराबंदी कर दी जायेगी ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इसको देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1138(श्री शाहनवाज)

अध्यक्ष : इसके लिए माननीय सदस्य श्री फराज फातमी प्राधिकृत है । उत्तर आया हुआ है, आपने देखा है ?

श्री फराज फातमी : नहीं देखा है सर ।

अध्यक्ष : उत्तर बता दीजिए माननीय मंत्री जी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड के प्रसादपुर पंचायत अन्तर्गत घोरमारा कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका, 2014 की कंडिका 6(34) में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है ।

माननीय विधायक, उन्हें प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा सकते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1139(श्री फराज फातमी)

अध्यक्ष : आपका भी उत्तर आ गया है, पढ़े हैं ?

श्री फराज फातमी : जी, नहीं सर ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अन्तर्गत खिरमा ग्राम पंचायत के रतौली कब्रिस्तान एवं ग्राम पंचायत बरिओल के बरिओल कब्रिस्तान की आंशिक घेराबंदी है । जिला स्तर पर संधारित अस्थायी प्रतिक्षा सूची में रतौली कब्रिस्तान एवं बरिओल कब्रिस्तान केवटी प्रखंड के क्रमशः 90 एवं 100 पर अंकित है ।

उक्त प्राथमिकता सूची के क्रमांक 54 तक कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है/प्रक्रियाधीन है ।

बाकी कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमवद्ध ढंग से घेराबंदी किये जाने की नीति है ।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका,2014 की कंडिका 6(34) में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी योजना को शामिल किया गया है । माननीय विधायक, उन्हें प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा सकते हैं ।

श्री फराज फातमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी एनाऊंस किया है कि जो भी कब्रिस्तान है, जितने भी बच गये हैं कब्रिस्तान बिहार के अन्दर सबकी घेराबंदी होगी । लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि दरभंगा जिला के अन्दर कई ऐसे कब्रिस्तान हैं, जिसका टेंडर हो गया और काम एलॉट हो गया

संवेदक को, लेकिन उसके बावजूद एक साल हो गया, डेढ़ साल हो गया, वे कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं टेंडर एलॉट होने के बाद भी और काम शुरू नहीं हुआ है तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमने जिन कब्रिस्तानों के बारे में विवरण किया है, कब तक इसको बनाने की कृपा करेंगे और सही मायने में जिन कब्रिस्तानों का पहले से टेंडर हो चुका है, उसको कब तक कमप्लीट कराने की जिम्मेवारी लेंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, हम इसको देखवा लेंगे लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जिसका टेंडर हो गया, उसका काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि फंड के एगेंस्ट में ही टेंडर होता है।

अध्यक्ष : आप अलग से सूचना दे दीजियेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि सैकड़ों ऐसे कब्रिस्तान हैं, जो दो-दो साल से टेंडर हो गया और दो साल पहले टेंडर हुआ और किसी कारणवश वह रद्द हो गया और आज तक उसका टेंडर नहीं हुआ । ऐसे जो कब्रिस्तान हैं, उसकी सूची बनाकर के माननीय मंत्री जी इसपर कब तक कार्रवाई करेंगे, इसके लिए जो दोषी पदाधिकारी होंगे, इसको चिन्हित करके कार्रवाई करना चाहते हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, लिखकर दे दें कि कौन ऐसे कब्रिस्तान हैं, हमारे पास सूची उपलब्ध नहीं है, हम उसको देखवा लेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय,महोदय, यह बहुत ही आपत्तिजनक बात है, सदन में बात आयी है....

अध्यक्ष : सदन में आप कह रहे हैं कि सैकड़ों ऐसे कब्रिस्तान हैं तो मंत्री जी आपसे सूचना मांग रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, एक कब्रिस्तान का ही लीजिए, शाहनवाज जी का पहला क्वेश्चन है, फातमी जी ने कहा कि .....

अध्यक्ष : वह क्वेश्चन खत्म हो गया ।

श्री ललित कुमार यादव : ठीक है महोदय, आप कब्रिस्तान पर ही है ।

अध्यक्ष : क्या है पहला क्वेश्चन ?

श्री ललित कुमार यादव : उन्होंने कहा है कि एक साल से टेंडर होकर के पुनः टेंडर नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष : क्या ?

श्री ललित कुमार यादव : ठीकेदार को कार्य आवंटित है और ठीकेदार कार्य नहीं कर रहा है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय,महोदय, जरा ये विद्वान बन रहे हैं, सुनिये सर ।

(व्यवधान)

मैंने कहा कि यह कब्रिस्तान जिनका माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, 90 और 100 पर अंकित है । इसका कोई टेंडर वगैरह नहीं हुआ है । माननीय सदस्य

ने कहा है कि कई एक कब्रिस्तान का टेंडर हो चुका है एक-एक साल, दो-दो साल पहले तो मैंने कहा है कि सूची दे दीजिए, हम उसको देखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : क्या है ?

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है,

(व्यवधान)

महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि जिला पदाधिकारी और एस0पी0 की एक कमिटी है, जो सेनसेटिव कब्रिस्तान है, उसकी सूची बनायी गयी है तो हम यह जानना चाहते हैं कि जो जिला में प्राथमिकता सूची बनी है, उसमें इस कब्रिस्तान का कितना नम्बर है और कितने प्राथमिकता सूची वाले कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो चुकी है और कितनी प्रक्रियाधीन है ?

टर्न-3/शंभु/15.07.19

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैंने कहा महोदय कि 90 और 100 पर अंकित है जो माननीय सदस्य का प्रश्न है । 90 और 100 और 54 तक हो चुका है ।

अध्यक्ष : वह तो मूल प्रश्न में ही था ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-1140(श्री आलोक कुमार मेहता)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि तात्कालिक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक सं0-515, दिनांक-08.11.04 द्वारा नोनिया, बिन्द, मलाह, कम्हार, लोहार, कर्मकार, बढ़ई, तुरहा, राजभर, चन्द्रवंशी, कहार, कर्मकार, कोंकड़ के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल करने की अनुशंसा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित की गयी थी । इसमें निषाद जाति शामिल नहीं थी ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-6711, दिनांक-05.09.15 के द्वारा मलाह, निषाद, बिन्द, बेलरा, चाई, टीयर, खुलवट, सुरैया, गोढ़ी, बनपर, केवट एवं नोनिया जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को प्रेषित की गयी ।

3- निषाद जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । अतएव निषाद जाति को अनुसूचित जाति एस0सी0 में शामिल करने की अनुशंसा केन्द्र सरकार को भेजा जाना औचित्यपूर्ण नहीं है । महोदय, पहले से ही भेजा जा चुका है, वहां लंबित है ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के पहले प्रश्न में अस्वीकारात्मक बताया । जबकि उसमें जिन जातियों को एस0सी0 में शामिल करने की अनुशंसा की

गयी थी । उसमें निषाद जाति की कुछ उप जातियां भी शामिल है । दूसरी बात एस0टी0 में शामिल करने की प्रक्रिया मतलब यह प्रक्रियाधीन है । महोदय, कई वर्षों से यह प्रक्रिया चल रही है । केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार को निदेश दिया था कि एथनोग्राफी रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाय । एथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार करने में कई वर्ष लग गये और उसके बाद एथनोग्राफी रिपोर्ट में यह बताया गया ए0एन0सिन्हा इन्सटीच्यूट द्वारा एथनोग्राफी रिपोर्ट तैयार किया गया उसमें यह बताया गया कि जो निषाद और निषाद समाज की जो उप जातियां हैं, बड़ी संख्या है बिहार के अंदर उनका रहन सहन एस0सी0 समाज के लोगों से ज्यादा मिलता है न कि एस0टी0 समाज के लोगों से । जहां उसने एथनोग्राफी रिपोर्ट से आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक मसले पर अध्ययन किया गया और उस अध्ययन में पाया गया कि एस0सी0 समाज से ज्यादा इसका जुड़ाव है और अस्पृश्यता भी जो छुआछूत, भेदभाव है, यह भी आंशिक रूप से उस जाति में है । ऐसी अवस्था में सरकार क्या पुनः इस बात पर विचार करने को तैयार है कि उसे एस0टी0 समाज में शामिल किया जाय और उसकी प्रक्रिया शुरू करे। एथनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूँ । महोदय, यह एथनोग्राफी रिपोर्ट सीधे केन्द्र सरकार को भेज दिया गया या नहीं भेज दिया गया, मैं नहीं जानता, लेकिन यह सरकार की जिम्मेवारी है कि यह समाज आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ है और उनके पास जमीन का रकबा- इसमें भूमिहीन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है ।

अध्यक्ष : हो गयी बात, आप प्रश्न पूछ चुके हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैंने क्या कहा अस्वीकारात्मक का क्या अर्थ है ? माननीय सदस्य का प्रश्न है उन्होंने कहा कि 2004 में ही अनुशंसा की गयी थी निषाद जाति के लिए तो मैंने कहा 2004 की जो अनुशंसा की गयी थी उसमें वह नहीं था । मैंने कहा कि 05.09.15 के द्वारा मलाह निषाद जाति की भी अनुशंसा की गयी, 05.09.15 के द्वारा और वह अभी लंबित है वहां और सारे रिपोर्ट जो उसकी प्रक्रिया है संपूर्ण की अनुशंसा की गयी है । अब प्रक्रियाधीन है, जब आ जायेगा तो देखा जायेगा ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, यह जो सरकार की अनुशंसा है वह एस0टी0 में शामिल करने के लिए है इसका आरक्षण प्रतिशत बिहार के अंदर मात्र 1 प्रतिशत है और इतने बड़े समाज को यदि आप शामिल कर रहे हैं तो उसके लिए स्पेस भी होना चाहिए । मांग यह थी समाज के तमाम उप जातियों सहित जो लोग थे उनकी मांग थी एसी0सी0 में शामिल किया जाय, यह अनुशंसा तो एस0टी0 के लिए की गयी थी ।

अध्यक्ष : वह आप पूछ लिये ।

श्री आलोक कुमार मेहता : । मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि एथनोग्राफी रिपोर्ट के आधार पर क्या सरकार उसे एस0सी0 में शामिल करने का विचार रखती है ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैंने कहा रिपोर्ट के आधार पर ही अनुशंसा की जाती है वही मापदंड है भारत सरकार का नहीं तो उसमें क्वेरी हो जाता है । अनुग्रह नारायण संस्थान द्वारा सारी रिपोर्ट तैयार किये गये उसके पारामीटर के आधार पर भेजा गया 2015 में अभी तक उसका आया नहीं है । यह तो पार्लियामेन्ट के क्वेश्चन का सवाल है ।

अध्यक्ष : अनुग्रह नारायण के यहां से भी एस0टी0 में शामिल करने की बात है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : हां वह आ गया ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, उसमें एस0सी0 में शामिल करने की बात.....

अध्यक्ष : ठीक है उसको देखवा लीजिएगा उस रिपोर्ट के आधार पर ।

श्री आलोक कुमार मेहता : उसमें उसके अध्ययन में यह बताया गया कि इनका कल्चर, इनके आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति एस0सी0 से मिलती जुलती है । महोदय, सरकार से इसपर विस्तृत जवाब की अपेक्षा है।

अध्यक्ष : क्या है ? इनका पूरक सुन लीजिए । हो गयी आपकी बात सुन लिये ।

श्री विद्यासागर सिंह निषाद : महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न की बात है । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2015 के सितम्बर में निषाद समाज और इसकी उप जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का जो आग्रह किया था केन्द्र सरकार से और पुनः निषाद समाज और नोनिया समाज के सभी उप जातियों को 2018 में भी रेकोमेन्ड किया केन्द्र सरकार से, लेकिन माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं इनकी पार्टी के ही सांसद अजय कुमार मंडल उर्फ बूलो मंडल ने लोक सभा में इस बिल का विरोध किया था ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : तारांकित प्रश्न सं0-1141, श्री राजकिशोर सिंह । राजकिशोर जी, आपने उत्तर पढ़ा है ? मैं फिर माननीय सदस्यों से कहता हूँ कि आप सदन में आने से पहले यदि आपका प्रश्न है तो एक बार साइट पर उत्तर देख लिया कीजिए, सदन का समय बचेगा ।

श्री भाई वीरेन्द्र : 10 बजे के बाद आता है ।

अध्यक्ष : 10 बजे के बाद आता है वह आप नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उसके पहले आता है तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1141(श्री राजकिशोर सिंह)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इस कब्रिस्तान की घेराबन्दी हो चुकी है ।

तारांकित प्रश्न सं0-1142(श्री शाहनवाज)

अध्यक्ष : श्री फराज फातमी अधिकृत हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत पलासी प्रखंड के मियांपुर कब्रिस्तान एवं बड़ा मियांपुर कब्रिस्तान घेराबन्दी हेतु जिला स्तर पर तैयार प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबन्दी के लिए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है । उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबन्दी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका-14 की कंडिका-6(34) में भी कब्रिस्तान की घेराबन्दी योजना को शामिल किया गया है । माननीय विधायक उसके प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तान की घेराबन्दी करा सकते हैं ।

टर्न-4/ज्योति/15-07-2019

श्री फराज फातमी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से, जानना चाहता हूँ कि और यहाँ जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, इससे अवगत हैं कि जो भी कब्रिस्तान सूची में शामिल नहीं है और कोई भी विधायक अगर अनुशंसा करते हैं और मैं ही करता हूँ और जो सूची में शामिल नहीं होता है तो उसको कह दिया जाता है कि जब सूची में शामिल होगा तब ही अनुशंसा कर सकते हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस नीति मे परिवर्तन करेंगे ताकि जो भी हम अनुशंसा करें उसको प्राथमिकता में ले लिया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य अनुशंसा करें, उसको करवा दिया जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-1143 (श्री अशोक कुमार सिंह)</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस अधीक्षक, कैमूर द्वारा नुआंव प्रखंड के सहायक थाना, नुआंव को पूर्ण थाना में उत्क्रमित करने हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को प्राप्त कराया गया था, इसमें वरीय पुलिस अधिकारी का मंतव्य नहीं था । उक्त पृच्छा के आलोक में पुलिस मुख्यालय द्वारा वरीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रमण्डलीय आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक को मंतव्य उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, कैमूर को निदेशित किया गया है । पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को जानकारी देना चाहता हूँ कि नुआंव प्रखंड उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ है । प्रखंड म्रें थाना मुख्यालय है

और पॉच कि.मी. की दूरी पर तीन पुल हैं, आने जाने का रास्ता है और उस रास्ते से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर इलाके के लोग शराब और मादक पदार्थों की तस्करी बिहार के रास्ते करते हैं इसलिए मंत्री जी से अनुरोध करुंगा कि इसकी जॉच कराके नुआंव को थाना का दर्जा देंगे ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वह थाना नहीं है, उप थाना है वहॉ से रिपोर्ट आयी थी लेकिन जो उसके प्रौपर चैनल है कि एस.पी., डी.एम., डी.आई.जी. आई.जी. वह मुख्यालय को प्राप्त होगा, वह प्रक्रियाधीन है, वह मांगा गया है, वहां से आयेगा तो कार्रवाई की जायेगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1144 (श्री ललित कुमार यादव)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा कार्यालय अवधि में पूर्व एवं बाद तथा रविवार अवकाश के दिन किए गए कार्यों के लिए कार्मिक प्रशासनिक सुधाार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित दर पर उन्हें मानदेय दिया जाता है । यह मानदेय केवल पदाधिकारयिों को नहीं दिया जाता अपितु इसका भुगतान कार्य करने वाले सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों यानी छुट्टी के दिनों मे जिन जिन लोगों से काम लिया जाता है सब को यह दिया जाता है ।

श्री ललित कुमारयादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा कि पदाधिकारी एवं कर्मचारी को तो मानदेय बी.पी.एस.सी. में देते हैं तो क्या बिहार विधान सचिवालय या सामान्य सचिवालय में यह मानदेय का भुगतान होता है कि नहीं ? महोदय, यह छोटा सा प्रश्न है....

अध्यक्ष : क्या ?

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, कि बी.पी.एस.सी. में जिसतरह से देते हैं पदाधिकारी एवं कर्मचारी को तो बिहार विधान सभा सचिवालय और सामान्य सचिववालय में यह लागू है कि नहीं ? यह हम जानना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : यह इस प्रश्न से नहीं उठता है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1145(श्री महेश्वर प्रसाद यादव)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है । गृह विभाग ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : उत्तर नहीं आता है तो आपको दिक्कत कहॉ होती है, उसको पढ़वा देते हैं ,जब देखकर आईये तो नहीं कहिये कि हम देख कर नहीं आए हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान घेराबंदी हेतु प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रुप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, उसी क्रमबद्ध ढंग्र से घेराबंदी कराये जाने की नीति है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के संशोधित मार्गदर्शिका 14 की कंडिका 6(34) में भी कब्रिस्तान की घेराबंदी की योजना को शामिल किया गया है । माननीय विधाायक उनसे प्राप्त निधि से भी प्राथमिकता सूची में शामिल कब्रिस्तान की घेराबंदी करा सकते हैं ।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, सेंसेटिव जगह है इसको घेरवा दें विधायक निधि से होने वाला नहीं है ।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको देखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1146 (श्री विधासागर केशरी)

अध्यक्ष : आपका भी उत्तर आया हुआ है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1- वस्तुस्थिति यह है कि अररिया जिलान्तर्गत फारबिशगंज प्रखंड मिर्जापुर के वार्ड सं. 7 में श्मशान घाट की जमीन से संबंधित अतिक्रमण का मामला प्रकाश में नहीं आया है, उक्त श्मशान घाट की चहारदिवारी एंव छतदार चबूतरा नहीं है। गृहविभाग द्वारा श्मशान घाट की चहारदिवारी एवं छतदार चबूतरा के निर्माण कराये जाने का प्रावधान नहीं है ।

श्री विद्यासागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, यह जो श्मशान घाट है उसके ठीक बगल में पड़ता है वहॉ पर मस्जिद और उसके अगल बगल में काफी क्षेत्र में अतिक्रमण चारों ओर से हो रहा है इसलिए विवाद नहीं हो इसलिए कम से कम चहारदिवारी तो घेरवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो बतला दिया ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : मैंने तो बतला दिया कि गृह विभाग से संबंधित नहीं है नगर विकास विभाग से है ।

तारांकत प्रश्न संख्या - 1147 (श्रीमती सुनीता सिंह चौहान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत दोनों कब्रिस्तान की घेराबंदी हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है जो निविदा की प्रक्रिया में है । अभी तुरत किया गया है ।

श्रीमती सुनीता सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं । कबतक राशि का आंवटन हो जायेगा समय सीमा निर्धारित कर दें ।

अध्यक्ष : अब तो कह रहे हैं कि टेण्डर हो रहा है तब तो हो ही जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1148(श्री लाल बाबू राम)

श्री श्याम रजक, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत सकरा प्रखंड के कृषकों द्वारा गत वर्ष विभाग द्वारा चलायी जाने वाली मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना अंतर्गत चयनित प्रभेद के उन्नत प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने हेतु आवेदन नहीं दिया गया है । मुख्यमंत्री गन्ना विकोस योजना अंतर्गत गन्ना के चयनित प्रभेद के प्रमाणित बीज के क्रय हेतु पहले आओ पहले पावो के तर्ज पर सहायक निदेशक, ईख विकास मुजफ्फरपुर कार्यालय में इच्छुक किसानों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन समर्पित कर उन्नत किस्म का बीज प्राप्त किया जा सकता है ।

श्री लाल बाबू राम : अध्यक्ष महोदय, सकरा में जो प्रखंड बीज उपलब्ध कराने वाले पदाधिकारी होते हैं वहॉ पर पदस्थापित नहीं हैं अब भी बीज मुहैय्या सरकार द्वारा किसानों के लिए कराया जाता है तो उसको मालूम नहीं हो पाता है कि कब बीज आया है, हमको कब एप्लाई करना है तो माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि इसके लिए पदाधिकारी नियुक्त कर इसका प्रचार प्रसार कर किसानों को बीज उपलब्ध कराने चाहते हैं और कबतक ?

श्री श्याम रजक, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा समय समय पर समाचारपत्रों के माध्यम से विज्ञापन दिए जाते हैं जैसा माननीय सदस्य का कहना है उसपर देख लेने का काम करेंगे लेकिन विज्ञापन दिए जाते हैं और उसके माध्यम से लोगों को जानकारी होती है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1149 (श्री मेवा लाल चौधरी)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद , मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । राज्य सरकार द्वारा अलपसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से प्रत्येक जिला मुख्यालय में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया जाता है । वर्तमान नीति के अनुसार राज्य योजनान्तर्गत प्रखंड स्तर पर छात्रावास निर्माण का प्रावधान नहीं है ।

श्री मेवा लाल चौधरी : महोदय, तारापुर प्रखंड एक ऐसा एरिया है जहॉ पर मुस्लिम डौमिनेटिंग एरिया है अल्पसंख्यक डौमिनेटिंग एरिया है अभी हाल में मुंगेर हेडक्वकार्टर में हुआ होगा, यह बहुत ही वलनरेबुल जगह है, हम मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन करेंगे कि अगर इसपर विचार रखें, तो उनकी बड़ी कृपा होगी ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1150 (डा0 रामानुज प्रसाद)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 1: स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सारन जिलान्तर्गत दियर इलाके के अकिलपुर थाने में एक मिक्सड टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन

प्रतिनियुक्त है जिससे अगलगी की घटना होने पर अग्निशामक का कार्य किया जाता है । दियर इलाके में अग्निशामक का कार्य दानापुर अग्निशामकालय सोनपुर अग्निशामकालय तथा साथ साथ नया गांव थाना में प्रतिनियुक्त मिक्सड टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन की सहायता से भी किया जाता है । दानापुर अग्निशामकालय से दियर इलाके की दूरी लगभग 12 कि.मी. एवं जाने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है दियर इलाके से सोनपुर अग्निशामकालय की दूरी लगभग 13 कि.मी. इसे जाने में लगभग 35 मिनट का समय लगता है, दियर क्षेत्र में अग्निशामक की त्वरित कार्रवाई कर अगलगी की घटना को नियंत्रित किया जाता है ।

3- उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट की गयी है । वस्तुस्थिति यह है कि दियर इलाके के अकिलपुर थाना में मिक्सड टेक्नोलॉजी अग्निशामक वाहन प्रतिनियुक्त है जिससे अग्निशामक का कार्य कियाकजाता है वर्तमान में प्रखंड स्तर पर अग्निशामक केन्द्र स्थापित करने की नीति नहीं है ।

टर्न : 05/कृष्ण/15.07.2019

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी को पदाधिकारियों ने जो जवाब बनाकर दिया है, मंत्री जी उसी को पढ़े हैं । महोदय, मैं इस जवाब को न सिर्फ चैलेंज कर रहा हूं बल्कि जिन पदाधिकारियों ने यह जवाब बनाकर दिया है कि 12 मिनट लगता है, 33 मिनट लगता है, मैं उन पदाधिकारियों को वहां भेजना चाहता हूं कि वे वहां पर जाकर देख आवें कि हम 12 मिनट में दानापुर से वहां पहुंच रहे हैं, 33 मिनट में सोनपुर से हम वहां पहुंच रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, मैं इस साल की घटना बता रहा हूं कि दुधिया, रामदासचक, नौदिअरी, तिरपुर, पकौलिया, बरियारचक, रमसापुर, गरीपट्टी, छितरचक, बतरौली, तिवारी टोला इतने जगहों पर आग लगी, हमलोग पूरा तबाह रहे तो जो कह रहे हैं कि मिक्स्ड टेक्नोलॉजी के अग्निशामक गाड़ी वहां डिप्लॉयड है तो मैं दावा करता हूं, मंत्री जी का जवाब ही पूरा गलत है, वह पढ़ रहे है, जिसको पदाधिकारियों ने बनाकर दिया है ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न कीजिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : मेरा पूरक प्रश्न यह है कि सरकार को उसमें क्या है उतने बड़े इलाके में अगर कह रहे हैं कि सोनपुर में, नयागांव में, दिघवारा में दानापुर में है तो अकिलपुर थाना है और पटना जिला का पार्ट है नकटा, नौदिअरी, इसके अलावे सारण जिला का भी पार्ट है, वहां अग्निशामक गाड़ी का डिप्लॉयमेंट केन्द बनाने में सरकार को क्या हर्ज हो रहा है कि इतना बड़ा इलाका जो धू-धू कर जल जाता है, लोग बेघर हो जाते हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक प्रश्न पूछिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप इसकी जांच करायेंगे जिस पदाधिकारी ने जवाब बनाकर भेजा ? दूसरा, यह है कि सरकार अगर सोनपुर में कह रही है तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं पूरे सम्मान के साथ कि जिन इलाकों की मैंने चर्चा की है, सोनपुर से माननीय मंत्री जी 33 मिनट में चल कर दिखावें । चारो ओर से गंगा नदी से घिरे हुये इलाके हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछते-पूछते कहां-कहां चले जाते हैं ? हम कहते हैं कि पूरक पूछिये।

डा0 रामानुज प्रसाद : मेरा यही पूरक प्रश्न है कि जो जवाब इस प्रश्न का आया है, क्या माननीय मंत्री जी जांच करायेंगे ? दूसरा पूरक प्रश्न यह कि सरकार जवाब दे रही है कि वहां पर है तो इसकी भी जांच हो जाये कि वहां मिक्स्ड टेकनोलॉजी के अग्निशामक गाड़ी लगी हैं या नहीं तथा क्या वह कंडीशन में है ?

फायर स्टेशन बनाने की मेरी तो मांग है ही । मेरे प्रश्न में ही सन्निहित है कि उक्त दियर इलाके में अगलगी पर काबू पाने के लिये अकिलपुर में फायर स्टेशन की स्थापना करें । यही तो मैं मांग रहा हूं कि माननीय मंत्री जी को और सरकार को क्या एतराज है ?

अध्यक्ष : रामानुज जी, आप जहां से शुरू किये थे और जहां तक आये हैं, इस बीच की तारतम्यता खत्म हो गयी है । जब आप प्वाइंटेड सप्लीमेंटरी नहीं पूछियेगा तो कोई क्या जवाब देगा ?

डा0 रामानुज प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसकी मैं जांच चाहता हूं कि 33 मिनट और 12 मिनट में वहां पहुंच रहे है ।

अध्यक्ष : आप 5 मिनट से सप्लीमेंटरी पूछ रहे थे और कोई सवाल निकला नहीं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, समस्या के निदान की मांग नहीं कर रहे हैं । हम ही को कह रहे हैं कि ऑफिसर ने गलत सूचना दी है । मतलब हमीं मूर्ख है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि पदाधिकारी ने गलत सूचना दी है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मेरी बात सुन लीजिये । जो ऑफिसर जवाब बनाकर दे देता है और वही हमलोग पढ़ देते हैं, यह उनकी मान्यता है । यही वह आरोप लगा रहे हैं ।

महोदय, मैंने क्या कहा ? केवल अभी थाना स्तर पर ही अग्निशामक रखने का प्रावधान है और यह कह रहे हैं कि 3-4 पंचायत के विभिन्न इलाके हैं । उसको करने के लिये अभी यह नीतिगत निर्णय नहीं है । यही मैंने कहा है।

अध्यक्ष : आप अंतिम पूरक प्रश्न पूछिये ।

डा0 रामानुज प्रसाद : मेरा अंतिम पूरक प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में यह भी शामिल किया है कि अकिलपुर में मिक्स्ड टेक्नोलॉजी के अग्निशामक गाड़ी है। महोदय, मैं कहता कि वहां मिक्स्ड टेक्नोलॉजी के अग्निशाामक गाड़ी नहीं है । तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने यह कहां कहा है ?

डा0 रामानुज प्रसाद : अकिलपुर थाना है, मैं चाहता हूं कि उस थाना पर अग्निशामक केन्द्र खुले, इन इलाके के गरीबों की जान-माल की हिफाजत के लिये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इनका कहना है कि अकिलपुर थाना में मिक्स्ड टेक्नोलॉजी की अग्निशामक गाड़ी नहीं है । आप इसको दिखवा लीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : जी । ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1151 (श्रीमती पूनम देवी यादव)

श्री श्याम रजक,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1. स्वीकारात्मक है ।

सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजेस्टिक एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा0लि0 को बियाडा के कार्यालय के पत्रांक 561 दिनांक 02.04.20111 द्वारा औद्योगिक विकास केन्द्र में 98.30 एकड़ भूमि का आवंटन Maize Cluster, Agriculture hub & Strach Production के उद्योग स्थापना हेतु किया गया। पुनः सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजेस्टिक एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा0लि0 से प्राप्त अनुरोध के संदर्भ में निदेशक पर्षद की 43वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में पूर्व में निर्गत आवंटन पत्र 561 दिनांक 02.04.2011 में संशोधन करते हुये बियाडा के कार्यालय के ज्ञापांक 6117/डी0 दिनांक 27.08.2013 द्वारा सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजेस्टिक एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा0लि0 को आवंटित 98.30 एकड़ भूमि को दो भागों में विखंडित करते हुए दो अलग इकाई क्रमशः 70.00 एकड़ भूमि पर सर्वश्री प्रस्टीन मेगा फूड पार्क प्रा0लि0 का उत्पादन Mair Cluster under Special Prupose Vehicle (SPV) एवं 28.30 एकड़ भूमि पर सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजेस्टिक एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा0लि0 को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी ।

2. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार से इस विषय में विभाग को कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

3. इकाई को भूमि आवंटन के 8 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात् भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारणवश सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजेस्टिक एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा0लि0

को आवंटित रकबा 28.30 एकड़ भूमि का आवंटन बियाडा के कार्यालय के ज्ञापांक 290 दिनांक 07.03.2019 द्वारा रद्द किया जा चुका है ।

सर्वश्री प्रिस्टाईन मेगा फूड पार्क प्रा0लि0 द्वारा शेष आवंटित 70.00एकड़ भूमि में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,भारत सरकार की योजनान्तर्गत मेगा फुड पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें से लगभग 7.00 एकड़ भूमि पर कोल्ड स्टोरेज आदि असैनिक निर्माण कार्य किया गया है । 10 हजार मे0टन क्षमता के दो वेयर हाउस कुल 20 हजार मे0टन क्षमता के स्थापित हो चुके हैं तथा कार्यरत हैं । इसके अतिरिक्त 10 हजार मे0टन क्षमता का एक ड्राई वेयर हाउस निर्माणाधीन है । साथ ही 10 हजार क्षमता का मल्टि कॉमोडिटी कोल्ड स्टोर स्थापित हो चुका है तथा कार्यरत है । 2 मे0टन प्रति घंटा क्षमता का इन्टिग्रेटेड कैनिंग लाईन स्थापित एवं कार्यरत है । 10 हजार मे0टन क्षमता का ग्रेन सिलोज एवं 1500 मे0टन क्षमता का डीप फ्रीज स्टोर निर्माणाधीन है ।

बाउंड्रीवाल, गेट, इन्टरनल रोड एवं ड्रेनेज का कार्य पूरा हो चुका है । वे-ब्रिज स्थापित एवं कार्यरत है । पावर ट्रान्समिशन, डिस्ट्रीव्यूशन एवं स्ट्रीट लाईटिंग का कार्य पूरा हो चुका है । एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग सह फैसिलिटी सेंटर, स्टाफ क्वार्टर्स तथा MSME शेड्स का कार्य पूरा हो चुका है । अन्य आवश्यक कार्य निर्माणाधीन/प्रक्रियाधीन है ।

महोदय, वर्तमान में समेकित रूप से बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति,2016 दिनांक 01.09.2016 से लागू है, जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के उद्योगों को प्राथमिकता/उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है, उसके लिये विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है ।

महोदय, सरकार स्वयं उद्योग नहीं लगाती है अपितु उद्योगों की स्थापना एवं विकास को प्रोत्साहित करती है । अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति,2016 के तहत सभी सुविधाएं दी जाएगी ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने, सरकार ने स्वीकार किया कि वहां जो प्रिस्टाईन कंपनी है और जो फुड मेगा पार्क है, पूरे जिला का मक्का के उत्पादन में एशिया महादेश में प्रथम स्थान है और जो कंपनी फुड मेगा पार्क स्थापित की गयी है, 98.कुछ एकड़ भूमि का अधिग्रहण बियाड के द्वारा किया गया था, जो मक्का आधारित उद्योग लगाने के लिये सरकार ने सर्वश्री प्रिस्टाईन लॉजेस्टिक्स एण्ड इन्फ्राप्रोजेक्ट प्र0लि0 को दिया था तो मेरा मानना है कि मक्का आधारित जो व्यवसाय कर रहा है और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया तो हम जानना चाहते हैं कि दिनांक 30.11.2018 को खाद्य उपभोक्ता मंत्री जी आयीं थीं और माननीय मंत्री बता रहे हैं कि

मेगा फुड पार्क में सारा चीज, सारा यंत्र लग रहे हैं लेकिन पूरा यंत्र नहीं लगा, आधा-अधूरा लगा है और दिनांक 30.11.2018 को बगैर उद्घाटन के माननीय मंत्री लौट गयीं।

अध्यक्ष : यह सब तो हो चुका है । आप पूरक प्रश्न पूछिये न ।

टर्न-6/अंजनी/15.07.19

श्रीमती पूनम देवी यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारा यह मानना है कि जो हमारे उद्योग के लिए जमीन दिया गया था, जब मेगा फूड पार्क नहीं बनना था, मक्का के उद्योग पर आधारित बनना था तो क्या माननीय मंत्री जी उस जमीन को रद्द करके मक्का पर आधारित उद्योग बनाना चाहते हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी तो बता दिये कि रद्द कर दिये हैं, तब उससे आगे न पूछिए ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : महोदय, आगे मेरा यह कहना है कि जो वहां सब कुछ बन रहा है फुड मेगा पार्क का तो उसका क्या, वे 70 एकड़ के बारे में बता रहे हैं कि....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, हम जो समझे हैं और आप जो जानना चाहती हैं, प्रिस्टाईन वाले का तो रद्द कर दिया गया, अब मक्का आधारित उद्योग लगाने की क्या प्रक्रिया चल रही है, यही न आप पूछना चाहती हैं ?

श्री श्याम रजक, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि सरकार उद्योग नहीं लगाती है, हम माहौल बनाते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के माध्यम से उनको कई तरह की सुविधा अनुदान दिये जाते हैं । हम उद्योग नहीं लगाते हैं । 70 एकड़ पर तो काम चालू है, 28 एकड़ जिसको रद्द कर दिया बियाडा ने, उसपर अगर कोई आयेगा तो विचार किया जायेगा ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और पूरक है । हम जानना चाहते हैं 28 एकड़ के बारे में, 70 एकड़ तो जमीन फूड मेगा पार्क को दे दिये, 28 एकड़ में मक्का आधारित उद्योग तो लगेगा नहीं, हम चाहते हैं जो प्रिस्टाईन कम्पनी बना रही है, जो बनाया भी नहीं और आधा-अधूरा में माननीय मंत्री जी को उद्घाटन के लिए बुलाया गया था.....

अध्यक्ष : उसका तो रद्द हो गया । उसको तो इन्होंने कैन्सिल कर दिया । माननीय मंत्री जी ने कहा कि रद्द करके 28 एकड़ जमीन बची हुई है, उसपर कोई उद्यमी प्रस्ताव लेकर आयेंगे तो सरकार उसको देखेगी । उन्होंने तो कहा है ।

श्रीमती पूनम देवी यादव : मंत्री जी, भविष्य में क्या ये प्रस्ताव लाना चाहेंगे ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो कहा कि इसमें उद्यमी प्रस्ताव देते हैं, सरकार प्रस्ताव नहीं देती है।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मक्का उद्योग आधारित के लिए बियाडा ने जमीन आवंटित किया था, उसपर दूसरे चीजों का उपयोग किया गया तो माननीय सदस्या का कहना है कि क्या इन चीजों को हटाकर पुनः मक्का आधारित.....

अध्यक्ष : वही तो कह दिये ।

तारांकित प्रश्न सं0-1152(श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्या का प्रश्न बहुत ही समिचिन है । अभी फिलहाल पांच सैप बल की प्रतिनियुक्ति जिला स्तर से की गयी है और फिलहाल पुलिस मुख्यालय को निर्देश दिया गया है कि जितने पर्यटक स्थल हैं, उसकी भायब्लिटी रिपोर्ट और उसकी नेसेसिटी को देखते हुए एक व्यापक पॉलिसी बनावे, वहां पर थाना खोलने के लिए कार्रवाई करें ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, मंदार महोत्सव के समय में इतनी सारे पर्यटक आते है, पहले मेरी बात सुन ली जाय ।

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आपकी बात को स्वीकार करके नीतिगत निर्णय के लिए कह दिये गये ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी की तो बात पहले आप सुन लीजिए ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : मान लिये हैं, मैं अपनी बात इसलिए रखना चाह रही हूँ कि आये दिन भी वहां लोग जाते हैं पर्यटन स्थल के रूप में तो मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूँ कि आदेश तो दिये हैं लेकिन कबतक करायेंगे ?

अध्यक्ष : अभी तो यह नीतिगत बात है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि पांच सैप बलों को फिलहाल अभी स्थापित कर दिया गया है, जिसका जिक्र वे कर रही हैं । परमानेंट थाना बनाने के लिए निर्देश दिये गये हैं । मैंने कल ही कहा है कि एक व्यापक ग्रोथ बेस्ड पॉलिसी बनाकर ले आइए ।

तारांकित प्रश्न सं0-1153(श्री विनोद प्रसाद यादव)

श्री विनोद प्रसाद यादव : सर, उत्तर मिला हुआ है ।

अध्यक्ष : बोलिए, बहुत धन्यवाद आपको ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : पूरक मेरा यह है कि सरकार ने यह माना है कि कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिस्ट क्रमांक-8 और 22 पर निर्धारित है । महोदय, इसमें कई कब्रिस्तान ऐसे हैं, जिस समय प्राथमिकता सूची बनायी गयी थी, वहां के संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर बनाया गया था लेकिन बाद में संवेदनशीलता बदलती रहती है समय-समय पर तो क्या सरकार प्रत्येक वर्ष एस0पी0, डी0एम0 की जो कमिटी है, उसको प्रत्येक वर्ष रेसनालाइज कराने का विचार रखती है और दूसरा चूंकि जब रेसनालाइज जब ये कराना चाहते हैं तो उस बैठक में क्षेत्र के विधायक को भी वहां सम्मिलित करने का विचार रखते हैं ताकि उसका सही रेसनालाइजेशन हो सके ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह नीति बहुत पहले बनायी गयी थी, उस समय होता यह था कि कब्रिस्तान को लेकर राइट हो जाया करता था तो प्राथमिकता सूची का आधार यही था कि जहां डिसपुट होता है हिन्दु-मुसलमान का, उसको प्राथमिकता सूची में डाली जाय, इसलिए डी0एम0 और एस0पी की अध्यक्षता में कमिटी बनी हुई है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें व्यापक तौर पर कहा कि फिलहाल विधायक लोगों की मांग ठीक है कि हम भी अपनी योजना से कराना चाहते हैं तो उसको भी एमेंड किया गया लेकिन माननीय सदस्य कह रहे हैं डी0एम, एस0पी0 की बैठक में वे किये जाते हैं और 20 सूत्री की बैठक में आप प्रश्न कर सकते हैं, उसमें कहां कोई दिक्कत है ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : एक 22 नम्बर पर अंकित है कब्रिस्तान, अभी माननीय मंत्री महोदय ने माना है कि 7 नम्बर क्रमांक तक डोभी प्रखंड में कार्यान्वित कराया गया है लेकिन जो 22 नम्बर क्रमांक पर अंकित है, वह काफी संवेदनशील है तो उसका तो नम्बर संवेदनशीलता के आधार पर काफी दिन में आयेगा और दूसरा, उसको जो अभी प्रत्येक साल अगर संवेदनशीलता के बारे में समीक्षा करेंगे तो हो सकता है कि उसको 8वें, 9वें स्थान में मिले और उसमें राशि की क्या व्यवस्था है ताकि उसको जल्द-से-जल्द घेरवाया जाय ।

अध्यक्ष : विनोद जी, तब तो प्रत्येक साल सूची भी बदल जायेगी, प्राथमिकता भी बदल जायेगी ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अभी एस0पी0, डी0एम0 को कहीं भी झगड़े-झंझट होते हैं इस संबंध में, उसकी पूरी जानकारी होती है कि इस संबंध में कब्रिस्तान से संबंधित, इनक्रोचमेंट से संबेंधित या अन्य बातों से संबंधित कहां विवाद पैदा हुआ है तो उसके आधार पर उसका प्राथमिकता क्रमांक चेंज करना चाहिए ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य के भावना के अनुरूप भी विधायक फंड में उसको इनकुलुड किया गया है । यह हमारी और आपकी भी जवाबदेही है कि हमारे क्षेत्र में हिन्दू-मुसलमान के झगड़े न हों, उसको करवाइए ।

श्री विनोद प्रसाद यादव : उससे पूरा बनना संभव नहीं है ।

मो0 नवाज आलम : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि पूरे सदन के माननीय सदस्य भी इसपर चिंतित हैं ।

अध्यक्ष : आप अपनी बात न कहिए ।

मो0 नवाज आलम : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो कब्रिस्तान सूचीबद्ध है, अगर सूचीबद्ध नहीं रहने के बावजूद विधायक अपने कहीं कब्रिस्तान की घेराबंदी अपनी निधि से कराना चाहते हैं तो क्या वे अपने निधि से करा सकते हैं ? यह बात हम जानना चाहते हैं ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : निश्चित रूप से करा सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा कि करा सकते हैं । मंत्री जी ...

(व्यवधान)

आप लोग बैठिए न । क्या कहे माननीय मंत्री जी...

अच्छा, वह सब सूची मंत्री जी को दे दीजियेगा । यह पूरे सदन का मामला है, बैठिए न ।

तारांकित प्रश्न सं0-1154(श्री शम्भू नाथ यादव)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-1155(श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री श्याम रजक, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- स्वीकारात्मक है ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-52 दिनांक 14.03.2018 के प्रावधान के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग के अनुरोध पर पंडौल को-ऑपरेटव स्पिनिंग मिल्स लि0, मधुबनी को 7.5 एकड़ भूमि इंजिनियरिंग कॉलेज खोलने हेतु विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग को नियमानुसार भूमि आवंटित करने हेतु विभाग द्वारा बिहार औद्योगक क्षेत्र विकास प्राधिकार से अनुरोध किया गया है।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि पंडौल सहकारी सूत मिल के पूर्व से विभाग में प्रतिनियुक्ति पात्र कर्मियों का समयोजन विभाग द्वारा किया जा चुका है । शेष पात्र कर्मियों का नियमानुसार समायोजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो बचे हुए हैं, उनका कबतक कर देंगे? माननीय मंत्री जी ने माना है कि आठ का पहले कर चुके हैं अब जो बचे हुए हैं 10-12 लोग हैं, जमीन जब बियाडा ले चुकी है और इंजीनियरिंग कॉलेज को दे दिया है, केवल हम माननीय मंत्री जी से चाहते हैं कि महीना-दो महीना के अन्दर कर दें । यही मेरा आग्रह है । माननीय मंत्री बतायें कि कबतक ?

अध्यक्ष : ठीक है । प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों तो उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायें ।

टर्न–7/राजेश/15.7.19

कार्य–स्थगन

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15 जुलाई, 2019 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैंः सर्वश्री समीर कुमार महासेठ, श्री मो0 नेमतुल्लाह, श्री मो0 नवाज आलम, श्री राजेन्द्र कुमार एवं श्री यदुवंश कुमार यादव ।

दूसरा श्री ललित कुमार यादव, श्री सत्यदेव राम एवं श्री राजेन्द्र कुमार ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2019–20 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद तथा मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–172 (3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण इन दोनों कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, हमलोगों ने क्या कार्य स्थगन दिया है, उसको तो सुन लीजिये । इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है .....(व्यवधान)

अध्यक्षः हमने आपका कार्य स्थगन देखा है और उसपर प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही बातें हो चुकी हैं।

श्री ललित कुमार यादवः महोदय, यह सरकार कुंभकरण की निद्रा में सोयी हुई है, बाढ़ से सैकड़ों लोग मर चुके हैं, एक छटांक भी सूखा राहत गॉवों में नहीं पहुंचा है, यहॉ तक कि मवेशी के लिए चारा भी उपलब्ध नहीं कराया गया है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और यह सरकार कुंभकरण की निद्रा में सोयी हुई है, इसलिए हमलोग सरकार को कहना चाहते हैं कि इतने लोग महोदय, हलॉकि अब तो 24 घंटे से उपर हो गये, कितने लोग बाढ़ में मर गये हैं लेकिन अभी एक छटाक चूड़ा, गुड़ भी नहीं पहुंचाया गया है, बिहार में बाढ़ से भयावह स्थिति है .....(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः महोदय, बाढ़ से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उससे सरकार भी अवगत है और हमलोग भी अवगत हैं, तो कम से कम सरकार यह उठकर कह दें .....

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्रीः हुजूर, इनको नेता ये लोग नहीं मानते हैं, ये खड़े होते हैं और अगर अच्छी बात कहते हैं, तो इनलोगों को अच्छा नहीं लगता है ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, सरकार अगर संवेदनशील होती, तो कम से कम उठकर यह कहती कि बाढ़ की यह स्थिति है राज्य में और बाढ़ की स्थिति से निबटने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या करने जा रही है एवं क्या की है, उससे सदन को अवगत कराने का आश्वासन देती ।

(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, मेरी बात को सुन लिया जाय । कल ही मुख्यमंत्री जी ने डेढ़ घंटा सभी विभागों की बैठक बुलाकर समीक्षा किया है और महोदय उन्होंने हवाई सर्वेक्षण करने का भी काम किया, आज भी 10.30 बजे महोदय, पूर्णिया प्रमंडल के इलाके में सर्वेक्षण में गये हुए हैं, संभवत: डेढ़ बजे तक वे लौट आयेंगे, सदन में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आयेंगे, वे विस्तृत रुप से जानकारी देंगे सिद्दिकी साहब के प्रस्ताव पर, इसलिए इनलोगों को ज्यादा परेशान होने की जरुरत नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय सिद्दिकी साहब, अभी जब सदन प्रारंभ हुआ था, प्रश्नकाल के समय आप नहीं थे, उस समय ललित जी से लेकर तमाम माननीय सदस्यों ने, सदानंद बाबू ने भी इस प्रश्न को उठाया था, हमने भी आसन से, इस विषय की गंभीरता को संज्ञान लेते हुए बताया था कि यह सदन के लिए चिंता की बात है और समय पर उठायें, हालॉकि हमने यह भी सुझाव दिया था, जिसपर सदानंद बाबू ने कहा था, यह इतना गंभीर मुद्दा है, लोग प्रभावित हैं, उनकी परेशानियॉ हैं, दुशवारियॉ हैं, अगर सदन चाहे और सभी सदन के माननीय सदस्य चाहें, तो इसपर विमर्श करने के और भी तरीके हैं । अच्छे से, विस्तृत रुप से, इसपर बहस हो सकती है, हमने आपको विकल्प भी बताया है । इसलिए अभी तो तत्काल आपने शून्यकाल, कार्यस्थगन के समय का उपयोग करके इसे उठा दिया लेकिन सार्थक बहस तो नियमानुकूल उसपर विस्तृत का जो तरीका है, उसी से करने से होगा । माननीय मंत्री संसदीय कार्य ने भी उस समय उठकर कहा था कि इस तरह के प्रस्ताव पर, कोई नियम से चर्चा होती है, तो सरकार को कोई एतराज नहीं है । यह माननीय मंत्री, संसदीय कार्य ने कहा था ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, सरकार जब सुखाड़ की समीक्षा कर रही थी, बाढ़ आ गया, सरकार को इसका अंदाजा नहीं था । महोदय, मैं अनुरोध करुंगा कि जो बाढ़ की स्थिति है और माननीय सदस्यों के क्षेत्र में बाढ़ है और माननीय सदस्य सदन में है, तो हम तो चाहेंगे कि दो दिन सदन को कम से कम स्थगित कर दीजिये और हमलोगों को अपने-अपने क्षेत्र में जाने दीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है । अब शून्यकाल होने दीजिये । आप ही लोगों का है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आ गये)

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सरकार तो हर तरह से तैयार है महोदय, हमने तो विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह किया है कि बाढ़ के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई है, अगर उस संबंध में कोई सुझाव हो, तो आप सरकार को दीजिये, सरकार तुरत कार्रवाई करेगी लेकिन इनलोगों को बाढ़ से प्रभावित लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको राहत पहुंचाने का संबंध नहीं है, इनको तो पोलिटिकल माईलेज लेना है, ये इसपर राजनीति करना चाहते हैं, ये लोग तो हर विषय पर राजनीति करना चाहते हैं और तुरत -तुरत वेल में चले आते हैं, वेल में क्यों आते हैं, जब आपकी बात सुनी जा रही है, जब आपको अध्यक्ष महोदय जी के तरफ से नियमन दिया जा रहा है, तो फिर क्यों वेल में चले आते हैं, इनलोगों को उनकी समस्या से कोई लेना-देना नहीं है, इनको सिर्फ राजनीति करना है, इनको सिर्फ अखवारों में छपवाना है, इनको मीडिया में बने रहना है, हमने तो कहा है महोदय कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिन चीजों की आवश्यकता है, आप सरकार को लिखित तौर पर दीजिये, उसपर भी कार्रवाई करेगी ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य ललित जी, आप जब अपनी सीट से बोल रहे थे, तो सब लोग आपकी बात को सुन रहे थे, अब यहॉ से बोलियेगा तो कैसे सुनेंगे ।

(व्यवधान)

भाई वीरेन्द्र जी तो पीछे से भी बोलकर सुनवा देंगे अपनी बात ।

श्री भाई विरेन्द्र: महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी क्या बोल रहे थे ?

(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: महोदय, इन्हें सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो हॉस्पिटल में बढ़िया इंतजाम है कान का, हमलोग इनको दवाई भी करा सकते हैं, इसके लिए सरकार से उपाय है ।

अध्यक्ष: आपलोगों की क्या इच्छा है कि शून्यकाल और ध्यानाकर्षण नहीं हो । अगर कहिये, तो नहीं हो ।

(व्यवधान)

अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/15-7-19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, ऊर्जा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए समय दिया जायेगा ।

राष्ट्रीय जनता दल	60 मिनट
जनता दल यूनाईटेड	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	41 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	19 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	01 मिनट
निर्दलीय	03 मिनट

माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री:अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

'' ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 88,94,31,85,000/-(अट्ठासी अरब चौरानवे करोड़ एकतीस लाख पचासी हजार) रू0 से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

महोदय, एक बात और मुझे कहनी है कि प्रश्नकाल में गलत सूचना पर मैंने यह कह दिया था कि जो लिस्ट में नहीं है कब्रिस्तान, वह भी विधायक फंड से होगा वह सही नहीं था, जो लिस्टेड हैं, उसी को विधायक फंड से भी किया जा सकता है ।

अध्यक्ष: यह आप स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं ?

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: जी ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, श्री ललित कुमार यादव, श्री सदानन्द सिंह, श्री भोला यादव, श्री महबूब आलम, श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री रामदेव राय से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक है जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: श्री ललित कुमार यादव ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: श्री सदानन्द सिंह ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: श्री भोला यादव ।

श्री भोला यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

'इस शीर्षक की मांग 10/-रू0 से घटायी जाय।'

महोदय, हमारे पार्टी के अन्य साथी इस पर विस्तृत रूप में अपना विचार रखेंगे ।

अध्यक्ष: ठीक है । श्री कुमार सर्वजीत ।

श्री कुमार सर्वजीत: अध्यक्ष महोदय, आज हम कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हुए हैं। महोदय, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिहार बिजली के मामले में...

अध्यक्ष: सर्वजीत जी, आपको 14 मिनट का समय आवंटित है ।

श्री कुमार सर्वजीत : जी । यह कहने में मुझे कहीं से कोई संकोच नहीं है कि बिजली के मामले में बिहार ने एक अच्छी अपनी पहचान बनायी है पूरे बिहार में और जो गरीबों के बीच में गांव तक जो बिजली पहुंचाना था उसमें निश्चित तौर पर इन्होंने कामयाबी हासिल किया है और हम बधाई देते हैं इस सदन में, जो इनके सी0एम0डी0 हैं प्रत्यय अमृत जी को, अपने तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उनके अन्दर काम करने का जो विजन है जो उनकी मेहनत है और बाकी सभी जो सदन के सदस्य हैं, उन्होंने जिस तरह से मेहनत किया है बिहार के एक-एक गांव में बिजली पहुंचाने के लिए, उसमें निश्चित तौर पर, मंत्री जी तो काफी सिनियर हैं, हम बहुत ज्यादा नहीं बोल सकते हैं लेकिन उनकी भी इच्छा शक्ति इतनी रही है कि बिहार में इसमें प्रगति हुआ है । महोदय, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी डिपार्टमेंट को बिजली पहुंचा देना, यही उसका एक मिशन नहीं होता है । बिजली पहुंचाने के साथ-साथ, पहुंचाने के बाद उसको किस तरह की

कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, इस पर मुझे लगता है कि विभाग में थोड़ी कमी रह गयी है । हमलोगों ने देखा है महोदय, 1990 के आसपास सिक्कम ऐसे राज्य, जहां पर इंसान चल नहीं सकता है, पहाड़ों की ऊंचाई छू नहीं सकता था, वैसे स्टेट में पूरे जंगल और पहाड़ बड़े-बड़े नदियों को पार करते हुए 1990 के आसपास वहां पर पूरे गांव में बिजली पहुंचा दी गयी थी । महोदय, हमारे यहां जो बिहार में बिजली पहुंचायी जा रही है गांव-गांव में, मैंने पहले भी कहा कि यह बहुत अच्छा कदम है लेकिन अभी जो बिहार में बाढ़ की हालात हुई है और जिन कम्पनियों ने यह काम किया, बाढ़ की जब स्थिति उत्पन्न हुई तो उनकी कामों की क्वालिटी सामने दिखने लगती है । हमलोगों ने पहले भी कई बार मीटिंग में कहा कि गांव के अन्दर जिस तरह से बिजली के खम्भे लगाये जाते हैं, वह मिट्टी के अंदर जो है महोदय उसको सिर्फ दबा के खड़ा करते हैं और जब बारिश आती है, तूफान आता है, आंधी आती है तो बड़े पैमाने पर बिजली के खम्भे गिर जाते हैं और गिरने के बाद फिर जो हमारा धन राशि उसमें लगता है, गरीबों का पैसा उसको पुनः खड़े करने में लगता है और साथ-साथ विभाग का जो मिशन है किसानों को बिजली पहुंचाना, दलितों के घर में बिजली पहुंचाना, बिजली पहुंचाने में जिस तरह से माननीय मंत्री जी ने मेहनत किया और जिस तरह से इनके विभागों ने मेहनत किया अगर उसी तरह का मेहनत मैन पावर पर होता कि अगर बिजली आपने पहुंचाया, एक-एक प्रखंड में 20-20 पंचायत होते है, 27 पंचायत होते हैं और अगर वहां पर देखेंगे तो उस प्रखंड में जो इनका ग्रिड है या सबस्टेशन हैं, वहां पर एक जे0ई0 और एक अलग से, प्राइवेट से ज्यादातर इनलोगों ने 1-2 आदमी को रखा है। वे 19 कि0मी0 का सफर तय करते हैं, 25 कि0मी0 का सफर तय करते हैं ग्रिड से, कहीं कहीं पर 63 कि0मी0, 50 कि0मी0 तक का भी हमलोगों ने बिजली ग्रिड से उस गांव में भेजा है जहां बिजली के तार गिर जाते हैं, खम्भे गिर जाते हैं लेकिन विभाग ने कभी इसको गंभीरता से नहीं लिया कि हम ग्रिड में साधन क्या उपलब्ध करायें हैं । अगर कोई सूचना प्राप्त होती है, कोई आदमी को करेंट लगता है तो वहां तक पहुंचने का इन्होंने कोई किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं किया है । हमने देखा है कि जब मैकेनिक, मिस्त्री जो है बिजली बनाने वाले इनके स्टाफ, वे कहीं जाते हैं तो मोटर साईकिल में बड़ा-सा सीढ़ी पीछे टांग लेते है और उसको लेकर गांव की ओर निकल जाते हैं । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि मैन पावर को, आप जिस प्रकार से गांव में बिजली पहुंचा रहे हैं उसको आज व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए मैन पावर की आवश्यकता है और अगर मैन पावर नहीं ला पाते हैं तो इतने बड़े पैमाने पर आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं बिजली पर और वह आप गांव की ओर दे रहे हैं तो वह बेकार

है। मैन पावर अगर आप पूरा कर लेते हैं, उसके कर्मचारियों के बहाली आप अगर करते है तो मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी जो आपकी व्यवस्था है, उसमें अच्छे ढंग से वह चल सकेगा । सब्सिडी आप देते हैं किसानों को, गरीबों को, बी0पी0एल0 को, ए0पी0एल0 को, बहुत प्रकार की सब्सिडी आप के द्वारा जो दी जाती है, हमलोगों ने देखा है कि जो लोग बी0पी0एल0 सूची में हैं, हमने देखा कि किसी बी0पी0एल0 सूची के लोग को डेढ़ लाख का बिल आया है, किसी को दो लाख का बिल आया है तो किसी को 50 हजार का बिल आया है, 10 हजार का बिल आया है ।(क्रमशः)

टर्न-9/मधुप/15.07.2019

...क्रमशः....

श्री कुमार सर्वजीत : आप सब्सिडी दे रहे हैं, उसका रेट आपने फिक्स कर रखा है, इसका मतलब यह होता है कि जो इन्होंने प्राइवेट तौर पर रखा है, बहुत सारे जिले हैं जहाँ इन्होंने प्राइवेट तौर पर रखा है कि हम मीटर का रीडिंग करके उसके घर तक बिजली बिल पहुँचायेंगे। उसमें मैं समझता हूँ कि यह विभाग पूर्ण रूप से फेल्योर है । जितने बड़े पैमाने पर गलत तरीके से बिजली बिल भेजी जा रही है, यह एक जाँच का विषय है । हम आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह भी करेंगे कि इसमें जब आप इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं तो आखिर गरीब बिजली बिल लेकर दर-दर क्यों भटक रहा है ? इनको इसपर अंकुश लगाना चाहिये ।

महोदय, मैं अपने बोधगया का ही उदाहरण देता हूँ, अन्तर्राष्ट्रीय स्थल है, कम से कम 150-200 से उपर मन्दिर हैं वहाँ पर । विदेशी मन्दिरों का बिल 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 1 लाख, इस तरह से जब आता है, वे लोग जब कम्पलेन लिखते हैं कि हमारे इस बिल में संशोधन होना चाहिए तो उसको देखने वाला कोई इनका अधिकारी उपस्थित रहता है और न इसपर कोई कार्रवाई होती है । गाँव के अन्दर अभी किसानों को जरूरत है, एक तरफ अकाल पड़ा है पूरे मगध प्रमंडल में, दूसरी तरफ उत्तरी बिहार बाढ़ से प्रभावित है, जहाँ पर अकाल पड़ा है वहाँ पर मैं समझता हूँ कि किसानों को अविलम्ब बिजली उपलब्ध कराना चाहिये सिंचाई के लिए । हमलोग एक मीटिंग में गये थे, उसमें हमलोगों को यह संज्ञान में आया, उसमें कम्पनी के लोग भी थे, उन्होंने कहा है कि हम जितना जल्दी हो सके, किसानों को बिजली पहुँचा देंगे । लेकिन उसमें तेजी लाना चाहिए । हम यही इनसे आग्रह करते हैं । साथ-साथ महोदय, कई बार हमने विभाग में भी कहा बोधगया जैसा इतना विश्वविख्यात स्थल है और वहाँ पर जब आंधी-पानी आती है, एक साथ बिजली के खम्भे, तार, सब गिर जाता है ।

इससे मेसेज अच्छा नहीं जाता है । वहॉ पर हमेशा 2 हजार, 4 हजार, 5 हजार विदेशी लोग रहते हैं । हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय जी से कि कम से कम इस तरह के जो पर्यटक स्थल हैं, राजगीर है, बोधगया है, वैशाली है, इन सब पर्यटक स्थल में कम से कम बिजली अंडरग्राउंड होनी चाहिए ताकि वहॉ पर जो समस्या उत्पन्न होती है, उससे छुटकारा मिल सके । एक बार जब बारिश हो जाती है तो पूर्ण रूप से 24 घंटे, 20 घंटे बिजली ठप हो जाती है । इसलिये हम आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बोधगया ऐसे पर्यटक स्थल पर कम से कम अंडरग्राउंड बिजली लगायें । मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पर अपनी बात को रखते समय हमें जरूर बतायेंगे कि वहॉ पर हमने क्या प्रयास किया है ।

एक पर्यटक स्थल है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी वहॉ पर कई बार गये हैं, बखरौर एक गॉव है, वहॉ पर सुजातागढ़ माना जाता है कि भगवान बुद्ध को सुजाता ने खीर खिलाया था, वहॉ पर डेली जब सितम्बर से लेकर जनवरी-मार्च-अप्रील तक जब सीजन होता है, वहॉ पर बड़े पैमाने पर पर्यटक जाते हैं लेकिन हमलोग कहते-कहते विभाग को थक गये कि उसमें थाना से जो ड्यूटी लगती है, तीन-तीन चौकीदारों की मृत्यु हो गई लेकिन हमलोग कितनी बार पत्राचार किये कि उस गॉव में जो तार लटके हुये हैं, एक बार विदेशी बस में करेंट आ गया, उसके बावजूद भी वहॉ संभव नहीं हो सका । हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि जहॉ पर देश-दुनिया में आपकी बदनामी होती है, इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी, वैसे जगह पर निश्चित तौर पर आपका ध्यान जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, मुआवजा का मामला है कि जिस तरह से हमलोग बिजली पूरे गॉव में पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और किये हैं, उसमें गरीब-गुरबा जो है, वह बेचारा अपने केबिन पर, मशीन पर तार ले जाता है और जब वह जिला में आवेदन देता है विभाग को कि हमको तार की आवश्यकता है खेती के लिए हमको वहॉ पर, इनके विभाग के स्टोर में ट्रांसफर्मर नहीं रहता है, इनके पास पोल नहीं रहता है ।

(इस अवसर पर श्री मो0 नेमतुल्लाह ने माननीय सभापति का आसन ग्रहण किया)

सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि कम से कम हर जिला में स्टोर होना चाहिये जहॉ पोल-तार-ट्रांसफर्मर होना चाहिये । सीधे वहॉ पर एक लाईन में कह देते हैं कि जो कम्पनी काम कर रही है, उससे आप कांटेक्ट कर लीजिये, तो मैं समझता हूँ कि विभाग को भी कम से कम से इसको अपने पास स्टोर करके रखना चाहिए ताकि समय रहते काम हो सके ।

महोदय, फिर से हम माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि बिजली में सुधार तो होगा ही, साथ-साथ बिल का जो प्रोब्लेम है, आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं और सड़क पर लोग बिजली का बिल लेकर आंदोलन कर रहे हैं ! इन्होंने बीच में प्राइवेट कम्पनी को दिया, हम बधाई देते हैं सी0एम0डी0 साहब को कि जब हमलोगों ने प्राइवेट कम्पनी के खिलाफ कम्पलेन किया तो उसकी छुट्टी हुई लेकिन जो सरकारी संस्थाएँ हमारी काम कर रही हैं और जनता त्राहिमाम है बिजली बिल को लेकर, एक घर में अगर दो फैमिली है, उसका बिजली बिल 25 हजार से 30 हजार आ रहा है । इसका मतलब मुझे लगता है कि सरकार जो सब्सिडी देती है, कहीं उस सब्सिडी को आम जनता से इस तरह का पैसे की उगाही करके अपनी भरपाई तो नहीं कर रही है ! इसलिये हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि एक सिस्टम ऐसा लाया जाय, पूरे बिहार में जितने जगह आपका बिजली बिलिंग का काम हो रहा है, सब प्राइवेट संस्था को दी जा रही है और प्राइवेट संस्था जो एवरेज निकालता है कि पिछले महीने उनका बिल कितना आया था, पिछले महीने अगर उनका बिल 25 हजार का बिलिंग हुआ तो बैठे-बैठे कम्प्युटराइज्ड सिस्टम से उसको 1-2 हजार बढ़ाकर फिर उसके यहाँ बिजली बिल भेज देते हैं । यह बहुत बड़ी खामी है ।

हम आग्रह करेंगे, माननीय मंत्री जी काफी लम्बे अरसे से इस पद पर हैं, उनके अन्दर क्षमता है, वे हमलोगों को भी सीख देते रहते हैं कि तुमलोग नौजवान हो, एक काम करने की इच्छाशक्ति लाइये और कुछ नया करने की कोशिश करिये । हम आपके सिखाये हुये नक्शेकदम पर मैं आपसे आग्रह करते हैं कि आप स्वयं इसकी मोनिटरिंग करिये कि आखिर गरीब जनता को आप इतनी सहुलियत दे रहे हैं बिजली का लेकिन इतने बड़े पैमाने पर उनको बिजली बिल क्यों दिया जा रहा है ?

आज ऊर्जा विभाग के साथ-साथ पर्यटन विभाग की भी माँग है, माननीय पर्यटन विभाग के मंत्री जी यहाँ होते तो हमलोगों को अच्छा लगता कि कुछ बात को वे समझते । अब चूंकि वे यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, अहम यह मुद्दा था बिहार के लिए, मैं समझता हूँ कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग एवं मद्य निषेध विभाग के भी मंत्री यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, चूंकि ऊर्जा मंत्री इतने विद्वान हैं, अपने काम की जिम्मेवारी को वे समझते हैं, सभापति महोदय, अगर नहीं भी हैं तो सदन की कार्यवाही में तो कम से कम आ ही जायेगा । हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बोधगया पर्यटक स्थल है और पूरे देश-विदेश के लोग आते हैं । सरकार की पॉलिसी, मुझे ताज्जुब होता है कि राजस्थान एक रेगिस्तान का राज्य है और देखिये वहाँ की सरकार की क्षमता, काम करने की इच्छाशक्ति कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े लोग

प्रचार करते हैं कि रेगिस्तान में आप आइये और रेगिस्तान के महत्व को समझिये और हमारी सरकार दलाई लामा जैसे व्यक्ति को भी आग्रह नहीं कर सकती है कि आप बोधगया में आइये और आकर हर साल पूजा करिये । महोदय, हमलोग जो बोधगया के स्थानीय नागरिक हैं, दलाई लामा को बोधगया में लाने से यहाँ की सरकार को राजस्व का फायदा, बड़े पैमाने पर डॉलरों का फायदा होता है, विदेशी मुद्रा आता है लेकिन मैंने नहीं देखा है कि इनके विभाग में आज तक, जब से इनकी सरकार बनी, एक भी हमने ऐसा नहीं देखा कि ये पर्यटकों को बोधगया या बिहार में लाने के लिए, विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए किसी तरह का काम किये हों ।

सभापति महोदय, समय हमारा समाप्त हो गया इसलिये बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-10/आजाद/15.07.2019

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : जनता दल युनाईटेड के माननीय सदस्य श्री राज किशोर सिंह, आपका 10 मिनट समय है ।

श्री राज किशोर सिंह : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत,बहुत धन्यवाद । आज बिजली पर चर्चा है । बिजली यानी रोशनी, रोशनी हमारे अन्दर उत्साह पैदा करता है । हम निडर बनते हैं और वही अँधेरा हमें अवसाद में ले जाता है । मैं सबसे पहले इसी उत्साह में भोला बाबू से निवेदन करूँगा यूं तो बिहार का सर्वांगिण विकास हुआ हर क्षेत्रों में, जब से माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, सर्वांगिण विकास हो रहा है लेकिन खासकर के बिजली के क्षेत्र में यह मैं नहीं कहता हूँ, सर्वजीत जी का भाषण भी यही बात कह रहा था । बिजली के क्षेत्र में आऊटस्टैंडिंग अभूतपूर्व काम हुआ है बिहार में और इसके लिए बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी का कुशल नेतृत्व और मोदी जी का सहयोग और काबिल मंत्री विजेन्द्र यादव जी का साथ और हमें गर्व है प्रत्यय अमृत जैसे कार्य क्षमता वाले अधिकारी पर पूरे बिहार को गर्व है । वे जितना काम करते हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष, तमाम बिहार के वासी उनके विषय में जानते हैं । इसलिए भोला बाबू से कहेंगे कि आज के इस सदन को ऐतिहासिक सदन बनाईए और बिजली बिल के बारे में सरकार के द्वारा जो बजट लाया गया है, तमाम सदस्य मेज थपा-थपा कर समर्थन कीजिए, इससे न सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी बल्कि बिहार की जनता के निकट आप जायेंगे और वो आप पर ज्यादा विश्वास और भरोसा करेंगे ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप अपनी बात जारी रखिए ।

श्री राज किशोर सिंह : मैं कहना चाहूँगा कि बिहार को लोग बीमारू राज्य कहते थे, लेकिन बिजली की उपलब्धता के चलते बिहार फंक्शनल स्टेट की सूची में शामिल हो गया । ऐसा बिजली काम किया है जिसके चलते हम फंक्शनल स्टेट जो देश में 6-7 हैं, उसमें हमारा राज्य शामिल हो गया । इसीलिए मैं फिर से कहूँगा और बार-बार आज कहूँगा भोला बाबू, संयोग से पहले के तीन कटौती प्रस्ताव आये थे, वे तो अनुपस्थित थे लेकिन एकाएक इतेफाक आया है कि आज भोला बाबू उपस्थित हो गये हैं, इसलिए भोला बाबू से आज ज्यादा निवेदन होगा । सर्वजीत जी के भाषण में भी यही बात थी, मैं कहना चाहूँगा कि नीतीश जी का जो कुशल नेतृत्व हुआ .....

श्री भोला यादव : सभापति महोदय, बार-बार माननीय सदस्य मेरा नाम ले रहे हैं, यह श्रेय अगर किसी को देना है तो फर्स्ट यू0पी0ए0 गवर्नमेंट को दीजिए, जिसमें आदरणीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और हमारे माननीय नेता श्री लालू प्रसाद रेल मंत्री थे ....

श्री राज किशोर सिंह : भोला बाबू हो गया । महोदय, मैं गांव से आता हूँ, मैं बताना नहीं चाहूंगा चूँकि यह सब लोग बेहतर जानते हैं कि बिजली के क्षेत्र में क्या-क्या काम हुए हैं । मैं एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा । मैं गांव से आता हूँ, अभी एक साल पहले मैं अनुसूचित जाति के बस्ती में रात के 7-8 बजे गया था । एक बूढ़ा आदमी जब हमको देखे तो वे मेरे नजदीक आ गये और वे हमारा बदन पकड़ लिया और उनके ऑख में मैंने ऑसू देखा तो मैं समझ नहीं रहा था कि क्या बात है, चेहरा देखा तो लगा कि वे खुश भी हैं और ऑसू भी है । मैं सदन को बताना चाहता हूँ उनके खुशी के विषय में, मैं कुछ पूछता, मैं अचंभित हो गया क्या बात है, क्यों रोने लगे, कहने लगे कि बाबू 85 साल का उम्र उनका रहा होगा, कहने लगे कि हम नहीं जानते थे कि हमारे बस्ती में भी और मेरे घर में भी कभी बिजली आयेगी, ऐसा उनका सोच था । वे सोच भी नहीं पाये थे कि हमारा घर भी कभी बिजली से रोशन हो पायेगा । यह काम है बिहार सरकार का, यह काम है बिजली विभाग का, इसीलिए यह सदन को चाहिए कि बिजली विभाग के तमाम परिवार को धन्यवाद देना चाहिए आज, उस दलित के ऑख के खुशी को देखकर के । जो कभी कल्पना नहीं किया था कि उनका घर रोशन होगा बिजली से, हमलोग ढिबड़ी और लालटेन में बचपन में पढ़े और मैं समझता हूँ कि जो दलित बस्ति जो कभी सपना में भी नहीं सोचा, वह बस्ति भी आज रौशन है । गांव में जब हमलोग बच्चे थे तो गांव के लोगों को, अपने बच्चे को कहते थे कि अँधेरा में मत जाओ, भूत है, उनके मन में यह भ्रम रहता था कि अँधेरा में अगर बच्चा जायेगा तो उसको साँप काट लेगा, बिच्छू काट लेगा लेकिन भूत बताकर के डर पैदा करके बच्चा को अँधेरा में नहीं जाने देते थे । आज जो मलिन बस्ती है, जो दलित बस्ती है, जो गरीब बस्ती है,

वहां भी आज रोशन है, वहां भी गुलजार दिखता है, यह है बिजली । बिजली के क्षेत्र में कहां काम नहीं हुआ । आप इस सूबे के जिस कोने में जायं, जिस गांव, कस्बे में जायं, जिस टोले में जायं, सब जगह आपको बिजली दिखेगी । बिजली न जात का, न धर्म का भेदभाव करता है । यह समाजवादी काम हुआ है, समावेशी विकास हुआ और जस्टिश फॉर ऑल इसमें दिखता है, जो माननीय नीतीश कुमार जी का नारा है, सोच है, जो विजन है, जो गोल है, वह दिखता है । जस्टिश फॉर ऑल समावेशी विकास, इसके अन्दर दिखाई पड़ता है । महोदय, बिजली के क्षेत्र में जितने काम हुए हैं, उसमें अगर सबसे ज्यादा काम और सबसे ज्यादा लाभ अगर मैं समझता हूँ कि किसी एक को है तो वह है किसान । किसान को सबसे ज्यादा लाभ हुआ है । किसान को लाभ होने के कारण है अभी जो दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लागू हुआ, अभी यू0पी0ए0 का नाम ले रहे थे, मैं मानता हूँ कि यू0पी0ए0 की सरकार ने भी मदद की थी, इससे हम इंकार नहीं कर सकते हैं जो मेरे जानकारी में है । लेकिन वर्तमान सरकार, दिल्ली की सरकार अभी जो वर्तमान दिल्ली की सरकार है और जस्ट इसके पहले की सरकार थी, उसने भी पुरजोर मदद किया है बिहार सरकार को बिजली के क्षेत्र में और बिहार का कुशल नेतृत्व और जो माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री और बिजली विभाग के तमाम कर्मचारी जिनका सहयोग रहा है, जिसके चलते आज इतना काम हुआ है, इससे आप इंकार नहीं कर सकते हैं । दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत आज किसानों को बिजली मिल रही है और हर खेत को बिजली मिल रही है । अभी तक 5200 पम्पिंग सेट को बिजली पहुँचायी जा चुकी है । मैं समझता हूँ , आप हिसाब जोड़ लीजिए, मैं किसान परिवार से आता हूँ । एक घंटा अगर पम्पिंग सेट चलता थ तो 100रू0 खर्च होता था । आज 5 रू0 में उस किसान को बिजली मिलती है और अगर कोई छोटा किसान उनके बगल में है तो उसको कितना पैसा देना पड़ता था 125 से 150 रू0 प्रतिघंटा तब वह पटवन करता था । लेकिन आज क्या है, जब 5 रू0 उसका लागत पड़ता है, वह 20 रू0 में बिजली का पानी एक घंटा में बेच देता है । उसको भी फायदा है और लेने वाले को भी फायदा है । इससे क्या फायदा हुआ, उस किसान को तो पैसा बचा ही, हमारा डॉलर बचा । हम तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ राजनीति किया था । जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का एक वाक्या बताता हूँ । मैं उनके साथ चल रहा था, जब महुआ के तरफ बढ़ा तो वे देखें कि हमारे साथ गाड़ी चल रही है, उन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और कहा कि मुझे जाने के लिए दो गाड़ी जायेगी, आप समस्तीपुर रात में जायेंगे क्यों, एक आदमी के लिए दो गाड़ी और उन्होंने

गुस्सा में कहा कि आपको मालूम है पाई-पाई देश जमा करता है तब जाकर कहीं तेल खरीद होती है । यह माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का सीख था और वह पैसा डॉलर आज.

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप दो मिनट में समाप्त करें ।

श्री राज किशोर सिंह : हमारा बिजली विभाग वह डॉलर आज बचा रहा है । बिजली के क्षेत्र में अनेकों काम हुए हैं । मैं संक्षेप कर देना चाहता हूँ, देख लीजिए 4000 मेगावाट आपका बांका में, 1980 मेगावाट नवीनगर में, चौसा में 1320 या तो काम हो रहे हैं या होने वाले हैं । इस तरह से जहां 700 मेगावाट बिजली आपूर्ति होती थी बिहार में, वही आज 5100-5200 मेगावाट बिजली आपूर्ति हो रही है और दूसरे राज्य के लोग भी आज बिहार में आते हैं, जो 15-20 साल पहले आये थे, वे भी आते हैं तो बिजली देखकर अचम्भा हैं । कोलकाता के लोग यहां आते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहां आपसे ज्यादा लोडशेडिंग है । जबकि हमलोग बचपन में कोलकाता जाते थे तो कोलकाता को देखकर हमलोग तरसते थे कि यहां पर इतनी बिजली रहती है और यहां तक सुख-सुविधा की बात है, भौतिकता की बात है, भौतिकवाद की बात है तो आज गांव के लोग भी ए0सी0 में रहने लगे, कूलर में रहने लगे हैं, यह बिजली का देन है लेकिन हम आज तमाम लोगों से एक निवेदन और करेंगे कि आप तमाम लोग बिजली बचाने का प्रयास करेंगे और यह सदन जिस तरह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के मुद्दे पर एकमत हुआ था, उसी तरह आज बिजली के बजट के समर्थन में पूरा सदन मेज थपा-थपा कर इनके बजट को पास करे, 5 मिनट पहले नहीं जायं, इन्हीं निवेदनों के साथ आप सब लोगों को बहुत, बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आपको भी बहुत,बहुत धन्यवाद ।

टर्न-11/शंभु/15.07.19

श्री राजेश कुमार : सभापति महोदय, हमलोग तो विशेष राज्य का दर्जा मांग ही रहे हैं, ये ही साथ नहीं देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री सत्यनारायण सिंह : महोदय, सरकार द्वारा जो अनुदान मांग पेश किया गया है उसके समर्थन में और कटौती प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लाया गया है उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूँ। हम समझते हैं कि जो एन0डी0ए0 की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मोदी जी और विजेन्द्र बाबू के नेतृत्व में सरकार चल रही है । खासकर के बिजली के क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया गया है और हमारा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा काम करे तो उसको और प्रोत्साहित करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप

पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं आपको और पैसा देना चाहिए । इसलिए कटौती का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिए बल्कि कहना चाहिए कि आप और पैसा लीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं । जहां तक बिजली के बारे में पूर्व में अगर चले जाएं तो हम देखते थे कि बिजली नहीं रहती थी, हमलोग बाहर रहते थे और जब बिजली आती थी, कभी-कभी आती थी तो दौड़कर जाते थे कि कम से कम 1 घंटा उसका आनन्द लें और आज सुनने में आता है कि 10 मिनट कटा बिजली आ जाती है । इसलिए सरकार की जितनी प्रशंसा की जाय वह कम है । जहां तक बात है आम लोगों की तो यहां की 80 परसेंट आबादी किसानी पर निर्भर है । फैक्टरी के लिए ही नहीं यह सरकार किसानों के लिए कृत संकल्पित है । दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 2019 तक अलग फीडर की स्थापना करके और 75 पैसे प्रति यूनिट देकर के जो साथी चर्चा कर रहे थे कि डीजल का दाम नहीं इससे सस्ता सूबे हिन्दुस्तान में कहीं बिजली का बिल नहीं है । यह एन0डी0ए0 सरकार लक्ष्य निर्धारित करके करने का काम कर रही है । हम समझते हैं सूबे बिहार में कहीं भी चले जाइये और खासकर बिजली के बारे में हम नहीं बिहार के जितने भी पिछड़े हों, दलित हों, बी0पी0एल0 परिवार के हों झोपड़ी में हो आज लालटेन जलाने की जरूरत नहीं है । उसी का प्रतिफल है कि समाज के जितने लोग हैं एकमुश्त होकर सरकार का समर्थन किया । इसलिए साथियों जहां तक हमारे क्षेत्र की बात है, माननीय मंत्री जी वहां गये थे और लोगों ने लिखा था- हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे 1984 के बाद डालमिया नगर में लोग अंधेरे में थे, लेकिन कोर्ट के द्वारा उस जमीन का परमिशन हो गया है । हमारे सी0एम0डी0 यहां पर हैं, हमने मिलकर कहा भी था और बड़ी खुशी की बात है उन्होंने संज्ञान में लिया, पोल गिर गया है, लेकिन प्रोजेक्ट का काम थोड़ा स्लो चल रहा है । वहां हम समझते हैं 18 ट्रांसफार्मर चूंकि डालमिया नगर किसी जमाने में- टाटा, बिड़ला, डालमिया का नाम सबलोग जानते हैं । उन्हीं के कर्मचारी लोग बिजली से वंचित थे, अगर वह लगा दिया जाता तो बड़ी अच्छी बात होती । जहां तक डेहरी नगर की बात है, डेहरी नगर में अभी प्रोजेक्ट का वर्क चल रहा है और डेहरी मेन टाउन में जो तार है वह इधर से उधर क्रॉस होता है जिसके कारण किसी पर्व या त्योहार में या तजिया में लाइन काटना पड़ता है । डिहरी एक छोटा सा जगह है, रिंग रोड है उसके किनारे दोनों साइड से पोल करके केबलिंग कर दिया जाय तो डेहरी का लाइन कटने का दिक्कत नहीं होगा । दूसरी बात है कि हमारे यहां तेतरार एक जगह है । अकोढ़ीगोला फीडर है, डेहरी में है, मथुरापुर में है, लेकिन तेतरार में अगर फीडर की स्थापना हो जाती है तो चांदबधुआ, महमरी, राजपुर के इस साइड में बिजली निर्बाध सप्लाय होगा, बल्कि एक आग्रह माननीय मंत्री जी से करेंगे

कि हमारा पूरा क्षेत्र ओबरा है और वहां से दो बार हम विधायक रहे हैं । इस बार हम डेहरी से लड़े, लेकिन ओबरा में एक बहुत पुराना मांग है कि अगर दाउद नगर में माननीय मंत्री जी वहां गये थे । वहां दाउद नगर में ग्रिड की स्थापना कर दी जाय तो अभी औरंगाबाद से और बारूण से चूंकि दूरी लंबी पड़ती है, कभी बरसात के दिनों में या आंधी तूफान के चलते तार टूट जाता है तो 4-5 घंटा बिजली नहीं रहती है । इसलिए वहां ग्रिड की स्थापना कर दी जाय तो जनता को बहुत सहूलियत होगी । चूंकि मांगता उसी से है- कहा गया है कि मांगे उसी से जो दे दे खुशी से । हम समझते हैं माननीय मंत्री जी वहां गये भी थे और जान रहे हैं वहां की समस्या- हम समझते हैं कि इसका निदान हमारे माननीय मंत्री जी अवश्य करेंगे । अभी हमारे क्षेत्र डेहरी ऑन सोन में तेतरार में कुछ एडीशनल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, जैसे- तेतरार बालपर, तेररार बाजार में, कपसिया गांव के पश्चिम भाग में, बाघातो, राजपुर में ज्ञानी जी के पास, देवरिया में और कुछ डेहरी नगर में । अभी

सभापति(मो0नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिए, लिखित है तो दे दीजिए ।

श्री सत्यनारायण सिंह : महोदय, एक मिनट । जहां तक पर्यटक के बारे में बात है । हम बहुत धन्यवाद देते हैं हमने बहुत सारा प्रोजेक्ट देखा, लेकिन हमारे यहां एक जगह है, बहुत पुराना झारखण्डी मंदिर, डेहरी ऑन सोन- वहां हजारों शादियां बिना दहेज के होता है, हम समझते हैं कि पर्यटक स्थल है । वहां पर लाखों श्रद्धालु साल में पहुंचते हैं। वहां एक विश्रामालय बन जाय । हमने देखा सरकार को कोटि-कोटि धन्यवाद देते अगर वहां एक गेस्ट हाऊस बना दिया जाय तो बहुत अच्छी बात होगी । इसलिए अब इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ । धन्यवाद, नमस्कार ।

टर्न-12/ज्योति/15-07-2019

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री राम देव राय जी ।

श्री रामदेव राय : सभापति महोदय, कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैं अपने कुछ शब्द चंद मिनटों में रखना चाहता हूँ । ऐसे तो मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि बिहार में बिजली के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : 6 मिनट ही टाईम दिया गया है, माननीय सदस्य रामदेव बाबू।

श्री रामदेव राय : 6 मिनट ! 2 मिनट में काम चल जायेगा ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): आपको पार्टी ने इतना ही समय एलौट किया है ।

श्री रामदेव राय : विद्युत के क्षेत्र में वहॉ की लोकल समस्या का अध्ययन किया हूँ, कई राज्यों का और हमारा राज्य उस मामले में काफी आगे है और काफी तेजी से विद्युत के क्षेत्र में हमारा विकास हुआ है । इसका श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सी.एम.डी. साहेब, एम.डी. साहेब और उनके सहयोगियों का है । उन्हें धन्यवाद दिया जाता है,,अच्छा काम किए हैं, तारीफ के योग्य हैं । इसके अलावे भी विद्युत है, हर घर तक विद्युत पहुंचाना है । यह कार्य भी कोई सरल काम नहीं है । यद्दपि मुख्यमंत्री जी अपना वचन पूरा कर चुके हैं कि 2018 के दिसम्बर तक हर घर में बिजली पहुंचाने का, मगर सर्वे करके देखा जाय तो अभी भी बहुत सारे गांव छूटे हुए हैं । बसावटें छूटी हुई हैं । इन बसावटों पर अलग से सर्वे कर बिजली विभाग ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि बिजली विभाग का यह लक्ष्य जो दिसम्बर तक पूरा होना था वो निश्चित रुप से कुछ दिन में पूरा हो सकता है । दूसरी बात मैं, कुछ व्यावहारिक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आंकड़े से हमारा काम चलने वाला नहीं है । हमारी कई परियोजनाएं मंत्री जी बहुत दिनों से लम्बित हैं । ऐसे तो आपने बरौनी को भी एन.टी.पी.सी. में दे दिया है, कांटी को भी दे दिया है । इसके लिए शायद आप सोचे होंगे कि इससे काफी लाभ है मगर समय सीमा के अंदर वह काम पूरा कर दे तब तो एन.टी.पी.सी. अपना काम समय पर पूरा कर नहीं पाता है आप उसपर अतिरिक्त भार दिए हैं, खैर दिए हैं, यह सरकार का फैसला है, ठीक बात है मगर चौसा कितने दिनों से लम्बित है, इस पर गौर फरमाना आपको है । कई स्कीमें हैं आपके पाास जिन पर आपको गौर फरमाना है । आप देख लीजिये इन्द्रपुरी जलाशय येाजना , डगमारा इसीतरह से नवीनगर सभी योजनाएं अभी तक या तो विस्तारीकरण में जा रही हैं और अभी तक वह पूरी नहीं हुई हैं । अगर यह पूरी हो जाती तो माननीय मंत्री रेकर्ड कायम कर लेते देश में, ऐसे भी रेकर्ड की ओर आप जा रहे हैं । इसमें थोड़ा मेहनत की जरुरत है, आपके सी.एम.डी. साहेब काफी मेहनत करते हैं । मालूम है अतिरक्त कई विभाग के प्रभार में रहते हुए भी, अगर जो पुरानी योजनाएं हैं, उसको पूरी कर लेते तो बिहार एक गरीब राज्य नहीं रह सकता है । अभी भी आप देख लीजिये पन बिजली योजना की भी हालत वही है । हमारी 11 यूनिट अभी भी मैं समझता हूँ कि सफल रुप से संचालित नहीं है । पन बिजली योजना से कितना लाभ होगा हमारे यहॉ नदियों का भण्डार है गंगा, गण्डक, वाया, बेलान, बैंती, करई, कमला और अनेक और हर साल हमारा पानी बर्बाद होता है बाढ़ से इस पानी को हम रोक कर न तो खेत में दे पाते हैं, न कोई इससे उत्पादन के अलावे अन्य काम ले सकते हैं तो कम से कम बिजली उत्पादन का काम तो हम यहॉ मजे से कर सकते हैं हमारे पास पूरा साधन है, टेक्नोलॉजी भी है यह नहीं है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं

है, नये नये टेकनोलॉजी के मध्यम स इन योजनाओं को आपे इसे खेत में उतार सकते हैं और जहॉ तक अभी जो आपका कार्य चल रहा है ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जो पहले राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम प्रसिद्ध था भले आप उसका नाम बदल दिये लेकिन आज भी गांव में उसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण येाजना के नाम से ही जानते हैं । ठीक है, कोई बात नहीं सरकार आपकी है, जितने बार आप नाम बदल दें लेकिन आपको देखना होगा कि इसके जरिये जो आप काम किए हैं और इसके अलावे अब आप एग्रीकल्चर फीडर अलग तैयार कर रहे हैं और उसके जिम्मे ही नये मीटर लगाने का काम दिए हैं । नया मीटर लगाने में आर.ई.सी. को भी आप जवाबदेही दे दिए हैं । यह जितना तेजी से काम करना चाहिए मेरे ख्याल से मैं जो स्टडी किया हूँ उसके मुताबिक वह तेजी से काम नहीं कर रहा है इसलिए जो गांव में जो प्रीपेड मीटर की जरुरत है आपूर्ति नहीं हो रहा है । प्रीपेड मीटर अगर आप दे दते गांव में जो समस्या है कि आज उपभोक्ताओं की वह समस्या नहीं रही जाती । समस्या यह है कि जो सारे मेम्बरान कह रहे हैं कि इस महीने में हमारे पास बिल आता है दो ह जार रुपाये का तो अगले माह हमारे पास बिल आ जाता है 4 हजार क्योंकि जितने भी मीटर रीडर हैं और उसक कंट्रैक्टर हैं सभी लोकल होते हैं और लोकल में जिसको आज कल हीरो कहते है, उस टाईप के होते हैं जिसको जैसे मन होता उसी तरह से वूसल करता है आपा शिविर लगाने की बात करके उसका निपटारा करना चाहते हैं । शिविर अगर नियमित रुप से होता, शिविर नियमित रुप से हो और होना चहिए तो निश्चित रुप से उपभेक्ता को इससे लाभ होगा चॉकि एक घर में आप दो हजार रुपया लेते हैं और दूसरे महीने में 4 हजार रुपया लेते हैं । लेकिन फिर आप एक बात भूलते हैं कि परिवार हैं सात एक घर के नाम से उपभोक्त बनाते हैं तो 6 घर छूट जाता है तो नुकसान किसका हुआ, यह सरकार को नुकसान हुआ बिजली विभाग को नुकसान हुआ, इसका कारण क्या है कि आपके पास हैण्ड नहीं है लाईनमैन नहीं है । कौंग्रेस के टाईम में लाईन मैन गांव गांव में होता था आज लाईन मैन ढूंढने से मिलता ही नहीं है ।

(व्यवधान)

लाईन तो ऐसा था कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से पहले आप बिजली देखे होंगे, आप देखें होंगे औार आपको खुशी हुई होगी चूँकि आपने कूर्परी ठाकुर जी का नाम लिए इसलिए कहता हूँ, वह धन्यवाद दिए थे हम ही को मैं बिजली मंत्री था, दूसरी बात टैरिफ के बारे में कहना चाहता हूँ कि बिहार गरीब राज्य है । बिहार के किसानों की हालत देखकर टैरिफ का फैसला कीजिये । यह अभी संपन्न राज्य में नहीं है । जब

संपन्न राज्य हो जायेगा तब आप इसके टैरिफ के बारे में सोच सकते हैं । टैरिफ को किसानों के लायक बनाईये ताकि किसान टैरिफ देने लायक हो जाय ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : ठीक है रामदेव बाबू अब समय आपका हो गया ।

श्री रामदेव राय : ठीक है समाप्त करते हैं । आप अभी नया रिस्ट्रक्चर किए हैं विभाग का हर जग्रह लेकिन रिस्ट्रक्चर सबडिवीजन का, सब सेक्टर का यह बहुत अच्छा काम किए हैं । इससे रेवेन्यू में आपकोबबहुत मदद मिलेगी लेकिन अभी तक कार्यान्वित वह नहीं हो पाया है । लगता है कि 6 महीना से अधिक हो गया लेकिन यह अभी कार्यान्वित नहीं हो सका है इसलिए आपने विभाग को रिऔर्गेनाईज किए हैं, औफिस को, कार्यालय को इसको जल्द से जल्द कार्यान्वित करा दीजिये ताकि आपके काम में और सप्लाई मेंटेन करने में, कन्ज्युमर की असुविधा को दूर करने में राजस्व वसूली करने में, प्रशासन को चलाने में कन्ज्युमर से सीधा संबंध रखने में और सरकार और कन्ज्युमर और विभाग को सीधा संबंध तय करने में वह काम करेगा कोऔर्डिनेशन का काम करेगा ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब रामदेव बाबू समाप्त कीजिये ।

श्री रामदेव राय : कर रहे हैं समाप्त । अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि बिजली के संबंध में आपने जितनी तरक्की की है, उसी तरह बिहार की तरक्की के लिए अन्य क्षेत्रों में भी कारगर कदम उठाना चाहेंगे ।

टर्न : 13/कृष्ण/15.07.2019

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री रामविशुन सिंह

श्री राम विशुन सिंह : सभापति महोदय, ऊर्जा विभाग के अनुदान मांग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये मुझे अवसर मिला है, इसके लिये मैं अपने नेता एवं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं ।

महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी इस सदन में हमारे अविभावक के रूप में हैं और एक लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसका लाभ आज हमलोगों को देखने को मिल रहा है । महोदय, बिहार के सभी विभागों से कोई अच्छा है तो वह है ऊर्जा विभाग । बिहार में जितने भी विभाग काम कर रहे हैं उसमें ऊर्जा विभाग प्रथम स्थान पर चल रहा है । परन्तु इसमें अभी कुछ कमियां हैं, जिसको सुधारने की आवश्यकता है। महोदय, मेरा कहने का मतलब है कि बिजली विभाग का जो कार्य करना चाहिए, गांवों के लोगों को जितनी बिजली की आवश्यकता है, वह अभी पूरा नहीं हुआ है ।

महोदय, हम यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यह देना यू0पी0ए0 की सरकार है । यह स्व0 राजीव गांधी जी, जो हमारे नेता थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री

थे, उन्होंने देश के गावों के बारे में सोचा था और उस समय उन्होंने राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना लागू करने का काम किया । हमारे आर0एस0एस0 के लोग इस का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति कर दिया । हमारे मंत्री जी यहीं है, हम कहना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो बिजली के तार हैं, जिस संवेदक को तार बदलने का काम दिया गया है, जिसका नाम है मे0 वी0टी0एल0 कंपनी, जिसने अभी तक पुराने बिजली के तारों को नहीं बदला है । हम अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, न वह कवर का तार लगाया और न 11000 और 33000 का लाईन जो देना था, उसका काम अभी सही ढंग से नहीं चल रहा है ।

महोदय, हमारा राज्य कृषि प्रधान राज्य है । यहां के 80 प्रतिशत लोग आज भी खेाती पर निर्भर हैं । आप दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति के माध्यम से किसानों को बिजली का लाईन उपलब्ध कराना चाहते हैं । अभी हमने देखा है कैप कॉन इन्डिया प्रा0 लिमिटेड को आपने काम दिया है, सी0एम0डी0 साहब यह सुनते होंगे । महोदय, भोजपुर जिला में उसकी स्थिति इतनी पुअर है, वहां 5 परसेंट भी काम नहीं किया है जबकि सरकार कह रही थी कि हम मार्च,2018 तक योजना को पूरी कर देंगे, फिर कहे कि 2019 तक पूरा कर देंगे । लेकिन भोजपुर जिला हमारा कृषि प्रधान जिला है और वह सोन नहर के अंतिम छोर पर है, वहां सोन नहर का पानी समय पर भी नहीं पहुंच पाता है । भोजपुर जिला का पूरा इलाका सिंचित नहीं है, कैनाल विभाग अभी कर रहा है । इसलिए हम माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि उस कंपनी को कहकर भोजपुर जिला के, मैं अपने जगदीशपुर निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कह रहा हूं कि उसने 10 परसेंट भी अभी तक काम नहीं किया है । मेरा आग्रह है कि उस काम में वह तेजी लाने का प्रयास करे, सी0एम0डी0 भी सुन रहे हैं । हम तो एक बार एस0सी0 से भी बात किये थे तो उन्होंने कहा कि सर, हम तो कहते-कहते थक गये हैं लेकिन वह सुन नहीं रहा है । उसका कहना है कि उसके पास मैन पावर नहीं है । हम डी0एम0 साहब से मिले थे तो उन्होंने कहा था कि उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाय, सरकार को लिखिये । अब डी0एम0,भोजपुर सरकार को उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेट करने के लिये लिखे या नहीं, एस0 सी0 ने लिखा कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है । उसको ब्लैक लिस्टेड करना है, हटाना या नहीं हटाना है यह सरकार का काम है ।

हम कहना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था कि हर किसान के खेत में पानी देंगे, किसान ने अप्लाई भी किया है, आपका जो सेंटर चलता है वहां किसानों ने रसीद कटाकर अपना दख्र्वास्त भी दे दिया है लेकिन अभी तक हमारे क्षेत्र में 10 परसेंट भी नहीं हुआ है ।

महोदय, प्रायः गांवों में जितने भी पुराने तार है, चाहे वह पिछड़ा, अति पिछड़ा या महादलितों का मुहल्ला हो, सभी माननीय सदस्यगण जानते हैं, यह कोई बनावटी बात नहीं है, सारे तार जर्जर हो गये हैं, लेकिन तार चेंज नहीं किया जा रहा है और न वहां ट्रांसफरमर की कैपिसिटी बढ़ाई जा रही है जिसके कारण शाम में बिजली नहीं रहती है, न तो पंखे चलते हैं और न बल्ब जलता है जिससे वहां के बच्चे पढ़ने से वंचित रहते हैं । इसलिए मेरा अनुरोध है कि जिस गांव में तार बदलने का कार्य लिया जाय तो उस पूरे गांव का तार बदल दिया जाये चाहे जिस समाज का गांव हो, जिस समाज का मुहल्ला हो । उस गांव का पूरा तार बदल दिया जाय और आवश्यकतानुसार वहां ट्रांसफरमर भी दिया जाय और उसके बाद दूसरे गांव को टेकअप किया जाय ।

आज हमने समाचार पत्र में देखा था कि संवेदक जो तार पोल गाड़ रहे हैं, उसमें केवल मिट्टी से भर रह है, न उसमें सिमेंट की मात्रा है और न कंकिट की मात्रा है जिससे आंधी और पानी में सारे पोल हिल गये हैं ।

अभी हमने सभापति जी के गांव के बारे में समाचार पत्र में देखा कि इनके क्षेत्र में भी पोल गिर गया है । पता नहीं सभापति महोदय सरकार से कह पाते है या नहीं । गोपालगंज जिला के बरौली प्रखंड के रतनसराय गांव का मामला हमने आज समाचार पत्र में देखा है कि वहां का पोल उखड़ गया है और एक सप्ताह से बिजली का लाईन बंद है, अभी तक उसको ठीक नहीं किया गया है । इस तरह की बातें हमारे क्षेत्र में भी है। हम ने वहां कार्यपालक अभियंता से कहा है, उन्होंने सुधार करने की बात कही है । आपके यहां मैन पावर की बहुत कमी है।

हमारे वरीय नेता श्री रामदेव बाबू ने कहा कि पहले लाईन मैन घुमता था, अब वह घुमता नहीं है । लाईन कट जाता है तो डायरेक्ट एस0डी0ओ0 से एक्जेक्यूटीव इन्जीनियर से कहना पड़ता है, कनीय अभियंता तो सुनता ही नहीं है। कनीय अभियंता तो अपने मोबाईल को ही स्वीच ऑफ कर देता है । सोचता है कि रात में यह प्रोब्लेम क्यों लिया जाय । जब हमलोग एक्जेक्यूटीव या एस0डी0ओ0 से कहते हैं तभी लाईन सुधरता है । तो इसकी व्यवस्था किया जाय ।

महोदय, हम एक अनूठा केस बताते हैं । हमारे जगदीशपुर में एक सिविल इन्जीनियर की पोस्टिंग हो गयी है आपके विभाग में । वह कैसे हआ है, जाने हुआ है, अनजाने हुआ है, पता नहीं । सिविल एस0डी0आ0 को तो बिजली की जानकारी तो नहीं होगी तो वह काम क्या करेगा ? इस पर ध्यान दिया जाये कि उसकी पोस्टिंग कैसे आपके विभाग में हो गयी । सी0एम0डी0 उसको जगदीशपुर अनुमंडल से हटाकर वहां पर इलेक्ट्रिक एस0डी0ओ0 की पोस्टिंग किया जाय ।

महोदय, आपने वादा किया था लेकिन आप अभी तक कृषि को विद्युत देने के मामलों में पिछड़े हुये हैं । हमारा जिला कृषि प्रधान है । अभी चौसा, बक्सर का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ है और न बांका का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है । जब हमलोग ज्वाइंट सरकार में थे तो हमलोगों से आपने कहा था कि वह एक वर्ष में चालू हो जायेगा लेकिन आपकी स्थिति बहुत कमजोर है ।

महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भोजपुर जिला में किसानों को बिजली उपलब्ध कराया जाय, हमारा जगदीशपुर निर्वाचन क्षेत्र है, बेगपुर नहर का पानी भी अब नहीं आता है । दिसंबर तक कहा गया है, अगर दिसंबर तक भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा है । अभी जो स्थिति है, बारिश हो गयी, खेत में अब तो पोल नहीं गाड़ा जा सकेगा । जून महीने में ही हमने कहा था कि लाईन दे दो नहीं तो बरसात शुरू हो जाययगा तो नहीं हो पायेगा । दो साल से इसी तरह से कह रहा है । लेकिन उस पर ध्यान नहीं है ।

महोदय, विद्युत अधीक्षण अभियंता, आरा भोजपुर ने हमसे कहा है कि कंपनी वाले हमारी बात नहीं मान रहा है, इसके पास आदमी नहीं है जिसके कारण वह काम नहीं कर रहा है । इसलिए हमलोग क्या करें । विद्युत अधीक्षण अभियंता ऐसी बात कहते है कि कंपनी वाले हमारी बात नहीं मानते हैं। अभी दो-चार जगहों पर शुरू भी किया है तो गांव के पार्ट में शुरू किया है, दो-चार लोग जब पेटी कॉनट्रैक्टर से संपर्क करता है तो वह दो-चार किसान को देता है फिर वह उस गांव से चला जाता है । महोदय, हर जगह पोल गिराया गया है लेकिन वह इधर का पोल उधर और उधर का पोल इधर ले जा रहा है । इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है । हमने वहां के लोगों को कहा है कि जिस गांव में पोल गिरा है, उसी गांव में वह पोल गाड़ा जायेगा, दूसरे गांवों में नहीं जायेगा तो अब दूसरे गांव में नहीं जाने दे रहे हैं ।

माननीय मंत्री महोदय हम आपकी प्रशंसा करते हैं, और हमलोग प्रशंसा करेंगे चूंकि आपका विभाग आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ सकता है । इसएिल आप मैन पावर बढ़ाईये । आपके यहां स्टाफ की बहुत कमी है, जुनियर इन्जीनियर भी नहीं है, लाईन मैन भी नहीं है ।

क्रमश :

टर्न-14/अंजनी/15.07.19

श्री राम विशुन सिंह : क्रमश:.... महोदय, आपने कांट्रैक्ट पर स्टाफ को रखा है, वह मोबाईल को स्वीच ऑफ कर देता है, अगर कोई खोजता है तो वह नहीं मिलता है । अगर सरकारी

रहता तो डर रहता कि कहीं उसपर कम्पलेन हो जायेगा तो नौकरी चली जायेगी । रात में लाईन कटता है तो वह सुनता नहीं है । इसलिए सभी समाज के लोगों को आपने बिजली पहुंचाया है लेकिन पुराने तार होने के कारण और बिजली का लोड बढ़ने के कारण दिक्कत हो रही है । ट्रांसफार्मर की कमी के चलते इसपर थोड़ा शिकायत हो रहा है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पुराने तार को बदलें और किसानों को बिजली दें अैर ट्रांसफार्मर आवश्यकतानुसार जितना कंज्यूमर हैं, उसके अनुसार दिया जाय तो इसपर और अधिक सुधार होगा । हम अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बात रखे हैं, वहां मेरे यहां कुछ ट्रांसफार्मर की जरूरत है, एस0ई0 साहेब को कहे तो वे दो ही देते हैं । सिवान को हम भेजवा देते है । जरा इसपर विचार कर लिया जायेगा ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री राम विशुन सिंह : माननीय सदस्यों ने इस सदन में कहा था, यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, आप ही के पक्ष के सदस्यों ने कहा था कि भागलपुर में लाईन नहीं रहता है, नाम नहीं बताते हैं, चूंकि आप सुने होंगे तो जब भागलपुर में लाईन नहीं रहता है तो दूसरे शहर की बात क्या कहा जायेगा । पटना में हमलोग रह रहे हैं, विधान सभा सत्र के चलते हमलोग यहां अभी रेगुलर रह रहे हैं तो देखते हैं कि यहां भी दो-चार घंटा लाईन कट जाता है । महोदय, मेरा कहना है कि पुराने तारों को बदला जाय, बिजली मुहैया करायें और गांवों में ट्रांसफार्मर की उपलब्धता हो, बढ़ाया जाय क्योंकि पहले की अपेक्षा कंज्यूमर बढ़ गये हैं । हर पायदान के लोगों को बिजली की आवश्यकता है और बी0पी0एल0 में जो आपने सीमित किया था कि एक बल्व और एक पंखा चलेगा, उसको सही किया जाय ताकि सबको समान रूप से बिजली मिले।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : जनता दल यूनाइटेड के माननीय सदस्य श्री राजकुमार राय जी ।

श्री राजकुमार राय : सभापति महोदय, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया है । आज मैं बिजली विभाग पर सदन में सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, एक समय था, जब शहरों में ही बिजली देखने को मिलती थी, गांव, देहात और शहर से दूर बसावट के लोगों को बिजली के संबंध में कुछ भी मालूम नहीं था, लोग यही समझते थे कि बिजली सिर्फ बड़े लोगों एवं शहर के लोगों के लिए होता है । पिछले एक दशक से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बढ़ता बिहार, नीतीश कुमार के साथ जब बिहार न्याय के साथ विकास का लक्ष्य पूरा होने लगा तब लोगों में बिजली की समस्या का ध्यान आया और जगह-जगह लोग बिजली की मांग करने लगे । महोदय, उस समय बिहार में बिजली का उत्पादन बहुत कम था । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार को

विकसित करने में बिजली महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए विभागीय तैयारी शुरू किये । बिहार को अपने विद्युत उत्पादन पर जोर दिया गया ? राज्य सरकार द्वारा संक्लपित सात निश्चय में एक हर घर बिजली के तहत राज्य में सभी इच्छुक परिवारों को मुख्यमंत्री विद्युत सम्बद्ध निश्चय योजना जैसे बाद में प्रधानमंत्री सहज बिजली योजना के तहत समाहित कर लिया गया । राज्य में बिजली की अधिकतम आपूर्त्ति अक्टूबर, 2016 में 3769 मेगावाट से बढ़कर अक्टूबर में 4535 मेगावाट हो गया । जो नयी उंचाई को छूते हुए वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर 2018 में बढ़कर 5139 मेगावाट तक पहुंच गया । महोदय, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत प्रतिष्ठान की क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 3345 करोड़ रूपये की योजना से 100 मेगावाट की दो इकाईयां कुल 390 मेगावाट से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दी गयी है । महोदय, नबीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड द्वारा नबीनगर में नये ताप विद्युत केन्द्र 1980 मेगावाट स्टेज फर्स्ट की स्थापना 15,132 करोड़ रूपये की लागत से की जा रही है । महोदय, चौसा, बक्सर में 1332 मेगवाट ग्रीन फील्ड तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु सतलज जल विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है । महोदय, 400 मेगावाट अल्ट्रा मेगापावर प्रोजेक्ट हेतु राज्य सरकार द्वारा बांका जिला में 2440 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है । महोदय, 15 अगस्त, 2012 को स्वतंत्रता दिवस समारोह गांधी मैदान में झंडोतोलन के बाद अपने संबोधन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 2015 तक यदि बिहार के हर गांवों में बिजली नहीं पहुंचाउंगा तो 2015 के विधान सभा चुनाव में वोट मांगने बिहार की जनता के बीच नहीं जाउंगा । बात कुछ कठिन था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इसे चुनौती के रूप में लिया और इसपर काम शुरू हुआ । आज परिणाम सामने हैं । जहां लोग बिजली का नाम भी नहीं जानता था आर आज वहां 18 से 20 घंटा से ज्यादा बिजली आपूर्ति की जाती है । महोदय, इतना ही नहीं बिजली विभाग ही नहीं, शिक्षा विभाग, पथ निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभागों जैसे सभी विभागों पर काम चल रहा है महोदय । बिहार में हमलोग देखे हुए हैं, जब छात्र लाइफ में थे तो हमलोग अपने घर से प्रखंड, अनुमंडल, जिला जाने के लिए सड़क नहीं थी महोदय लेकिन आज आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में लगातार चौतरफा विकास हो रहा है । महोदय, प्रदेश के अन्दर सभी जिला एवं प्रखंडों में...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आपका समय समाप्त हो गया । आपका पांच मिनट समय था।

श्री राजकुमार राय : पंचायत स्तर पर हर घर जल-नल योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिये गये । सात निश्चय योजना के तहत हर घर बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है । महोदय,

आज ग्रामीण क्षेत्र में बिजली से चलने वाली घरेलू योजनायें लगाया जा रहा है, जिससे बेरोजगारी का भी हल हो रहा है । सरकार प्रदेश में अब शीघ्र सौर उर्जा से संचालित विद्युत उत्पादन कर, विद्युत पंप इत्यादि जैसे कार्य करेगी महोदय । महोदय, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ समस्या बताना चाहता हूॅ। महोदय, बिजली पर काफी काम हुआ है लेकिन हमारे हसनपुर विधान सभा क्षेत्र से होकर कई नदियां गुजरती है । मैं सरकार को सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूॅ कि जो नदी के किनारे से इस पार से उस पार बसावट में विद्युत दी जाती है, उसमें मैं आग्रह करूंगा कि नदी के किनारे दोनों ओर पावरयुक्त पोल के माध्यम से विद्युत दिया जाय जिससे कि लोगों की जान बच सके । मेरे क्षेत्र में कई घटनायें हो चुकी हैं, इन्हीं शब्दों साथ आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य जिवेश कुमार जी । आपका पांच मिनट टाईम है ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय,मैं उर्जा विभाग पर विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हूॅ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): आपका पांच मिनट टाईम है ।

श्री जिवेश कुमार : आठ मिनट हमारा समय था ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : कट गया है ।

श्री जिवेश कुमार : महोदय, ठीक है । आसन ने जो समय दिया है, उसका पालन करने का प्रयास करूंगा लेकिन आसन से कुछ मदद की आवश्यकता है । आठ मिनट की तैयारी थी और पांच मिनट में निपटाना होगा । सबसे पहले मैं आसन को धन्यवाद देता हूॅ और जाले की महान जनता को धन्यवाद देता हूॅ कि जिसके कारण मैं यहां खड़ा हूं। कुछ बोलने के लिए अपने नेता को भी धन्यवाद देते हैं । हुजूर, बिजली का, उर्जा का क्या महत्व है हुजूर, आप फट से लाइट जला देते हैं, बिना बोले पहले चेतावनी दे देते है कि अब समाप्त कीजिए । फिर आप हरियरका जलाते हैं और ललका जलाते हैं तो बिजली का महत्व यहीं से शुरू हो जाता है । आसन भी बिजली के प्रयोग के माध्यम से कहता है कि बोलिए और चुप हो जाइए । इसके महत्व को जिन लोगों ने नहीं आंका, एक समय था कि बिजली का तार कपड़ा सुखाने के काम आता था और एक जमाने में बिजली के तार को छूकर पता कर लेता था कि बिजली आयी कि नहीं आयी । अब तो बल्व जलाकर पता किया जाता है कि बिजली कटती ही नहीं है, तब तो पता करने की नौबत नहीं आती है ।

क्रमशः .....

टर्न–15/राजेश/15.7.19

श्री जिवेश कुमार : क्रमशः .. बिजली के तार का एक जमाने में हुजूर, बिजली के तार को काटकर एक जमाने में व्यवसाय चलता था लेकिन अब तो बिजली इतनी रह रही है कि लोग...

(व्यवधान)

श्री कुमार सर्वजीतः महोदय,राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना कब चालू हुआ,इनको मालूम नहीं है ।

श्री जिवेश कुमारः हम बता रहे हैं, आप बैठ जाइये, बैठ जाइये । राजीव गॉधी विद्युतीकरण जब चालू हुआ हुजूर, आदरणीय रामदेव बाबू बोल रहे थे, पुराने पोल पर उसका डब्बा अभी भी कहीं–कहीं लगा हुआ है, हमारे गॉव में हुजूर संडास के लिए उससे बड़ा डब्बा लेकर जाते थे शौचालय, अब तो लोग शौचालय में जाते हैं और जो योजना ये लोग लाये हुजूर, सब में लूट का छूट था, लूटने के लिए योजना बनाये, माल कैसे अपना बने, वह काम किये और जिसने आज बिजली घर–घर पहुंचा दिया, वह भी नीयत समय से पहले, उसके प्रति क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं यहॉ पर खड़े होकर, पर इनपर कुछ कहने के लिए आज मैं खड़ा नहीं हूँ ।

बिजली विकास का प्रथम आयाम है हुजूर और मैं धन्यवाद देता हूँ बिहार सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय उप–मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय बिजली मंत्री जी को, कि जिन्होंने उर्जा के क्षेत्र में माईल स्टोन स्थापित करने का काम किया है और जो इन्होंने वादा किया था, इसके लिए मैं पदाधिकारियों को भी कृतसंकल्पित होकर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो बिहार की जनता से वादा किया था, उससे तीन महीना पहले हर घर बिजली पहुंचा देने का काम किया है । आदरणीय भोला बाबू के क्षेत्र में भी बिजली पहुंच गयी है, हम तो इनके पड़ोसी है, इसलिए जान रहे हैं, ये कटौती प्रस्ताव लाये हैं, यह तो परम्परा है लाने का लेकिन आदरणीय भोला बाबू से पूछियेगा, तो उनके मन में बढ़ोत्तरी प्रस्ताव आ रहा है कि क्यों नहीं इस विभाग का पैसा बढ़ा दिया जाय, ताकि छूटा–फूटा काम भी जल्दी हो जाय, हुजूर मैं धन्यवाद देता हूँ बिहार के बिजली मंत्री को और आदरणीय बिहार के मुखिया को कि जिसने किसानों को भी 75 पैसे यूनिट बिजली देने का वादा किया है और 20 दिसम्बर, 2019 तक कृषि फीडर के माध्यम से हर खेत को पानी देने का वादा जिसने किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, महोदय, बिना बिजली का कोई उद्योग नहीं चल सकता है और अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि पटना में भी बिजली कटता है, तो बिजली का महत्व का पता तो चल रहा है कि कटने पर भी इन्हें बेचैनी हो रही है, आपके जमाने में तो बिजली को आने ही नहीं देते थे कि लालटेन न बुझ

जाय, अब तो बिजली आयी, जैसे-जैसे बिजली बढ़ी, लालटेन बुझती चली गयी, अब तो जय सियाराम, लालटेन की जरुरत ही नहीं है बिहार में हुजूर और हुजूर, जान लीजिये पर्यटन विभाग भी आज है, इसलिए एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करुंगा.....

(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री जिवेश कुमार: हुजूर, एक मिनट । हमारे यहॉ एक पर्यटक स्थल अहिल्या स्थान है हुजूर, हम चाहेंगे कि उसका उचित पर्यटन विकास वहॉ पर हो और हमारे यहॉ एक गोलू झा होते थे, जिनकी लोकयुक्ति आज भी घूमती है, इसलिए आग्रह होगा कि गोलू झा के स्थल को तैयार किया जाय पर्यटक स्थल के रुप में.....(व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आपका समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह जी, 5 मिनट ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, उर्जा किसी भी देश या राज्य की आर्थिक विकास की जरुरत है और सड़क, सिंचाई और बिजली की स्थिति मजबूत होने पर ही किसी राज्य का विकास हो सकता है और इसी महत्व को देखते हुए इस बिजली विभाग को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है । महोदय, 2000 में जब बिहार राज्य का बॅटवारा हुआ, तो दो पुराने पावर प्लांट को छोड़कर सारे के सारे पावर प्लांट झारखंड में चले गये और उस समय बिहार को 90 प्रतिशत बिजली खरीदनी पड़ती थी लेकिन मैं माननीय उर्जा मंत्री एवं प्रत्यय अमृत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने स्थिति बदल दी और आज जो बिजली की स्थिति है, सभी उससे परिचित है और यहॉ तक कि पिक ऑवर में 6000 मेगावाट तक हमारी खपत होने लगी है, यह हमारी विशेषता है, चूंकि मुझे पॉच ही मिनट का समय दिया गया है लेकिन यह बात तो सही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे 88.7 प्रतिशत ग्रामीण आबादी बिहार में है और यह ग्रामीण कृत राज्य बन चुका है पूरे देश के लिए और 89 प्रतिशत आबादी यानि 1.26 करोड़ की आबादी गॉवों में बसती है, तो इस आबादी को बिजली मुहैया करना पड़ता है क्योंकि वहॉ अब तक 90 प्रतिशत लोग आज भी किरासन तेल से काम चला रहे हैं ।

महोदय, ... (व्यवधान)

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): माननीय सदस्य क्षेत्र की समस्या हो, तो बोल दीजिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: हॉ । महोदय, क्षेत्र की समस्या है । क्षेत्र की समस्या यह है कि काम तो ठीक हो रहा है लेकिन इनलोगों के संकल्प से, इनलोगों के कार्य दक्षता से हमारे जो नीचे के पदाधिकारी हैं, वे इन्हें गंभीरता से साथ नहीं दे रहे हैं । मैं इसका एक छोटा सा

उदाहरण देना चाहता हूँ कि दिनांक 13.1.2019 को मैं एक गॉव गया था, गॉव का नाम है भरतकोल, आमदाबाद प्रखंड में पड़ता है, वहॉ के लोगों ने मुझसे कहा कि पोल नहीं है, तो मैंने वहीं से एक्सक्यूटिव इंजीनियर को टेलिफोन किया, तो उन्होंने कहा कि कल पोल गिर जायेगा, मैं बहुत ही प्रभावित हुआ और जनता के सामने बोल दिया कि कल आपलोगों को पोल मिल जायेगा, जब पोल नहीं मिला, एक सप्ताह के बाद, गॉव वालों ने कहा कि पोल कहॉ मिला, तो मैंने फिर उनसे कहा कि भाई पोल नहीं गिरा, जबकि आप बोले थे, तो फिर उन्होंने कहा कि कल पोल चला जायेगा, फिर एक सप्ताह के बाद पोल नहीं आया, तो फिर एक महीना के बाद वहॉ की जनता ने कहा कि पोल अभी तक नहीं आया है और महोदय मैं यह बता देना चाहता हूँ कि अभी तक उस गॉव में पोल नहीं गया, यह इनके कार्य की दक्षता है । सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ गॉव में बिजली नहीं गयी, पोल नहीं गया लेकिन मीटर चला गया, मैं उस गॉव का नाम लेना चाहता हूँ, आमदाबाद प्रखंड में उत्तरी कर्मलापुर पंचायत है एवं प्राणपुर गॉव हैं, वहॉ 150 उपभोक्ता हैं, उसमें 70 उपभोक्ताओं को मीटर चला गया लेकिन वहॉ पर न तो बिजली का पोल गया और न ही तार गया, तो उस मीटर का क्या करेगा बेचारा ?

दूसरी बात यह है कि हमारे यहॉ बिजली जो जाती है, उसको तो मीटर मिलता नहीं है, अगर मीटर मिला और वह खराब हो गया, तो उसे बदला नहीं जाता है और लोगों को सीधे 260 रुपये के हिसाब से ले लिया जाता है और बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा भी है कि इतना मीटर चला जा रहा है लेकिन उसको दिया ही नहीं जा रहा है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब आपका समय समाप्त हुआ । आप लिखकर माननीय मंत्री जी को दे दीजिये ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह: ठीक है । मैं सिर्फ आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी समस्या है जो क्षेत्र की है, अगर उसमें सुधार हो जाय, तो बहुत अच्छा है । मैं माननीय मंत्री जी को लिखित दे देता हूँ । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह): अब राष्ट्रीय जनता दल की माननीय सदस्या श्रीमती समता देवी, 9 मिनट ।

टर्न-16/सत्येन्द्र/15-7-19

श्रीमती समता देवी: सभापति महोदय, आज मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । मैं ऊर्जा और इसके महत्व के बारे में भाषण देने के लिए खड़ी हुई हूँ । बिजली हमलोगों के लिए बहुत मायने रखती है। बिना बिजली के जन जीवन

अधूरा है, बिजली ऊर्जा का शक्तिशाली स्रोत होता है जिसका प्रयोग अनेक कामों में किया जाता है । बिजली आज के दौर में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है । आज के समय में घरों में बिजली का प्रयोग और बढ़ गया है । अगर थोड़ी देर के लिए भी बिजली चली जाती है तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है । महोदय, आज के आधुनिक युग में बिजली मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गयी है जिसके बिना मनुष्य किसी भी काम को करने में सफल नहीं होता है । महोदय, मैं जिस विधान-सभा क्षेत्र से आती हूँ, वह इलाका बहुत ही पिछड़ा इलाका है । राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत वहां गावों में बिजली पहुंचाया जा रहा था लेकिन अभी तक प्रचुर मात्रा में बिजली उपलब्ध नहीं कराया गया है । महोदय, अभी भी ऐसा कई गांव हैं, जहां पोल खड़ा है लेकिन तार नहीं खींचा गया है जिससे अभी भी बहुत लोग बिजली से वंचित हैं और आजादी के सात दशक बाद भी सभी जगह बिजली उपलब्ध नहीं हो सकी है । महोदय, मेरे विधान-सभा क्षेत्र के बाराचट्टी एवं मोहनपुर प्रखंड में 33 हजार के0वी0ए0 का तार करीब 40 कि0मी0 होकर बोधगया से आती है जिस कारण आये दिन, कोई ऐसा दिन नहीं है जब 33 हजार के0भी0ए0 का तार नहीं गिरता हो इसलिए जर्जर तारों का नवीनीकरण किया जाय ताकि समय से सभी जगहों पर बिजली मिल सके । महोदय, बोधगया ग्रिड से 33 हजार के0वी0ए0 के तार को सागरपुर-चोरमनिया होते हुए प्रखंड मोहनपुर के चरकेरिया विद्युत सब-ग्रीड में पहुंचाया जाय और वहां बिजली की समस्या तभी खत्म होगा जबतक वहां एक ग्रिड बनेगा इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि जल्द से जल्द वहां इस कार्य को कराया जाय ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) : आप अपने क्षेत्र की समस्या पर बोलिये ।

श्रीमती समता देवी: मैं अपने क्षेत्र की समस्या पर ही बोल रही हूँ महोदय । आज अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग आबादी के लगभग 35 प्रतिशत हैं लेकिन बजट में मात्र योजना हेतु 1244.89 करोड़ रू0 ही दिया गया है जो काफी कम है । महोदय, एस0सी0/एस0टी0 हेतु योजनाओं की बहुत घोषणा हुई लेकिन उपलब्धि काफी नहीं हुआ है जो एक गंभीर विषय है । सरकार के कमजोर इच्छाशक्ति के कारण आज भी उनका समुचित विकास नहीं हो पा रहा है । महोदय, यू0पी0एस0सी0 पी0टी0 एवं बी0पी0एस0सी0 पी0टी0 पास करने वालों को क्रमश: 1 लाख एवं 5000 रू0 देने की योजना है लेकिन पिछले वर्ष मात्र 46 विद्यार्थी ही इसका लाभ ले सकें जो कि काफी कम संख्या में है । महोदय, बच्चे को बी0पी0एस0सी0/यू0पी0एस0सी0 की तैयारी करने हेतु भी योजना है लेकिन सरकारी उदासीन रवैया के कारण से 07 प्राक परीक्षा प्रशिक्षण

केन्द्रों पर मात्र 1680 विद्यार्थी ही इसका लाभ ले सकें हैं क्योंकि सरकार एस0सी0/एस0टी0 को ठगना चाहती है और जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है । महोदय, एस0सी0/एस0टी0 छात्रों को 15 किलोग्राम अनाज देना था छात्रावासों में रहने वाले छात्र/छात्राओं को जो कि दिसम्बर 2018 से बंद है । उनके लिए मात्र केन्द्र सरकार राज्य सरकार घोषणा करती है लेकिन देती नहीं है । महोदय, 9559 विकास मित्रों को महादलित परिवार के लिए कार्य में लगाया गया है । ये हमारे समाज के पढ़े लिखे बच्चे थे, इसे कम वेतन में आप काम करने को मजबूर कर दिये ताकि आगे बी0पी0एस0सी0 यू0पी0एस0सी0 की परीक्षा नहीं दे सकें इसलिए इनको भी सम्मानजक वेतनमान वाला वेतन दिया जाय । महोदय, एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत उनको जो सहायता मिलती थी उसको या तो कम कर दिया गया या बंद कर दिया गया जो नहीं होना चाहिए था ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह)अब समाप्त कीजिये आप ।

श्रीमती समता देवी: महोदय, मैं एक चीज और कहना चाहती हूॅ कि हमारी सरकार द्वारा बोला जाता है कि लालू जी चारा घोटाला में फंसे हुए हैं । हम कहना चाहते हैं कि सरकार के जितने भी प्रतिनिधिगण या विधायकगण हैं जिसमें एक लालू जी ही है जिन्होंने ने पिछड़ों को, अकलियतों को मान-सम्मान देने का काम किये और कोई ऐसा काम नहीं किया है । आज दलितों को पिछड़ों को, 1990 से पहले बैठने नहीं दिया जाता था। आप जानते होंगे कि भगवती देवी एक अनपढ़ महिला थी जिसे उन्होंने ही पार्लियामेंट में भेजने का काम किया था और आज उनकी बेटी समता देवी आपके आखों के सामने बोलने के लिए खड़ी है और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूॅ ।

सभापति(श्री मो0 नेमातुल्लाह) अब जनता दल(यू0)के माननीय सदस्य श्री बशिष्ठ सिंह जी ।

श्री बशिष्ठ सिंह: महोदय, आज ऊर्जा विभाग के लिए सरकार द्वारा जो बजट पेश हुआ है उसके पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूॅ । महोदय, दो-चार बात बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और आपकी कृपा होगी तो एकाध मिनट बढ़ाया जा सकता है। महोदय, अपने माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिजली मंत्री आदरणीय विजेन्द्र बाबू उन्हें पूरे हृदय से आभार प्रकट करता हूॅ कि इनलोगों ने बिहार में विकास का काम किया और बिजली विभाग में जो काम हुआ इसका कोई जवाब नहीं है। महोदय, बिजली की स्थिति में राज्य में उत्तरोत्तर सुधार होता रहा है और तेजी से हो रहा है और आगे भी होने की संभावना जारी है । महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि विपक्ष के तरफ से जो बातें आ रही थी, वर्ष 2005 में बिहार में 700 से 800 मेगावाट बिजली मिलती थी और आज 2018-19 में 5600 मेगावाट बिजली हमारी

सरकार व्यवस्था कर बिहार को समर्पित कर रही है । यह अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है महोदय, जहां 7 सौ होता था वहां आज 5600 हो रहा है और अगर इसकी तुलना की जाय तो मैं समझता हूँ कि आज से पहले वाली जो सरकार थी उसकी तुलना अगर हमारी इस सरकार से की जाय तो धरती आसमान के फर्क का अन्तर पड़ेगा । महोदय, मैं यह आपको बतलाना चाहता हूँ , 88 अरब 94 करोड़ 31 लाख 85 हजार का यह बजट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बजट है और बिजली विभाग के ऊर्जा का महत्व आज के परिवेश में उतना है जितना इस शरीर को जीने के लिए, चलने के लिए, खून की जरूरत होती है, शरीर में खून का संचार जितना तेजी से होता है उसी तरह बिजली का भी संचार उतना ही तेजी से होगा तब समझिये कि इस बिहार का विकास तेजी से होगा और बिहार हिन्दुस्तान के प्रथम राज्य में स्थापित होगा । महोदय, हर घर बिजली की व्यवस्था सरकार ने अपने सात निश्चय के माध्यम से घोषणा किया था और दिसम्बर, 2018 से 2 माह पहले, 25 अक्टूबर को ही, इसके लिए हम बिहार सरकार और बिहार सरकार के पदाधिकारी को बधाई देना चाहते हैं, बिजली विभाग के सी0एम0डी0 प्रत्यय अमृत साहब को भी और अन्य उनके जो पदाधिकारी हैं उनको भी कि दो महीना पहले ही बिहार में हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया गया और इसके लिए उनको पुरस्कार भी सरकार की तरफ से मिला । महोदय, इतना ही नहीं, आज हर घर में नल का जल जो लोगों में पीने के पानी की समस्या बनी हुई है, अगर नल का जल भी गांव में लोगों को दिया जा रहा है तो बिजली से ही उस पम्प से पानी निकालकर गरीबों के घरों में, मुहल्लों में पानी देने का काम हो रहा है। महोदय, इतना ही नहीं, जो हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य कह रहे थे कि क्या पुराने बिजली का तार बदल पायेंगे तो हम उनको दावे के साथ कहना चाहते हूँ कि 2019 के लास्ट तक, दिसम्बर, 2019 तक सभी जगह बिजली का तार बदल दिया जायेगा, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ । महोदय, किसान के सवाल पर विपक्ष के लोग पूछ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के भाईयों से कि लालू जी के शासन में क्या होता था, कहीं बिजली नहीं थी तो कहीं ट्रांसफर्मर नहीं था जो तार लटका हुआ था उसको भी चोर तार काटकर के चले जाते थे और ट्रांसफर्मर कहीं जल जाता था तो 6 महीना पर भी ट्रांसफर्मर नहीं बदला जाता था और आज हमारी सरकार ने एलान कया कि कहीं भी ट्रांसफर्मर अगर जल जायेगा तो 24 घंटे के अन्दर हम उस ट्रांसफर्मर को चेंज कर देंगे । यह नीतीश कुमार जी की सरकार ने काम किया है, इतना ही नहीं इस हिन्दुस्तान के पैमाने पर आज बिजली विभाग में सबसे कम दर पर किसानों को बिजली देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वह हमारा बिजली विभाग किया है, 0.75 मात्र प्रति यूनिट की

दर से हमारा बिजली विभाग ने लोगों को यहां के किसानों को बिजली देने का काम किया है कृषि के लिए और इतना ही नहीं महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि बिजली बिल में जो त्रुटि की बात विपक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे सर्वजीत बाबू, त्रुटि पहले बहुत थी लेकिन अब त्रुटि में काफी सुधार हुआ है, आप ईमानदारी से कलेजा पर हाथ रखकर अगर पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले से और आज में बहुत परिवर्त्तन हुआ है । (क्रमशः)

टर्न-17/मधुप/15.07.2019

...क्रमशः..

श्री वशिष्ठ सिंह : आगे परिर्वतन करने के लिए भी कई तरह की योजनाएँ चलाई जा रही हैं । हर घर में प्रीपेड मीटर लगाने की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है और 15 अगस्त, 2019 तक हर घर में प्रीपेड बिजली का मीटर लगाकर हमलोग बिजली बिल के भुगतान करने में सुधार करेंगे ।

इतना ही नहीं महोदय, आज पर्यावरण पर समस्या है, संकट है जिसके लिए हमलोगों ने सेन्ट्रल हॉल में सभी पार्टी के लोगों ने बैठकर विमर्श किया है, 9-10 घंटा हमलोगों ने विमर्श किया है । यह एक सराहनीय काम है कि बिहार की भलाई के लिए, बिहार के हित के लिए जरूरत पड़ता है तो हमलोग एक हो जाते हैं, इसके लिए हम सदन के के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहते हैं । लेकिन महोदय, मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि उस पर्यावरण पर भी बिजली विभाग काम कर रहा है ताकि पर्यावरण दूषित न हो । इसके लिए सौर ऊर्जा के माध्यम से भी सरकार बिजली का कनेक्शन देने का काम कर रही है । सोलर पम्प योजना पर भी काम किया जा रहा है और इसके लिए अब तक बिहार के 50 हजार घरों को सौर ऊर्जा से रौशन किया जा रहा है । यह हमारी सरकार काम कर रही है । पहले में और आज में क्या अन्तर है, यह छुपी हुई बात नहीं है । आपके माननीय सदस्य लोग बोल रहे थे कि हम बिहार सरकार की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करनी पड़ेगी, बिना प्रशंसा किये हुये आपका जान नहीं बचेगा । अगर प्रशंसा नहीं कीजियेगा तो जैसे 40 में 39 सीट बिहार की जनता ने हमको देने का काम किया है और लालटेन छाप का खाता नहीं खुला है, वैसी ही स्थिति आपको फिर आगे बनेगी ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : महोदय, एक मिनट । क्षेत्र की कुछ बात रखना चाहता हूँ । महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ....

श्री सत्यदेव राम : महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूँ ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : क्या व्यवस्था है ?

श्री सत्यदेव राम : सरकार की नीति के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि बोलेंगे तो उसमें कमियों और त्रुटियों....

श्री बशिष्ठ सिंह : महोदय, ये लोग क्या बोलेंगे ? इनलोगों के पास कुछ बोलने को नहीं है । इनलोगों का आगे भी खाता खुलने वाला नहीं है ।

हम अपने क्षेत्र के बारे में कहेंगे कि मेरा रोहतास जिला तीन पंचायत करगहर ब्लॉक का, रीवां पंचायत, बख्शरा पंचायत और भोखरी पंचायत, ये कैमूर जिला से सटे हुये भाग हैं, इसमें कैमूर से बिजली सप्लाई किया जाता है । हम मॉग करना चाहते हैं कि इसकी सप्लाई रोहतास जिला के करगहर से किया जाय । कोचस के गारा पंचायत को बक्सर से हटाकर रोहतास से किया जाय । हम यह मॉग करना चाहते हैं । महोदय, अभी एक बात और बताने में खुशी है कि जब से मैं चुनाव जीतकर आया हूँ, 3-3.5 साल हुआ है, 4 पावर सबस्टेशन हमारे क्षेत्र में लगा है और कुछला पावर सबस्टेशन में थोड़ी धीमी गति से काम हो रहा है । हम चाहेंगे मंत्री महोदय से कि उसको भी तेजी से काम कराया जाय और हर किसान को बिजली की सुविधा मुहैया करायी जाय ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप समाप्ति करिये । भा0ज0पा0 की माननीय सदस्या श्रीमती गायत्री देवी ।

श्री बशिष्ठ सिंह : बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्रीमती गायत्री देवी : सभापति महोदय, मैं आग्रह करूंगी कि हमलोगों को, यानी महिला को दो मिनट ज्यादा बोलने का मौका मिलना चाहिये । 5 मिनट में आदमी कुछ बोल नहीं पाता है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : 5 मिनट आपका समय है, बाकी सदस्यों का समय है ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, मैं 2019-20 के लिए पेश ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ी हूँ । आज मुझे खुशी हो रही है कि आपने मुझे ऊर्जा विभाग के अनुदान मॉग पर बोलने के लिए समय दिया है ।

माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार एवं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के कुशल अगुवाई में लालटेन युग समाप्त हो गया है । बिहार का गॉव भी आज बिजली की रोशनी से दीवाली की तरह जगमग हो गया है । महोदय, गॉव में शादी-विवाह के समय रात में जब हमलोग जाते थे तो दूर से ही पता चल जाता था कि शादी कहॉ हो रही है, क्योंकि एक ही जगह रोशनी रहती थी । अब तो पूरा गॉव बिजली की रोशनी से चकाचक रहता है, विवाह स्थल खोजना पड़ता है । यह कमाल श्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने कर दिखाया है । इस तरह के कार्य से नई

पीढ़ी को आत्मविश्वास आया है कि बड़ा से बड़ा काम किया जाता है, इसका लाभ आने वाली नई पीढ़ी को भी मिलेगा ।

महोदय, राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए बिजली उप केन्द्र एवं अलग से फीडरों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है । साथ-ही, किसानों के लिए तेज गति से मीटर से जोड़कर बिजली खेतों तक पहुँचायी जा रही है । 31 दिसम्बर, 2019 तक सभी इच्छुक किसानों के बोरिंग तक बिजली पहुँचा देने का सरकार का संकल्प है । सीतामढ़ी जिला में यह काम पहले ही हो जायेगा । इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित 258 उप केन्द्रों में से 86 तथा निर्माणाधीन 638 अलग से फीडरों से 400 से अधिक का काम पूरा किया जा चुका है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अन्तर्गत मीटरयुक्त निजी एवं सरकारी नलकूपों के लिए बिजली शुल्क का दर 75 पैसे प्रति यूनिट तथा मीटररहित निजी नलकूपों का बिजली शुल्क का दर 84 रू0 प्रति एच0पी0 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है । अबतक इस योजना से 38,235 से अधिक बिजली संबंध दिये जा चुके हैं । महोदय, सरकार द्वारा राज्य के 71,672 सर्किट कि0मी0 खराब एवं जर्जर तारों को बदलने का कार्य तेजी से चल रहा है । अबतक 5,820 सर्किट कि0मी0 जर्जर तारों को बदला जा चुका है । महोदय, राज्य सरकार के द्वारा हर घर बिजली योजना के तहत राज्य के सभी इच्छुक परिवारों को मुख्यमंत्री विद्युत संबंधन योजना जिसे बाद में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य में समाहित कर लिया गया, के तहत दिसम्बर, 2018 तक बिजली से जोड़ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे दो माह पूर्व ही पूरा कर दिया गया है । सभी घरों को बिजली से जोड़ने में बिहार देश का आठवाँ राज्य बन गया है । महोदय, इस योजना के तहत 39,073 राजस्व गाँव एवं 1,06,828 इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन प्रदान कर दिया गया है । 32,49,828 परिवारों तक बिजली कनेक्शन 2018 में ही पहुँचा दिया गया है ।

बिजली विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी के कुशल नेतृत्व में बिजली विभाग बिहार को रौशन करने में दिन-रात लगा है । मैं उनको एवं उनके विभाग के समस्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी को धन्यवाद देती हूँ । हर महीने, दो महीने पर खुद सी0एम0डी0 पूछते हैं कि विधायक जी, आपके क्षेत्र में कोई कठिनाई है तो बोलिये, खोजने से भी कोई गाँव या टोला नहीं मिलता है जहाँ बिजली नहीं लगी हो । मेरे जिला में 22-24 घंटे बिजली रहती है । महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि सीतामढ़ी में 400 के0वी0 का नया पावर ग्रीड का शिलान्यास आपने सीतामढ़ी में

किया है जिससे सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, मधुबनी, दरभंगा एवं नेपाल को इसका लाभ मिलेगा । महोदय, अभी जो लोक सभा का चुनाव हुआ है इसमें गॉव के गरीब, किसान, मजदूर ने गैस, शौचालय एवं बिजली के काम के कारण लोगों ने एन0डी0ए0 को भारी वोट देकर लालटेन युग का हमेशा-हमेशा के लिए खात्मा कर दिया है ।

महोदय, सरकार द्वारा मॉ जानकी के जन्मस्थली पुनौरा धाम, सीतामढ़ी में रामायण परिपथ के अन्तर्गत पर्यटन को बढ़ावा के लिए विकास का कार्य भी किये जा रहे हैं । सरकार द्वारा राजगीर एवं बॉका के मंदार हिल में रोपवे का निर्माण कराया जा रहा है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त करिये ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, एक मिनट ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : एक मिनट में समाप्त करिये ।

श्रीमती गायत्री देवी : महोदय, राज्य सरकार द्वारा मुँगेर में ऋषिकुंड और गया में महाबोधि कल्चरल सेन्टर का निर्माण का भी काम किया जा रहा है इससे 2500 की क्षमता का मुख्य हॉल सहित 500 क्षमता का बहुद्देशीय हॉल एवं अन्य सुविधाओं का निर्माण कराया जा रहा है। महोदय, राज्य सरकार के द्वारा स्वदेश योजना के तहत प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के अन्तर्गत जैन परिपथ, कॉवरिया परिपथ और गॉधी परिपथ एवं मंदार परिपथ तथा अन्य प्रदेश परिपथ विकास के लिए कार्य कराया जा रहा है ।

महोदय, सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत बी0पी0एस0सी0 पी0टी0 एवं यू0पी0एस0सी0 पी0टी0 के पास होने वाले छात्र-छात्राओं को आगे की तैयारी के लिए क्रमशः 50 हजार एवं 1 लाख रू0 तक की राशि दी जा रही है । अब तक यू0पी0एस0सी0 की पी0टी0 के 46 एवं बी0पी0एस0सी0 पी0टी0 पास करने वाले 387 छात्रों को इसका लाभ दिया जा चुका है ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त करिये ।

टर्न-18/आजाद/15.07.2019

श्रीमती गायत्री देवी : आग्रह करती हूँ एक मिनट । आज जो है बिजली पर चर्चा है, ऊर्जा पर चर्चा है। कल कोई माननीय सदस्य बोल रहे थे, दिल पर हाथ रखकर सारे माननीय सदस्य बोलिए कि आपलोग कभी ए0सी0 में सोते थे, आज सभी आदमी गांव में भी ए0सी0 में सोता है । यह किनका दिया हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ है । पहले लोग बल्ब नहीं देखते थे, ढिबड़ी से काम चलाना पड़ता था, लेकिन अब ढिबड़ी की

सरकार नहीं है, बल्ब की सरकार है । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : सुश्री पुनम पासवान जी । आपको 4 मिनट ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : सभापति महोदय, आज कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और सरकार के विपक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ ।

आज बिजली की चर्चा है, खासकर देश में जब यू0पी0ए0 की सरकार में आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनके अगुवाई में पूरे देश में और खासकर के बिहार में जो बिजली की समस्या धीरे-धीरे समाप्त हो रही है । कहीं न कहीं हमारी कांग्रेस और यू0पी0ए0 सरकार की देन है । राजीव गॉधी विद्युतीकरण का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना रखा गया है । साथ-साथ आज समस्यायें निश्चित तौर पर है, जो आज कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आप आज भी कह रहे हैं गांवों में, घरों में कि आज भी 60 साल पहले के बिजली के तार पड़े हैं, जिन्हें बदलने की जरूरत है । यानी 60 साल पहले बिजली की तार लगी हुई नजर आती है । आज तार बदलने की जरूरत होती है, तभी तो आप बदल रहे हैं, जब 60 साल पहले भी काम किया गया है । साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि बिजली की समस्या आज दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है क्योंकि 60 साल पहले और आज हमलोग 21वीं सदी में चल रहे हैं तो साथ-साथ यह समस्या है कि पुराने तारों की बदलने की जरूरत है । नये तार लगाने का काम चल रहा है लेकिन हमारे विधान सभा में तार बदलने के बारे में हम समझते हैं कि हमारे एरिया में बहुत पीछे चल रहा है । कम से कम मात्र 7 प्रतिशत अभी काम हुआ है । आज बिजली की समस्या हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, कल भी 24 घंटे बिजली कटी रही हमारे विधान सभा कोढ़ा में । मैं यह कहना चाहती हूँ कि आखिर कमी कहां है ? हमें बिजली कभी पूर्णिया से लेना पड़ता है, कभी कटिहार से लेना पड़ता है । हमारे यहां एक पावर हाऊस की जरूरत है, वह स्वीकृति के लिए आया हुआ है और दो साल से यहां पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक पावर हाऊस की स्वीकृति नहीं मिली है, जिनके कारण मेरे क्षेत्र में बिजली की समस्या अभी तक ज्यो की त्यों पड़ी हुई है । साथ-साथ हमारे यहां कोढ़ा प्रखंड के अन्तर्गत बिनोदपुर पंचायत में संथाली टोला है, आज तक वहां बिजली नहीं पहुँची है, जो दो नम्बर वार्ड है । वहां पर बिजली की जरूरत है, साथ-साथ जिस तरह से ट्रांसफर्मर लगाया गया है और जितना ट्रांसफर्मर है, वहां पर कंज्यूमर के अनुसार अभी भी व्यवस्था नहीं हो पायी है, जिसके कारण बिजली की वोल्टेज आज भी कम है। उसको बढ़ाने के लिए जिस तरह से जितने कंज्यूमर हैं, उतने ट्रांसफर्मर की

आवश्यकता है, उस जगह पर ट्रांसफर्मर देनी चाहिए, जिससे कि सही ढंग से बिजली मिल पाये । साथ-साथ यह भी बहुत बड़ी समस्या है कि प्रखंडों में हमारे कई माननीय सदस्यों ने रखने का काम किया। जे0ई0 जो ब्लॉक स्तर पर रहते हैं, वे बात तक नहीं करते हैं, चाहे माननीय सदस्य हों, चाहे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था से जुड़े सदस्यगण हो, उनसे भी बात करना पसंद नहीं करते हैं । हमलोग डायरेक्ट एजक्यूटिव इंजीनियर और असिसटेंट इंजीनियर से बात करते हैं तब भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पाता है । यह बहुत बड़ी समस्या है हमारे प्रखंड के स्तर पर ।

सभापति महोदय, पर्यटन विभाग के संबंध में कहना चाहती हूँ कि हमारे मनिहारी प्रखंड में एक गोगा झील है, इसमें बाहर से पंक्षी प्रत्येक साल आते हैं । हम चाहते हैं कि मनिहारी प्रखंड में जो गोगा झील है, उनको पर्यटक स्थल बनाया जाय क्योंकि उस एरिया के लोग जो नये वर्ष में .....

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : जी, सर एक मिनट । उस एरिया के लोग नये वर्ष में जो फेस्टिवल मनाते हैं वह उसी जगह पर जाकर मनाया करते हैं । साथ-साथ निबंधन का कार्यक्रम है, सरकार ने जो 100रू0 में निबंधन का रखा है, मैं उनमें एक बदलाव चाहती हूँ । अभी हाल में हुजूर कि मध्यप्रदेश में यह लागू किया गया है कि जिस समय अगर निबंधन विभाग से जमीन रजिस्ट्री होता है तो उसी समय वहां एक सी0ओ0 का कार्यालय भी निबंधन ऑफिस के बगल में होनी चाहिए जो रजिस्ट्री होती है ताकि उसकी कॉपी वहां चली जाय और जमाबंदी रजिस्ट्री के साथ-साथ दो दिनों के अन्दर में हो जाय, तब हम समझते हैं कि जो कर्मचारी के द्वारा दोहन किया जाता है, उससे आम जनता, आम लोग प्रभावित होते हैं, उससे आज जनता प्रभावित नहीं हो पायेगी ।

सभापति महोदय, मैं एक मिनट समय लेना चाहती हूँ । खासकर दलितों के लिए जो अत्याचार अधिनियम है, उनको लोगों ने कुचलने का काम किया राजनीति के तहत । आज दलित पूरे बिहार में परेशानी झेल रहे हैं चाहे नवगछिया की घटना हो, चाहे खगड़िया की घटना हो, चाहे बिहार की कोई भी ऐसी स्थल की घटना हो,

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिए ।

सुश्री पुनम कुमारी उर्फ पुनम पासवान : हुजूर मैं बताना चाहती हूँ कि आज सरकार दलित अत्याचार अधिनियम को कुचलने का काम किया है और साथ-साथ इस दलित की अत्याचार अधिनियम को लागू करने में काफी परेशानी होती है । आज एस0सी0/एस0टी0 थाना है, लेकिन आज कितना एस0सी0/एस0टी0 थाना में केस दर्ज होती है, लोग थक जाते हैं, जबतक लोग कोर्ट का दरवाजे नहीं खटखटाते हैं, तब तक एस0सी0/एस0टी0 के लोगों

का केस दर्ज नहीं होता है । चाहे महिला थाना ले लीजिए, उनकी भी वही हालत है । अगर महिला थाना जायं तो 10 दिनों तक, 5 दिनों तक किसी का केस दर्ज नहीं होती है । यह हमारी हालत है । उसे सुधारने की जरूरत है । आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत, बहुत धन्यवाद देती हूँ ।

सभापति(श्री मो0 नेमतुल्लाह) : राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्य श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव जी । 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : धन्यवाद सभापति महोदय । आसन के प्रति एवं अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ ।

महोदय, मैं बहुत देर से सदन के सदस्यों का ऊर्जा विभाग के वाद-विवाद पर, अनुदान मांग पर बहस में कई सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की और ऊर्जा विभाग के जो बढ़ते कदम हैं, वह कहीं न कहीं अपनी राय व्यक्त की है । आदरणीय विजेन्द्र बाबू को आभार व्यक्त करता हूँ, स्वाभाविक तौर पर और इसलिए करता हूँ कि वे काम अच्छा करते हैं, लगन से करते हैं और दूरदर्शिता के साथ करते हैं, इस बाबत भी इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । लेकिन कुछ सदस्य मौकापरस्ती के हिसाब से आ गये हैं, उनके कुछ जो विचार आये हैं, उन विचारों पर अपनी प्रतिक्रिया न दूं तो मुझे लगता है कि सदन में होने के औचित्य पर भी सवाल खड़ा हो जायेंगे ? 2015 में जब निर्णय हुआ था सात निश्चय का तो निश्चय में था एक निश्चय कि बिजली हर घर को बिजली दी जायेगी । मुझे याद है 2015 के चुनाव में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बिजली मिली, बिहार के लोगों से कहा था, याद करिए बिजली मिली तो बिहार के लोगों ने इस बात को स्वीकारा कि नहीं प्रधानमंत्री जी, आपके मुखारबिंद से निकला हुआ शब्द बिल्कुल मिथ्या है, बिहार को बिजली मिली है और महागठबंधन को सशक्त बहुमत देने का काम किया । उसमें हमारी भी भूमिका है, उस भूमिका से हम अपने आपको कभी अलग नहीं रख सकते हैं । लोग पूछ रहे थे कि क्या विजेन्द्र बाबू को आप बधाई दे रहे हैं तो रहस्यरहित बधाई नहीं था, रहस्यसहित बधाई था, इसलिए मैंने उनको बधाई देने का काम किया । आदरणीय महोदय, हम ऊर्जा विभाग के सवाल पर पूरे देश में, पूरी दुनिया में 2004 में इकॉनोमी बुम हुआ, सब जानते हैं, हर राज्यों ने उसका उपभोग किया बी0आर0जी0एफ0 से फंड मिला, करीब 25000 करोड़ रू0 का फंड बना, जब 2004 में यू0पी0ए0 गवर्नमेंट बनी, उसमें बिहार भी राज्य का हिस्सा है । संघीय व्यवस्था में राज्यों का भी अपना अधिकार है, उसका फायदा राज्यों को मिला । उसका उपभोग, उसका सही उपभोग बिहार की सरकार ने

किया । बिजली के क्षेत्र में आगे बढ़े, लेकिन बिजली तापयंत्र, जितने भी ग्रीड हैं, उसको बढ़ाने का काम यू0पी0ए0 गवर्नमेंट ने किया । आदरणीय विजेन्द्र बाबू बैठे हुए हैं, शिंदे साहेब के योगदान को कोई नकार नहीं सकता । ये अपने स्वयं भाषण में कहेंगे कि शिंदे साहेब ने जो योगदान दिया, चाहे वह बाढ़ का तापगृह हो, चाहे वह नवीनगर का सवाल हो, जितने भी तापगृह हैं बिहार के अन्दर में, उसमें इनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता । स्वाभाविक तौर पर बिजली के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, हर घर तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य था, उसको हम प्राप्त करने का काम किया लेकिन कुछ चीजें हैं जो आज भी चर्चा होती है । कई माननीय सदस्यों ने सी0एम0डी0 साहेब की भी चर्चा की है, इसमें सबकी कलेक्टीव रिसपौंसबीलीटी होती है गवर्नमेंट की ।

..... क्रमशः .....

टर्न-19/शंभु/15.07.19

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : क्रमशः....जितने भी इसमें हैं चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वह पॉलीटिकल पर्सन्स हो सबकी अपनी कलेक्टिव रेस्पोन्सबिलिटी है- स्वाभाविक तौर पर कलेक्टिव रेस्पोन्सबिलिटी के आधार पर कलेक्टिव उनको बेनिफिट भी मिलेगा, लेना पड़ेगा उनको, श्रेय भी लेना पड़ेगा, लेकिन जहां कहीं हमारी खामियां हैं उन खामियों पर हमको गौर करना पड़ेगा । महोदय, जो सबसे बड़ी समस्या प्रतिदिन का सवाल है वह बिजली बिल का है । जो बिजली बिल का भुगतान होता है उसमें कई तरह की विसंगतियां हैं जिन विसंगतियों से मुझे लगता है कि कोई प्रतिनिधि इस सदन में बैठा हुआ होगा तो निश्चित तौर पर उससे रूबरू होकर अभियंताओं को फोन करके कहना पड़ता होगा कि रेवेन्यु का जो पक्ष देखने वाला अभियंता है, इसमें कहीं न कहीं दिक्कत है । उसको कहीं न कहीं निर्मूल करना पड़ेगा और निर्मूलता हमको खोजना है तो हमको सशक्त होना पड़ेगा । एक बात मैं दावे के साथ कहता हूँ आदरणीय विजेन्द्र बाबू सदन के अंदर बैठे हैं । इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो कंट्रेक्टर हैं, जो बड़े बाहर के लोग हैं, एक बात संक्रमण काल है । यहां जो पदाधिकारी दीर्घा में सी0एम0डी0 साहब बैठे हैं, हमलोगों से भी अच्छे संबंध हैं । हमको लगता है कि ऐसे ये स्मार्ट पदाधिकारी हैं कि सब इनकी प्रशंसा करते हैं, अच्छा काम करते हैं । सब प्रशंसा करते हैं, इसलिए कि जो काम अच्छा करता है वैसे व्यक्ति का सब प्रशंसा करता है ।

(व्यवधान)

विनोद जी, अभी तो आप बालू के दुख से दुखी हैं । सुनिये न पहले मेरी बात । आप सुनिये न पहले । हमने जो बात कहा यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं कह रहे हैं हम

आम अवाम के सवाल पर कह रहे हैं- निचले अधिकारी की बात अगर आपका कंट्रेक्टर नहीं सुनता है तो कहीं न कहीं संक्रमणकाल है बिजली विभाग के अंदर यह बात समझनी पड़ेगी । हम तत्परता के साथ तार-पोल बिछा रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी जो दीर्घकालीन अगर न हो हमारी योजना तो स्वाभाविक तौर पर सवाल खड़े होंगे । अगर हल्की सी या तेज आंधी आती है तो हमारा पोल यदि टेढ़ा हो जाय तो स्वाभाविक तौर पर सोचना पड़ेगा ।

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त करें ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, एक मिनट, हम कन्कलुड करते हैं । मैं दो-तीन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा माननीय मंत्री जी का और बैठे हुए पदाधिकारियों का कि सबसे पहले आपको एक काम करना होगा आप दे रहे हैं किसानों को खेत तक पहुंचा रहे हैं- अच्छा निर्णय है पहले ही निर्णय हुआ था 2015 में अभी जो गाल बजा रहे हैं न, डेन्ट पेन्ट लगाकर के वह सब चलनेवाला नहीं है, बहुत जल्दी उतरता भी है और चढ़ता भी है । इस देश ने कई उतार चढ़ाव देखा है, ऐसा नहीं है अर्श पर भी देखा है, फर्श पर भी देखा है, इस मुगालते में नहीं जीना चाहिए राजनीति में रहनेवाले लोगों को । हम कभी प्रशंसा भी करते हैं, आलोचना भी करते हैं दोनों चीज करते हैं, लेकिन लोकतंत्र का यही तकाजा है कि कभी उधर आप कभी इधर हम । यही तो लोकतंत्र का तकाजा है, लेकिन सबसे बड़ी बात इस खूबसूरती को समझने के पहले एक बात मानना पड़ेगा कि वर्ष 2004 में बीमारू राज्य की श्रेणीा में गुजरात था और 2004 के बाद इकॉनोमी बूम के सवाल पर माननीय मनमोहन सिंह की इच्छाशक्ति को कोई नकार नहीं सकता है जिसने देश में कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया । उसका फायदा किसी ने ज्यादा लिया, किसी ने कम लिया । जिसके अंदर स्किल था वह ज्यादा ले लिया, जिसके अंदर स्किल कम था उसने कम लिया, लेकिन देश के सभी राज्यों को लाभ मिला है । आदरणीय मंत्री महोदय, समय हमारा थोड़ा कम है, लेकिन एक बात और सबमिट करके हमारे क्षेत्र का मामला है और ध्यान आकृष्ट इसलिए करता हूँ कि माननीय हरिनारायण बाबू भी बगल में बैठे हैं, हमारे नेता भी हैं वहां पर एक पंचायत है अरौत और गांव है बिरनामा वहां पर सब स्टेशन बनाने के लिए प्रस्ताव गया था, प्रस्ताव नीचे से बना भी था, लेकिन अभी तक मूर्त रूप नहीं दिया गया है । यह केवल मेरा ही नहीं हरिनारायण बाबू का भी मामला है और ज्वाइंट मामला है । महोदय, इसलिए प्रायोरिटी पर उसको प्रत्यय अमृत जी लेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर क्वालिटी और कंट्रेक्टर पर नकेल और राजस्व पर कहीं न कहीं अंकुश लगाने पड़ेंगे जो विपत्र ज्यादा आता है बिजली बिल का इसपर हर व्यक्ति इन

चीजों में आप सुधार कर लेंगे तो एक लंबी जो छलांग आपने लगाया है ऊर्जा के क्षेत्र में वह स्वाभाविक तौर पर होगा । बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति(मो0 नेमतुल्लाह) : सी0पी0आइ0एम0एल0 के माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ । दूसरी बात है कि जो बिल बढ़ाकर देता है उसका निदान आसानी से नहीं होता है एक्सक्यूटिव के यहां, एस0डी0ओ0 के यहां गरीब लोग दौड़ते रह जाता है ।

सभापति(मो0नेमतुल्लाह) : सुदामा प्रसाद जी, आपका दो मिनट समय है ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने बोलने का मौका दिया । मुझे तीन बातें कहनी है । पहली बात यह कि जितना दावा किया जा रहा है कि बिजली हम घर-घर पहुंचा दिये हैं और अगर टेक्नीकल कारण से बिजली कटती है या बारिश आंधी की वजह से तो हम समझते हैं कि अभी यह विभाग उतना सक्षम नहीं हुआ है कि वह कम से कम समय में बिजली की बहाली कर दे । 13 तारीख को मैं आरा गया था 8 बजे रात से जो बिजली कटी 10 बजे तक मैं आरा में था लेकिन बिजली नहीं आई तो क्या मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि यह बिजली विभाग का फेल्योर है । तत्काल कम से कम समय में बिजली की बहाली हो यह चुनौती है बिजली विभाग के सामने । दूसरी बात छः महीना से हम अधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि फलाना गांव में, महादलित मुहल्ले में ट्रांसफार्मर नहीं है, लेकिन लगता है कि अधिकारी इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देते हैं । हमारे विधान सभा में सहार प्रखंड का गांव गुलजारपुर, अमरूआ, धर्मपुर इसी तरह से दर्जनों गांव है विधान सभा में तो मैं आग्रह करूँगा कि अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाय । तीसरी बात बिजली बिल को लेकर खरांव गांव है, वहां पर महादलित मुहल्ले में एक-एक व्यक्ति को 10 हजार, 12 हजार का बिल एक महीने का आया है । इसमें सुधार हो और ये पूरे बिहार का मामला है, कोई यहां का नहीं है । पिछले साल पर्यटन विभाग ने देव को पर्यटक स्थल घोषित किया था, लेकिन अभी तक इस दिशा में वहां कोई काम नहीं हो रहा है । मैं आग्रह करूँगा माननीय मंत्रीजी से कि इस दिशा में वे तेजी से काम आगे बढ़ायें । धन्यवाद ।

सभापति(मो0नेमतुल्लाह) : धन्यवाद सुदामा जी । अब जनता दल युनाइटेड के श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी 5 मिनट टाइम है आपका ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : माननीय सभापति महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के द्वारा जो सदन में अनुदान मांग प्रस्ताव लाया गया है मैं उस प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आपके द्वारा जो मुझे समय दिया गया है आसन के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। महोदय, बिजली बुनियादी और मानवीय आवश्यकता है- आर्थिक विकास में तेजी लाने

के लिए, रोजगार सृजन करने के लिए, गरीबी निवारण और मानव विकास में बिजली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है । आज मनुष्य के जीवन का अंग बन गया है बिजली । माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया- यशस्वी बिहार, ऊर्जान्वित बिहार वह सफल हो गया । आज हर घर को बिजली मिल रही है चाहे दूकान हो या प्रतिष्ठान चकाचक रौशनी से चमक रही है, घर हो या बथान, हर किसान के खेत हो या खलिहान या गांवों की गली हो बिहार के हर क्षेत्र में बिजली पहुंची है । महोदय, 2005 के दशक में बांस के बल्ले और लकड़ी के खम्भे पर तार टंगी हुई थी, हमलोग देखते थे लेकिन आज कंक्रीट का पोल और सुंदर सा उसपर बॉक्स और कवर तार से पूरे बिहार में विद्युतीकरण हुआ है । पूरे बिहार के सभी गांव के सभी बसावट में विद्युतीकरण हुआ है।

क्रमशः

टर्न-20/ज्योति/15-07-2019

क्रमशः

श्री उमेश सिंह कुशवहा : बिहार के सभी बसावहट में, गांव के सभी बसावट में विद्युतीकरण हुआ है और सरकार ने अपने संसाधन से सभी के घर में बिजली पहुंचायी है । महोदय, हमारा बिहार कृषि प्रधान राज्य है और आज हमारे बिहार के कुछ जिला बाढ़ से प्रभावित हैं तो अधिकांश जिला सुखाड़ से प्रभावित है । हमारे किसान भाई हैं, उनकी कमर टूट गयी और जो डिजल की महंगाई है, जिस कारण 100 से 150 रुपया कृषि पटवन पर जो खर्च होता है, उसके लिए जो हमारे किसान असमर्थ थे लेकिन माननीय मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए जो कृषि फीडर बनाकर और कृषि के लिए किसान के लिए सभी खेतों में बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया है, वह अद्भुत और बेमिसाल है और इससे हम समझते हैं कि किसान को जो 100 रुपया या 150 रुपया खर्च होता था, उसके जगह पर 5 रुपया से 7 रुपया खर्च होगा तो यह किसानों के लिए बरदान साबित होगा और कृषि के क्षेत्र में क्रांति आयेगी । 2005 में हमारा 1000 मे.वा. बिजली की खपत थी और उससे भी कम लेकिन आज हमारे बिहार में 5 हजार मे.वा. से अधिक खपत है और आने वाले दिनों में 2020 तक 600 मे.वा. से ज्यादा तक की खपत होगी । 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहे, इसके लिए जर्जर तार बदला जा रहा है और जो पावर ग्रीड है, पावर सब स्टेशन हैं, सब का ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में निर्माण कराया जा रहा है । 13 तारीख को बहुत देर तक 9 घंटा चर्चा चली जलवायु परिवर्तन पर ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप समाप्त करें ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौर उर्जा के लिए बढ़वा दिया है बिजली उत्पादन पर तो सरकारी अस्पताल है या स्कूल भवन, उसको सभी जगह लगाना है । कुछ और समय दिया जाय चूँकि हमने तो समस्या पर कुछ बतलाया ही नहीं । बिजली रेट के प्रति सरकार ने 2008 में कृषि समग्रता करके कुटीर रोजगार ..

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : श्री अशोक कुमार सिंह जी ।

श्री अशोक कुमार सिंह : महोदय, विपक्ष द्वारा जो कटौती प्रस्ताव लाया गया है और मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सर्वप्रथम महोदय, मैं धन्यवाद दूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके संकल्प का प्रतिफल, माननीय मुख्यमंत्री जी के निश्चय का रिजल्ट...

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : 5 मिनट में खत्म करिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह : माननीय उर्जा मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी के अनुभव और दीर्घकालिक प्रोग्राम और उर्जा विभाग के सी.एम.डी., एम.डी. सहित सभी इंजीनियर के कड़ी मेहनत के बदौलत आज बिहार बिजली के मामले में देश में अपना स्थान रख रहा है । मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विपक्ष के माननीय साथियों का, जिन लोगों ने यह कबूल किया कि निश्चित रुप से उर्जा के क्षेत्र में बिहार ने बड़ी सफलता हासिल की है । महोदय, पिछले 13 तारीख से मैं देख रहा हूँ पक्ष और विपक्ष का रैवया जो रहा है, अगर यह रवैया रहा तो हमलोग निश्चित रुप से आगे जायेंगे, बिहार आगे बढ़ेगा, बिजली के ही क्षेत्र में नहीं बिहार हर क्षेत्र में आगे जायेगा इसलिए मैं विपक्ष के साथियों को दिल से धन्यवाद देता हूँ और उर्जा के क्षेत्र में हमारे पक्ष और विपक्ष के साथियों ने जो बताया बहुत कुछ नहीं कहना, 5 मिनट का ही समय है, उर्जा के क्षेत्र में, हमारे माननीय मंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उसके लिए एक चौपाई याद आ रही है कि ''हरि अंनत, हरि कथा अनंता'' जिसतरह का भागीरथ प्रयास 2005 से लेकर अबतक उर्जा विभाग में हमारे माननीय मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने किया है यह काबिलेतारीफ है और माननीय सदस्य भोला बाबू कह रहे थे कि इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को देना चाहिए । मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी भारत सरकार से लड़ रहे थे कि हमें 16 के.वी.ए. का डब्बा नहीं चाहिएख हमको 63,100 और 200 के.वी.ए. का बिहार में ट्रांसफार्मर चाहिए ताकि हम हर घर बिजली पहुंचायेंगे और हमारे जो बेरोजगार नौजवान है, गांव के गली में रोजगार चाहेंगे तो उन्हें रोजगार करने के लिए बिजली भी देंगे और इसके साथ ही साथ राज्य सरकार ने जो अपने बजट से उर्जा क्षेत्र में व्यय किया है, मैं बेहिचक कह सकता हूँ कि देश के किसी सरकार ने इतना व्यय नहीं किया होगा जितना कि हमारी राज्य सरकार ने उर्जा पर किया है । मैं एक सुझाव देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को कि आपके विभाग ने कहा था कि अगर

24 घंटे में ट्रांसफार्मर जलेगा शहर का तो हम बदलेंगे और गांव का जलेगा तो 48 घंटा में बदलेंगे, आप तो 72 घंटा में बदलेंगे तो आप सब काम को चुनौती लेकर कर रहे हैं, हर तीन महीना पर एक एक चुनौती को पूरा करते जा रहे हैं । आप ग्रीड बना रहे हैं । आप बिजली घर बना रहे हैं । आप पावर सब स्टेशन लगा रहे है । रिकंडक्टिंग कर रहे है । हमारे सदस्यों ने चर्चा की बिजली बिल का उसका भी आपने संकल्प लिया है कि 2020 से पहले स्मार्ट प्रीपेड मीटर हम हर घर में लगा देंगे और एक भी पैसा नाजायज किसी भी उपभोक्ता से कोई नहीं लेगा तो यह सब काम कर रहे हैं तो जो किसानों का ट्रांसफार्मर जलता है, उसका भी 24 घंटा किया जाय और जिला मुख्यालय में ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, हर पावर सब स्टेशन में ट्रासंफार्मर का स्टोर किया जाय ताकि जब जले 24 घेंटे के अंदर बदल दिया जाय और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि आज मद्य निषेध पर भी डिमांड है तो मद्य निषेध के लिए हमलोगों ने हाथ उठाकर इस सदन में संकल्प लिया था कि न दारु पियेंगे, न दारु पीने देंगे और लोगों को शराब पीने से मना करेंगे तो मैं एक सुझाव देना चाहूंगा आपको कि थोड़ा शराब बंदी सफल है, पूरा देश हमारा प्रशंसा कर रहा है, इससे घरेलू हिंसा में कमी आयी है । हमारे जो नौजवान हैं बच्चे है, सही रास्ते पर जा रहे हैं, थोड़ा इसमें और कड़ाई करने की जरुरत है और कड़ाई करके जो बाहर के राज्यों से हमारे राज्य में शराब आ रही है बिचौलिए ला रहे हैं, उसको कड़ाई करके रोका जाना चाहिए । चूँकि समय नहीं है आपका इशारा हो रहा है महोदय, इसलिए मैं बहुत कुछ न कहते हुए अपनी बात समाप्त करुंगा । बहुत बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : धन्यवाद । अब राष्ट्रीय जनता दल की स्वीटी सीमा हेम्ब्रम।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : आदरणीय सभापति महोदय, आज मैं उर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । सबसे पहले मैं अपने नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार देती हूं चूँकि उन्होंने एक आदिवासी महिला को गांव से लेकर सदन तक पहुंचाने का काम किया है । महोदय, आज उर्जा विभाग की मैं थोड़ी सी तारीफ तो जरुर करुंगी और साथ ही तारीफ के साथ साथ कुछ जो खामियाँ हैं उनकी तरफ भी मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करुंगी । खामियाँ यही है कि बिजली विभाग में जितने भी काम हो रहे हैं वह प्राईवेट सेक्टर के द्वारा कराये जाते हैं और प्राईवेट सेक्टर के द्वारा कराए जाने से हमारे राज्य के जो कुशल युवा हैं वह वंचित रह जाते हैं ।

क्रमशः ..

टर्न : 21/कृष्ण/15.07.2019

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम (क्रमशः) : सभापति महोदय, इस विभाग में जितने भी कार्य कराये जाते हैं, वह कंपनी के द्वारा कराये जाते हैं और वह कंपनी जनता के साथ ऐसी जायदती करती है, चाहे वह बिजली कंनेशन का मामला हो, चाहे मीटर लगाने का मामला हो और चाहे वह बिजली बिल का मामला हो । इन सभी मामलों के कारण कहीं न कहीं वह सरकार को कठघरे में लाकर खड़ी कर देती है ।

महोदय, आजकल बिजली से जगह-जगह घटनायें हो रही हैं । सदन के जितने भी माननीय सदस्य हैं, आप सभी इन बातों से वाकिफ हैं । महोदय, जितनी भी घटनायें बिजली से हो रही हैं, वे सब खुली तार के चलते हो रही है। जगह-जगह तारें गिर जाया करती है । अगर बिजली से मरनेवालों की संख्या कहीं अव्वल है तो हमारे बिहार राज्य में बिजली से मरनेवालों की संख्या अव्वल नंबर पर है ।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में कटोरिया प्रखंड के कोल्हासार पंचायत के कोल्हासार ग्राम जहां कृषकों को सुविधा देने की बात कही गयी थी, वह अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है । पता नहीं, कबतक यह पूरा होगा, यह हम नहीं कह सकते लेकिन वहां की जनता त्रस्त है उस कनेक्शन के लिये, अगर उनको वह कनेक्शन जल्दी मिल जाता, अगर वहां ग्रीड जल्दी बन जाता है तो वहां के कृषकों को लाभ मिलेगा ।

महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कटोरिया प्रखंड के ही जयपुर पंचायत के रसोईया ग्राम को पावर ग्रीड के लिये चिन्हित किया गया था, वहां का एन0ओ0सी0 भी विभाग को दिया गया था और एन0ओ0सी0 देने के बाद भी पता नहीं उसको कहां स्थानान्तरित कर दिया गया, यह हमारी जानकारी में नहीं है । मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि चूंकि वह गांव सुदूर देहात क्षेत्र में है, जिस गांव को चिन्हित किया गया था, वह सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का गांव है । वैसे ही कटोरिया प्रखंड के एक बसमता पंचायत के बरमसिया गांव जहां कोल जाति के लोग रहते हैं, वहां पर तीन वर्षों से ट्रांसफरमर लगा हुआ है लेकिन अभी तक उस ट्रांसफरमर का कनेक्शन नहीं मिल पाया है । कारण यही है कि प्राईवेट सेक्टर के जो लोग काम करते हैं, वे वसूली करते हैं । मीटर लगाना हो तो उसमें 500/-रूपये की वसूली करते हैं, ट्रांसफरमर लगाना हो तो हरेक गांव से 10 से 15 हजार तक की वसूली करते हैं । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करती हूं ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आप 2 मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त कीजिये ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : महोदय, महिलाओं को 2 मिनट ही नहीं बल्कि 4 मिनट और मिलना चाहिए ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : बाकी महिलायें आपकी लाईन में लगी हुई हैं । उनका समय कट जायेगा ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : सबको मैं समय दूंगी । साथ ही मद्य निषेध के संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि जो शराबबंदी हुई, यह बहुत ही अच्छी बात है कि शराबबंदी हुई । लेकिन शराबबंदी में सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हुई तो हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों को परेशानी हुई । मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि जिस दिन हाथ उठाकर पूरा सदन शराबबंदी का समर्थन किया था, उसी दिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम महुआ के फूल से जैम तैयार करवाने का काम करेंगे । लेकिन 3 साल गुजर गये, जैम आजतक तैयार नहीं हुआ । उसका कारखाना आज तक नहीं लग पाया है । मैं आज इसीलिये इसके तरफ भी आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करती हूं । साथ ही, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अगर एस0सी, एस0टी0 का वहां पर मामला नहीं उठा, यह हमारे आदिवासियों के लिये नाकाफी होगी ।

सभापति महोदय, महोदय, मैं एक ऐसी बात को सदन में रखना चाहती है, वह है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के संबंध में । मैं आंकड़ा देना चाहती हूं, आप आदिवासियों के विकास की बात करते हैं, पूरे बिहार में अगर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में लाभ मिला है हम आदिवासियों को तो उनकी संख्या है मात्र 4 से 5 । तो क्या यही हमारे आदिवासियों का विकास का रास्ता है ? क्या हम आदिवासी विकास से वंचित रहेंगे ? मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि हम आदिवासियों को इस मुख्य धारा से भी जोड़ने का काम करेंगे ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकें ।

सभापति महोदय, साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि कस्तुरबा विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ आदिवासी बच्चे ही पढ़ते हैं । वहां भी आपको ध्यान देने की जरूरत है । हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न सड़कें, सड़कें तो आप दे ही रहे हैं, बिजली भी आप दे रहे हैं, हमें शिक्षा चाहिये शिक्षा । शिक्षा से महरूम हैं आदिवासी लोग । आदिवासियों को शिक्षा चाहिए ।

सभापति महोदय और एक विशेष बात यह है जिसकी ओर हम अपने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी । महोदय, मैं सदन में भी यह सवाल हमेशा उठाती रही हूं । संथाली भाषा जो 8वीं अनुसूचि में शामिल है, तीन साल हो गये, हमने सवाल भी उठाया था कि संथाली भाषा को बी0पी0एस0सी0 में शामिल किया जाय और

साथ ही संथाली भाषा की पढ़ाई तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में हो । लेकिन अभी तक यह नहीं हो पाया है । महोदय, मैं यही आग्रह करूंगी कि इसपर भी अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे भी बच्चे, हम आदिवासियों के बच्चे डी0एम0, बी0डी0ओ0, सी0ओ0 सभी बनेंगे।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह) : अब आप समाप्त कीजिये ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : (संथाली भाषा में भाषण दिया गया)

एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी ।

" हर नजर मूलत: विलासी है,
तृप्त होकर भी रूह प्यासी है,
तन से अगर कोई हो जाय आधुनिक,
मन से हर व्यक्ति आदिवासी है ।"

धन्यवाद । आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया । मैं आपका आभार प्रकट करती हूं ।

सभापति (श्री मो0नेमतुल्लाह) : माननीय सदस्य श्रीमती बेबी कुमारी जी । आपका समय 3 मिनट है।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, सरकार द्वारा ऊर्जा विभाग के संबंध में प्रस्तुत की गई मांग के समर्थन में बोलने के लिये मैं खड़ी हुई हूं । महोदय, मैं यह समर्थन केवल इसलिए नहीं कर रही हूं कि सरकार द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है बल्कि इसलिये कि बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार इस राज्य में हुआ है जहां कई दिनों तक बिजली नहीं आती थी, वहां 12 घंटे से 20 घंटे तक आज बिजली मिल रही है ।

सभापति महोदय, किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ है बिजली। वहां की सारी अर्थ-व्यवस्था बिजली पर आधारित होती है । चाहे वह खेती हो, उद्योग हो अन्य कोई क्षेत्र हो । आज खेतों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया है और खेतों के लिये अगल से फीडर बनाये जा रहे हैं। महोदय, यहां जितने भी उद्योग थे, वे कराह रहे थे क्योंकि उन्हें जेनरेटर से प्रोडक्शन करना पड़ता था जिससे वह मंहगा होता था परन्तु अब बिजली मिल जाने के कारण प्रोडक्ट सस्ता हो गया है और वह अन्य राज्यों से आये प्रोडक्ट का मुकाबला कर रहा है । आज गांवों के लोग जागरूक हुये हैं । उनकी क्रय शक्ति भी बढ़ी है । जीवन स्तर भी बढ़ा है जिसके कारण लोगों के हाथों में मोबाईल और प्राय: सभी घरों में टी0वी0 है लेकिन इन दोनों चीजों की कल्पना बिना बिजली के संभव नहीं है । पहले गांव एवं शहरों में कुछ लोग जेनरेटर से बिजली सप्लाई करते थे और उसका कनेक्शन लोग अपना मोबाईल चार्ज

करने के लिये लेते थे । कुछ घरों में बैटरी पर भी मोबाईल चार्ज होते थे । लेकिन अब लोग अपने-अपने घरों में ही मोबाईल की बैटरी चार्ज कर लेते हैं और इसके लिये उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है ।

सभापति महोदय, बिजली में सुधार के लिये इन्हीं कदमों के तहत मेरे बोचहा विधान सभा क्षेत्र में मुसहरी प्रखंड के नरौली पंचायत के बिन्दा गांव में पावर सब स्टेशन का काम जोर-शोर से चल रहा है । बोचहा में भी पावर सब स्टेशन स्थापित करने के लिये स्वीकृति मिल चुकी है ।

क्रमश :

टर्न-22/अंजनी/दि0 15.7.19

श्रीमती बेबी कुमारी : क्रमश:..... इसके लिए मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूँ और साथ-साथ प्रधान सचिव जी को भी बधाई देती हूँ । महोदय, मैं कुछ सुझाव भी जनहित में देना चाहती हूँ । मेरा पहला सुझाव है कि बिजली आपूर्त्ति की तार पुराने हो चुके हैं और प्राय: टूटते रहते हैं, जिससे दुर्घटनायें होती रहती है । मनुष्य और जानवरों की जानें चली जाती है । सभी जगह अभियान चलाकर केवल वायर लगाया जाय । दूसरा सुझाव है कि बिजली विभाग मीटर देता है और उसका रेंट लेता है, वह जीवन भर चलते रहता है, इसे बदलकर बिजली मीटर की कीमत एकमुश्त लेकर लायी जाय । तीसरा सुझाव है कि....

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती बेबी कुमारी : बिजली बिल की त्रुटि और सुधार निरंतर प्रक्रिया है । त्रुटि में सुधार के लिए उपभोक्ताओं को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है, इस व्यवस्था को बदलकर सुनिश्चित किया जाय और ऑनलाईन आवेदन सुधार लिये जायें और उसका निपटारा 24 घंटे के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाय । महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार और अपने नेता के प्रति सहृदय धन्यवाद ।

सभापति (श्री मो0 नेमतुल्लाह) : जनता दल यूनाइटेड के सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी। आपका पांच मिनट समय है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में वर्ष 2019-20 के अनुपूरक व्यय विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग पर मांग संख्या-10,38,46,44 के समर्थन पर आपने बोलने का मौका दिया, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं । सभापति महोदय, आपके माध्यम से विकास पुरूष माननीय सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने

न्याय के साथ राज्य के विकास की गाड़ी को बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ाने का दिन-रात काम कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का, माननीय मंत्री महोदय, ऊर्जा का, माननीय मंत्री महोदय, पर्यटन विभाग का, माननीय मंत्री महोदय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण का तथा माननीय मंत्री महोदय, संसदीय कार्य का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

मैं बिजली विभाग के इस निष्ठावान कर्त्तव्य को देखते हुए पूरा गति से कार्य इन्होंने किया । बिजली विभाग के सारे उच्चस्तरीय अधिकारी, पदाधिकारी प्रत्यय अमृत साहेब को और उनके साथ जितने भी कनीय अधिकारी हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । बिजली विभाग हर वक्त अग्रसर की ओर जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सात निश्चय के संभाग में एक भाग हर घर बिजली एक महत्वूर्ण भाग है । जिसपर ऊर्जा विभाग समय से पहले ही मूर्त रूप देने का काम किया है । हर घर बिजली लगातार निश्चय का शुभारंभ 15 नवम्बर, 2016 को किया गया था, दो वर्ष का समय दिया गया था लेकिन राज्य सरकार द्वारा संकल्पित सात निश्चयों में से हर घर बिजली के तहत राज्य के सभी इच्छुक परिवारों को मुख्यमंत्री विद्युत सम्बद्ध निश्चय योजना, जिसे बाद में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना संभाग में समाहित कर दिया गया के तहत दिसम्बर 2018 तक विद्युत सम्बद्ध देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे दो माह पूर्व अक्टूबर, 2018 में ही पूरा करके विभाग ने अपना बड़प्पन लिया । अध्यक्ष महोदय, आज ट्रांसफार्मर बदलने की बात लोग सुना रहे हैं...

अध्यक्ष : निरंजन जी, आप एक मिनट में सुझाव के साथ ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : ट्रांसफार्मर का भी बदली हो रहा है, 24 घंटा में हमलोगों के क्षेत्र में ट्रांसफार्मर बदली होता है । दीनदयाल उपाध्याय के अंतर्गत जर्जर तार और जर्जर पोल बदले जा रहे हैं । महोदय, बिजली में जितना भी द्रूत गति से काम हुआ है, एग्रीकल्चर में दीन दयाल उपाध्याय के तहत किसानों को बिजली मिल रही है और 75 पैसा जो यूनिट का रेट दिया गया है, उससे किसान खुश हैं । अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं चारों विभाग के माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्रीमती अनीता देवी, आप चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर लीजिए, साढ़े चार से सरकार का उत्तर होगा ।

श्रीमती अनीता देवी : महोदय, आज मैं विपक्ष द्वारा ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में हम लालू के लोग जनता के आवाज पर आज सदन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । इसलिए, अपने विधान सभा और बिहार की तरफ से सभी सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ । महोदय, आज ऊर्जा विभाग है और ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए हैं । हमारी दिनचर्या पहले से बेहतर हो गयी है और हमलोग केवल ऊर्जा पर ही आश्रित हो गये हैं । पानी हो, बिजली हो, रसोई हो या कल-कारखाना हो, सभी जगह बिजली के ही काम आते हैं । इसलिए यह कहना बिजली के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, उचित नहीं है, बहुत काम हुआ है । बिहार में बिजली का काम पहले से बेहतर हुआ है । महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र में जो बी0पी0एल0 के लोग हैं, जो गरीब गुरबे हैं, जिसके खाने के लिए दो जून की रोटी नहीं है, उनके यहां घर पर दो से चार-पांच हजार तक प्रति महीना बिल आ रहा है, यह एक चिंतनीय विषय है । मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ कि आपके जितने भी कर्मचारी हैं, उनको कहिए देखने के लिए । हमारे जितने गरीब गुरबा हैं, हम सभी गांव से आये हैं, उन कर्मचारियों को निदेश दिया जाय कि बिल को ठीक कराया जाय और मीटर देखकर ही बिल दें । जो गांव के गरीब, गुरबा हैं, एक, दो, तीन बल्व जलाते हैं, जिनके घर में टी0वी0, फ्रीज नहीं है, उनके यहां दो से चार-पांच हजार रूपये का इतना बिल कैसे आ रहा है, जिनको खाने के लिए दो जून की रोटी तक नहीं है । मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दें कि जो बिजली में बिल की समस्या आ रही है, जो गरीब, गुरबा का दोहन हो रहा है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है महोदय । आज पर्यटन भी है । बिहार की भूमि धार्मिक विरासत समृध ऐतिहासिक पौराणिक है । हमारे यहां बिहार में पर्यटन के स्थल बहुत सारे हैं । बिहार तो बिहार है । बिहार घूमनेवाला पौराणिक बुद्ध की धरती है और हमारे यहां 6 रोप-वे की स्वीकृति मिली थी, जो सिर्फ दो पर ही काम चला है । एक पर तो काम राजगीर में तेजी से हो रहा है और एक है मंडार, जिस पर काम 6-से-7 साल से चल रहे हैं लेकिन अभी तक रोप-वे का काम पूरा नही हुआ है, और चार, जिसकी स्वीकृति मिल गयी है लेकिन उस पर काम नहीं हो रहा है । महोदय, सरकार ने 2016 में पर्यटन विभाग को निर्देश दिया था पंचवर्षीय रोड मैप बनाने की । इसमें पूरे बिहार की जितने भी धाार्मिक स्थल थे, सबको लिया गया था लेकिन खेद और चिंता का विषय है कि अभी तक वह, सवा साल बचा हुआ है, अभी तक पंचवर्षीय रोड मैप तैयार नहीं हुआ है । महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि पर्यटन स्थल में बिहार के जितने भी पर्यटन स्थल हैं, जिसको हम बढ़ावा देना चाहते हैं, जिनका हम प्रचार-प्रसार करना

चाहते हैं, केवल राजगीर और सोनपुर को छोड़कर जितने भी महोत्सव हो रहे हैं, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है । केवल कागजीपूर्त्ति होती है, कोई पदाधिकारी नहीं जाते हैं । केवल दो ही जगह होता है, एक है सोनपुर मेला और दूसरा है राजगीर । राजगीर में तो काम होते ही रहता है । महोदय, आज मद्य निषेध विभाग भी है, हमलोग भी शपथ लिये थे कि न शराब पीयेंगे और न पीने देंगे ।

....क्रमशः....

टर्न–23/राजेश/15.7.19

श्रीमती अनिता देवी : क्रमशः.. यह बहुत ही सराहनीय कदम है, हमलोग भी इसकी वाहवाही कर रहे थे लेकिन अभी जो अति पिछड़ा, पिछड़ा का हाल है, जिसे सबसे ज्यादा नुकसान आज शराब से हो रहा है, जो सबसे ज्यादा इसे झेल रहा है, हम महिलाओं के कहने पर ही सरकार ने शराबबंदी की थी लेकिन अभी देखिये महोदय, कि हर जगह शराब आसानी से मिल रहा है ..... (व्यवधान)

अध्यक्षः अब समाप्त कर दीजिये ।

श्रीमती अनिता देवीः महोदय, मेरे क्षेत्र की बात है ।

अध्यक्षः ठीक है ।

श्रीमती अनिता देवीः महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत .....(व्यवधान)

अध्यक्षः अब अंतिम बात बोल लीजिये, पढ़िये नहीं, बोलिये ।

श्रीमती अनिता देवीः महोदय रोहतास जिलान्तर्गत हमारे जितने पर्यटक स्थल हैं, जैसे मांझरकुंड हैं, रोहतास का किला है, तुला भवानी है, मत्स्यगंधा जो झील है, उसकी स्वीकृति हो गयी है लेकिन काम अभी तक चालू नहीं हुआ है । महोदय, नोखा में एक पावर ग्रीड 2006 से ही बनकर रेडी है लेकिन वह अभी तक चालू नहीं हुआ है । महोदय, इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, उर्जा विभाग की मांग पर अब वाद–विवाद समाप्त हुआ । अब सरकार का उत्तर होगा लेकिन मंत्री, उर्जा को पुकारने से पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि आज प्रश्नकाल के शुरु होते ही और प्रश्नकाल के बाद इस सूबे में व्याप्त जो बाढ़ की भयावहता है, उसपर बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की थी । सरकार की तरफ से सूचित भी किया गया था कि माननीय मुख्यमंत्री स्वयं उन इलाकों का कल से आज तक लगातार सर्वेक्षण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, तो आज आसन को सूचित किया गया है कि कल प्रश्नकाल के तुरत बाद यानी 12.00

बजे के आस-पास माननीय मुख्यमंत्री स्वयं आज जो सूबे में बाढ़ के हालात हैं, उसकी जो अद्यतन स्थिति है, उसमें जो सरकार के प्रयास हैं, इन सारी चीजों के संबंध में अपने सर्वेक्षण और समीक्षा के आलोक में वक्तव्य देंगे कल 12.00 बजे । माननीय मंत्री, उर्जा विभाग ।

श्री भोला यादव: महोदय, हमलोग आग्रह किये थे आपसे कि जो बाढ़ की स्थिति है, उसको देखते हुए दो-तीन दिन के लिए सदन बंद कर दिया जाय, हमलोग का क्षेत्र प्रभावित है, हमलोग चलते सत्र के कारण क्षेत्र में जा नहीं पायेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय मंत्री, उर्जा ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के प्रति ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के लोगों को सूचित करना चाह रहे हैं कि हम मजबूरी में नहीं आ रहे हैं ।

श्री प्रहलाद यादव: महोदय, पहले हमलोगों से जानकारी ले लें, तब न माननीय मुख्यमंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्रहलाद जी, आप पुराने सदस्य हैं, वक्तव्य पर वाद-विवाद नहीं होता है । आपको जो सूचना देनी होगी, आप सरकार को दे दीजियेगा । इतनी संवेदनशीलता से सरकार एवं स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी वक्तव्य देंगे, तो इसमें क्या फिर अगर, मगर, जो आपको सूचना देनी होगी, उसके लिए कोई मनाही थोड़े है । माननीय मंत्री, उर्जा ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, मुझे खुशी है कि सभी माननीय सदस्यों ने उर्जा विभाग के कामों पर संतुष्टि व्यक्त किया और प्रशंसा करने का काम किया है कि अदभुत काम हुआ है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ । कुछ कमियाँ, कुछ त्रुटियाँ यह तो सतत् चलने वाली क्रिया है, जैसे बिल के संबंध में, उसपर भी मैं बोलूंगा, जैसे कंप्लेन के संबंध में या कुछ मांगे जो हैं, उसपर मैं बाद में बोलूंगा ।

महोदय, अब चूंकि भोला बाबू ने और नालंदा के माननीय विद्वान सदस्य, हलॉकि विद्वान कहना आर0जे0डी0 वालों को खराब लगता है, मैं नहीं कहूंगा, कुछ बातों का जिक्र किया, नहीं तो मैं छेड़ता नहीं चाहता था । महोदय, आज इस सदन में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए स्वर्गीय माननीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा, श्रद्धा व्यक्त करना चाहूंगा कि

देश में पहली बार ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में उन्होंने स्टेप लिया, उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत सरकार में मंत्री थे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना, उसी समय प्रारंभ हुआ और महोदय, सभी दल को, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस समय भारत सरकार में मंत्री थे, उनके नेतृत्व में हमलोग भी गये थे, सर्वदलीय एक कमिटी गयी थी कि बिहार के बॅटवारे के बाद जो बिहार की आर्थिक बदहाली है, जो साधन की कमी है, तो विशेष पैकेज मिले, तो चार हजार करोड़ रुपया सम विकास योजना के रुप में, वाजपेयी जी के प्रति, फिर मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा, उसमें उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री थे, उनका भी इनिसिएशन था और चार हजार करोड़ रुपये का सम विकास योजना के नाम से राशि दी गयी प्लानिंग कमीशन के द्वारा । इसके साथ ही महोदय, भागलपुर के रहने वाले हैं, अर्थशास्त्री है, उनकी अध्यक्षता में एक कमिटी बनी तीन सदस्यीय, उस समय कमिटी ने तीन महीने तक बिहार का अध्ययन किया विभिन्न जिलो में, उस समय आप ही लोगों की सरकार थी, तीन चीज को आईडेनटिफाई किया उन्होंने, नं0–1: बिहार में स्टेट हाईवे की हालत खराब है, नं0–2: गंडक, सोन, कोशी यह जो बराज बनाकर नहर परियोजनाएँ बनायी गयी, वह डिटोरिएट कर गयी है, उसकी क्षमता जो है इरिगेशन करने की वह 40 परसेंट बच गया है, उसके रिनोवेशन की जरुरत है और तीसरा यह कहा गया कि ट्रान्समिशन लाईन की कमी है, जिसके चलते बिजली व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता है, तो एक–एक हजार करोड़ रुपये इसके लिए आवंटित किये गये, अब मैं कंटोभर्सी पैदा नहीं करना चाहता, उस समय की सरकार ने कहा कि हम यह काम नहीं कर पायेंगे, केवल इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा कि हम कर पायेंगे, उर्जा विभाग ने कहा कि हम नहीं करेंगे, हमारी क्षमता नहीं है, सड़क विभाग ने कहा कि हमारी क्षमता नहीं है, तो सड़क विभाग का काम आवंटित किया गया, जो भारत सरकार की एक कंपनी है एन0बी0सी0सी0 को, उसको फस्ट फेज में काम दिया गया और पावर ग्रीड एन0पी0सी0सी0, दोनों को बिहार के 38 जिलों में से 30 जिले आवंटित किये गये, 8 जिले आवंटित थे, इसमें कटिहार, कोशी का तीनों जिला, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर, मुंगेर जिला का शेखपुरा, तो यह स्थितियॉ थीं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहॉ हैं, बाद में सरकार बनी, 2006 तक अवधि थी उस पैसे को खर्च करने की, खर्च नहीं हो पाये, यूं ही एक दिन कैबिनेट की बैठक थी, मैंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, सड़क विभाग में भी राशि खर्च नहीं हो पायेगा, इरिगेशन में भी खर्च नहीं हो पा रहा है, उर्जा विभाग तैयार है, अपना प्रोजेक्ट बना लिया है, ट्रान्समीशन लाईन का विस्तारीकरण में इस राशि को खर्च करना चाहते हैं, इन्होंने समीक्षा बैठक की, फिर

बुलाया गया हमलोगों को, रुपये आवंटित किये गये और वहीं से क्रिया प्रारंभ हुई महोदय, इसलिए मैं फिर स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ, आदर करना चाहता हूँ और बिहार उनके प्रति ऋणी रहेगा ।

अब महोदय, लंबी यात्रा चली, यह ठीक है कि सरकारें आती, जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, नामकरण का तबादला होता है, बदली होती है, राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना हुई लेकिन क्या थी स्थिति, यह ठीक है कि 90 परसेंट भारत सरकार और 10 परसेंट राज्य सरकार लेकिन रेवेन्यू विलेज का एडजेक्ट 10 परसेंट बी0पी0एल0 वालों को ही कनेक्शन देना था, 16 के ट्रान्सफर्मर और 26 के ट्रान्सफर्मर, ये दो ही लगाने की योजना बनायी गयी थी ।

क्रमशः

टर्न-24/सत्येन्द्र/15-07-19

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री:(क्रमशः): माननीय मुख्यमंत्री जी ने कईएक मीटिंग में कहा कि साहब हमारे यहां ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 का मिक्स आबादी है, हमारा पोपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है ग्रामीण क्षेत्र की बहुलता है, एग्रीकल्चर ओरियेंटेड स्टेट है, ए0पी0एल0 के बगल से हम बी0पी0एल0 के यहां कनेक्शन को ले जायेंगे तो हम कैसे उसको रोक सकते हैं या तो 100 प्रतिशत भारत सरकार करे, ए0पी0एल0 छोड़ दे राज्य सरकार के जिम्मे लेकिन वह भी निर्णय नहीं हो पाया, अंत में मुझे याद है एक मीटिंग में बहुत झड़प हुई, प्रधानमंत्री जी भी थे मनमोहन सिंह जी, मैंने कहा आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 30 हजार मेगावाट अगले 10-12 सालों में आप ट्रांसमिशन लाईन बनाकर नौर्थ स्टेट रीजन भूटान से बिजली ले जायेंगे देश के अन्य हिस्सों में, हमारे यहां खेत सूखे रहेंगे, घर अंधेरे में रहेंगे, मैं अपने लोगों को बतलाऊंगा कि ये टावर भारत सरकार का है और ये टावर राज्य सरकार का है, आई विल नौट सेंड द पुलिस, प्लानिंग कमिशन के वायस चेयरमैन उस समय अहुलवालिया साहब थे, उन्होंने कहा कि ईट इज द नेशनल थ्रेट, शिन्दे साहब थे इनर्जी मिनिस्टर, हमने कहा If it is a national threat, Bihar is a part of this country. How a democratic elected people can kill our own people if they are suffering from the problem. प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, शिन्दे साहब बैठ गये, अहुलवालिया साहब बैठ गये, प्रोब्लेम पर आगे बात बढ़ी, शिन्दे साहब आये और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक हुई, मुझे आज भी याद है, इनके एक अन्ने मार्ग में बैठक हुई, कहा नीतीश जी

आपका मंत्री हर मीटिंग में हमसे झगड़ा करता है, बैठ कर हमलोग शार्टआउट करें, कुछ सुधार हुए, कुछ बातें बढ़ी, मैं इससे इंकार नहीं कर सकता, सच को कभी झूठ बोलने की आदत हमलोगों की नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार अगर कोई गलतियां करेगी तो स्वीकारने में भी उसे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सही काम में अड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है । ऐसा नहीं कि थेथोरलौजी से हमलोग आगे बढ़ते हैं लेकिन 2015 में ही, 2015 में आपका महागठबंधन हुआ और 2015 में ही सात निश्चय योजना की घोषणा हुई और उस समय यह भारत सरकार की योजना में भी नहीं था हर घर बिजली और यह अपने पैसे से शुरूआत करने का काम हुआ 2015 में, ठीक है राजनीति में चीजें होती रहती है, बहुत इसकी परिस्थितियां होती है, मुझे याद है इतिहास के उन हिस्सों को याद करूंगा अभी, सकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो दुनिया दो भागों में विभक्त थी, एक कैपलिस्ट थियोरी और दूसरा कम्युनिष्ट की थियोरी, रूस और अमेरिका में आज से ज्यादा टेंशन था, ज्यादा मतभेद था एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, जब हिटलर की ताकत बढ़ने लगी तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे चर्चिल, अमेरिका और रूस को एक जगह बैठाकर हिटलर के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करने का काम किया था ताकि हिटलरशाही खत्म हो । जब दुनिया पर खतरा आता है, कोई राजनीतिक परिस्थितियां आती है, ऐवरीथिंग इज फेयर इन लव ऐंड वार, ये सब तो चलती रहती है इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी को धोखा देते हैं, हम किसी को समर्थन करते हैं । अब किसी का नोमिनेशन भरता है लोग और वोट किसी और को देता है । यह भी घटना हुई है तो इन बातों को छोड़ दीजिये, राजनीति में इन सब चीजों का जिक्र मत कीजिये, तो 2015 में आये और 2016 का चुनाव लड़ा गया, फिर जब हमलोग आये तो भारतीय जनता पार्टी ने उन सात निश्चयों को स्वीकारा और उसी के आधार पर जो हमारे कार्यक्रम थे, भोला बाबू भी हैं, हमलोगों की मीटिंग भी हुई थी, हमलोगों की एक ही शर्त्त पर कि नेता हमारा रहेगा, सीट कोई प्रोब्लेम नहीं है । बहुत खुशफहमी में रहते हैं कईएक बैठकें हुई, इसलिए उस सब जिक्र को छोड़ दीजिये तो महोदय कहने का मतलब, राज्य हमारा है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हों, हमें निश्चित तौर से आगे बढ़कर के उसमें राज्यहित में, बल्कि आज सिद्दिकी साहब नहीं है, वे गाना का जिक्र करते हैं तो मैं भी एक गाने का जिक्र करता हूँ, बड़ा माकूल गाना है, शिक्षाप्रद है, आज के तरह पहले गाने नहीं बनते थे- छोड़ों कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ हम सब मिलकर लिखें नई कहानी, हम हिन्दुस्तानी । इस सदन में 12 करोड़ लोगों के आप भी चुने हुए प्रतिनिधि है और 12 करोड़ लोगों के चुने हुए इधर भी प्रतिनिधि हैं । 243 मेम्बर 12 करोड़ के लोगों के द्वारा चुनकर इस सदन में

आना कोई मामुली बात नहीं है और आदरणीय हमलोगों के नेता स्व0 कपूर्री जी कहते थे, लोक लाज से राज चलता है सब कानून में लिखा हुआ नहीं है । वे सदन में हंगामे के खिलाफ रहते थे,कहते थे कि बड़ी कुर्बानी, बड़ी शहादत से ये सदन हमें हासिल हुआ है, गरीब से गरीब आदमी के बीच में भी लोग वोट मांगने के लिए जाता है इसीलिए हंगामे कर के समस्या का निदान नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हर बात पर तैयार रहते हैं । आज आपने सवाल उठाया, मुझे गर्व है कि अभी अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ पर बोलेंगे और कल ही से ये परेशान हैं, कल ही 10 बजे से माननीय मुख्यमंत्री जी परेशान है । पूरे बिहार में फल्ड इफेक्टेड एरिया का हवाई सर्वेक्षण कर आये हैं, सारे सीनियर अफसर इनके साथ थे और सभी जगह निर्देश देने का, आदेश देने का इन्होंने काम किया है, कल सुनियेगा पूरी बात, तो कहने का मतलब ये है कि हम सब मिलकर अगर कुछ खामियां हैं, कोई कमियां हैं तो उसको दूर करें । यही है इसका मतलब । अब कईएक माननीय सदस्य ने उठाया कि पशु मर जाते हैं, अब आदमी के मरने पर तो मुआवजा मिलता है, मैं बताना चाहता हूॅ सुनिये, तो महोदय, 15 जून को यह निर्णय कर लिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भैंस, गाय में 30 हजार, भेड़, बकरी, सुअर में 30 हजार, ऊंट, घोड़ा, बैल में 25000 तो ये निर्णय कर लिये गये इसलिए इसमें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है । (व्यवधान) अब सुन तो लीजिये, 15 जून को ही यह निर्णय हुआ, बीच में आचार-संहिता था, अगर कहीं नहीं मिला है तो माननीय सदस्य लिखकर दें, उसको दिखवाया जायेगा और निश्चित रूप से मिलेगा । जहां तक बिल का सवाल है महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, सभी लोग पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिये, जानकारी ले लीजिये । पहले क्या मिलता था, ये लोग बोलेंगे थोड़े ही कुछ । अब महोदय,पहले का भी जिक्र किया तो मैं पहले की ही बात करता हूॅ महोदय, पहले बिजली ही कितनी मिलती थी सात सौ सवा सात सौ मेगावाट, पटना में भी 24 घंटे बिजली नहीं रहती थी तो पहले आप कैसे निर्णय ले लेते कि मरने पर मुआवजा मिलेगा तो उनको तो छोड़िये महोदय, लेकिन मैं कहना चाहता हूॅ महोदय कि वक्त के अनुरूप कुछ समस्याओं के निदान के लिए निर्णय होते रहते हैं, यह लगातार की क्रिया है, ऐसी बात नहीं कि कल हुआ इसीलिए मैंने ठीक कहा लेकिन हम सब को मिलकर के, बैठकर के जनहित के जो मामले हैं, राजनीति अपनी जगह पर है, आज जो काम हुआ है, आप सब लोगों ने प्रशंसा करने का काम किया है इसीलिए मैं आपको फिर धन्यवाद दूंगा । मैं नहीं कहता कि आपलोगों ने कोई बेईमानी की, एक-एक माननीय सदस्यों ने प्रशंसा की लेकिन और कमियां हैं, कमियां तो हैं, अब ट्रिप करने की बात, टेक्निकल

फाल्ट की बात कर रहे हैं, आज ही सबेरे महोदय, मैंने अखबार में पढ़ा, अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयार्क, राजधानी तो वाशिंगटन है, मैं गया नहीं हूँ लेकिन पढ़ता तो हूँ, कल रात में भर रात बिजली वहां बंद रही लेकिन किसी ने हंगामा नहीं किया, जुलूस नहीं निकाला, अखबार में छपी है यह बात ..

श्री आलोक कुमार मेहता: महोदय...

अध्यक्ष: अरे, बैठिये न आप, इतनी देर बिहार के बारे में बोल रहे थे तब कुछ नहीं बोल रहे थे और अमेरिका की बात पर क्यों बोलने के लिए खड़े हो गये ?

श्री आलोक कुमार मेहता: अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल सहित पूरा विपक्ष उस समय सरकार में शामिल था और योजना के कार्यान्वयन...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: ठीक है,माननीय मंत्री जी..

(व्यवधान)

टर्न-25/मधुप/15.07.2019

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपको जाना है क्या ?

मंत्री जी ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ । संचरण के क्षेत्र में हमलोगों ने उत्साहवर्द्धक उपलब्धि हासिल की है । 2015-16 में 3459 मेगावाट बिजली हमलोग लेते थे, 2016-17 में बढ़कर 3769 मेगावाट हो गया, 2017-18 में 4535 मेगावाट, 2018-10 में 5139 मेगावाट, 2019-20 में 25 जून, 2019 तक 5598 मेगावाट रेकॉर्ड पीकलोड हुआ । आगे आने वक्त में महोदय, क्षमता का विस्तार करके 10,930 मेगावाट, जो 2019-20 के अंत में बढ़कर, अभी जो क्षमता है, 11,346 मेगावाट हो जायेगी ।

(इस अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से वाक-आऊट किया गया)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप बोलते रहिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, राज्य सरकार के द्वारा पहली बार योजना की राशि से 400 / 220 / 132 के0वी0 का जी0आई0एस0 ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण बख्तियारपुर में कराया

जाना है । निविदा अंतिम चरण में है । इस कार्य को मार्च, 2021 तक पूरा कर लिया जायेगा ।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कम्पनी के संयुक्त उपक्रम बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बी0जी0सी0एल0) द्वारा भी 400 / 220 / 132 के0वी0 के दो जी0आई0एस0 ग्रिड उपकेन्द्र जक्कनपुर एवं नौबतपुर का निर्माण कराया जाना है ।

(इस अवसर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं भा0क0पा0(मा0ले0) के माननीय सदस्यों द्वारा भी सदन से वाक-आऊट किया गया)

महोदय, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा 400 / 220 / 132 के0वी0 के तीन ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण सहरसा, सीतामढ़ी एवं चंदौती (गया) में किया जा रहा है ।

महोदय, हर घर को बिजली देने की योजना पूरी कर ली गई है । भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में जो प्राइवेट कम्पनी थे उनको हटा दिया गया है और हटाकर उस काम को भी तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है ।

रिकंडक्टरिंग का काम - कोई माननीय सदस्य चर्चा कर रहे थे, उसको भी माह दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, उसको भी पूरा कर लिया जायेगा ।

महोदय, ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस की चर्चा मैं करना चाहूँगा जिसकी चर्चा बराबर होती है । 2013-14 में जहाँ 46.33 प्रतिशत था, 2014-15 में घटकर 43.82 प्रतिशत हो गया, 2015-16 में 43.54 प्रतिशत, 2016-17 में 39.74 प्रतिशत, 2017-18 में 30.22 प्रतिशत, 2018-19 में 27.39 प्रतिशत पर आ गया है ।

महोदय, शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए भी स्पॉट बिलिंग कराई जा रही है । साथ-ही, सॉफ्टवेयर के उपयोग से उपभोक्ताओं को उनके घर पर ही मीटर आधारित सही विद्युत विपत्र की प्राप्ति होने लगी है । बिलिंग इफिसियेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि 2014-15 में 58.74 प्रतिशत, 2015-16 में 60.55 प्रतिशत, 2016-17 में 66.68 प्रतिशत, 2017-18 में 69.78 प्रतिशत एवं 2018-19 में 75.67 प्रतिशत बिलिंग इफिसियेंसी रही है ।

महोदय, राजस्व संग्रह में बढ़ोत्तरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि 2014-15 में 4933.08 करोड़ रूपये, 2015-16 में 5538.78 करोड़ रूपये, 2016-17 में 5808.44 करोड़ रूपये, 2017-18 में 8001.00 करोड़ रूपये तथा 2018-19 में 9071.31 करोड़ रूपये हो गया है । महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रतिमाह औसतन 756 करोड़ रूपये की राशि की वसूली हुई है ।

विद्युत उपभोक्ता एवं नये आवेदकों के लिए राज्य में 'सुविधा' नामक सिंगल विंडो हेल्पडेस्क की शुरूआत पेसू क्षेत्र के 12 प्रमण्डलों में की गयी है । शेष विद्युत आपूर्ति प्रमण्डलों में भी लागू कराया जायेगा ।

महोदय, कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता अपने विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के 'सुविधा' सिंगल विंडो हेल्पडेस्क पर पहुँच कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा या सेवाओं हेतु आवेदन दे सकेगा ।

इसके अतिरिक्त महोदय, विद्युत भवन-3 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड कॉलोनी के आवासीय परिसर में सामुदायिक भवन एवं ऑडिटोरियम का निर्माण भी कराया जा रहा है ।

महोदय, मैं अपने विभाग के तमाम इंजीनियरों को माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से ओडिशा में जो तूफान आया था, वहाँ के मुख्यमंत्री ने हमारे मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि बहुत खराब स्थिति है तो एक टीम माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर वहाँ गया था, जिसकी प्रशंसा ओडिशा की सरकार ने भी किया और रिक्विजिट समय में व्यवस्था को रेस्टोर करने का काम हमारे अभियंताओं ने किया । इसके लिये मैं अपने अभियंताओं को बधाई देना चाहूंगा ।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी महोदय, कई एक काम कराये जा रहे हैं । साथ-ही, हाइड्रो पावर के क्षेत्र में भी डागमारा परियोजना एवं अन्य कई छोटी-छोटी परियोजनाएँ हैं, विस्तृत रूप से काम करने की कार्रवाई की जा रही है । जल्द ही उसके परिणाम आने लगेंगे ।

महोदय, प्रीपेड मीटर लगाने के लिए भी हमलोग कटिबद्ध हैं लेकिन इसमें अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं । महोदय, एक लिस्ट है जिसे हम दे देंगे सदन में। प्रीपेड मीटर लगाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उसमें कठिनाई यह हो रही है कि एवेबलिटी की कमी है लेकिन फिर भी फेजवाइज उसको करके हमलोग आगे बढ़ायेंगे और निश्चित रूप से इसका निदान भी आयेगा ।

एक और बात, कुछ नई घोषणाएँ मैं ग्रिड के स्ट्रेंथनिंग के लिए करना चाहता हूँ । छपरा एक अकेला कमीश्नरी है जहाँ 400 के0वी0ए0 का ग्रिड नहीं है । हमलोगों ने निर्णय लिया है 400/220/132 के0वी0ए0 ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण छपरा में भी कराया जायेगा ताकि ऊर्जा का जो प्रोब्लेम आता है, वह ठीक-ठाक से फंक्शन करे, ठीक तरीके से वहाँ काम हो । उसी तरह से भागलपुर के बरारी में एक ग्रिड उपकेन्द्र बनेगा 132/33 के0वी0 का, 132/33 के0वी0 का ग्रिड उपकेन्द्र दाउदनगर(औरंगाबाद) में, 132/33 के0वी0 का ग्रिड उपकेन्द्र बाराचट्टी(गया) में, 132/33 के0वी0 का ग्रिड

उपकेन्द्र मानपुर(भोरे, गया) में और 132/33 के0वी0 का ग्रिड उपकेन्द्र मुरलीगंज, (मधेपुरा) एवं 132/33 के0वी0 का ग्रिड उपकेन्द्र, बगहा(पश्चिमी चम्पारण) में निर्माण होगा । 7 नये ग्रिडों के बनने से महोदय, और ज्यादा पावर इफिसियेंसी में वृद्धि होगी, बढ़िया से वोल्टेज भी रहेगा, जो ट्रिपिंग की समस्या या जो अन्य बातें होती हैं, समस्या दूर होगी ।

महोदय, बाकी जो माननीय सदस्यों ने शिकायतें की हैं, तूफान और बाढ़ के चलते, उस प्रोब्लेम से भी कोई न कोई निजात पाने का तरीका निकाला जा रहा है और आगे आने वाले समय में, अभी तक कंसंट्रेशन था हर घर को बिजली देने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का, अब इफिसियेंसी, पंक्चुअलिटी और क्रेडिबलिटी को की योजना बनाने का माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है, उसको कराया जायेगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सदस्य तो चले गये हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन से अनुरोध है कि हमारी अनुदान माँगों को पारित करने की कृपा करें ।

(माननीय मंत्री के बजट भाषण का अंश-परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री भोला यादव, अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

(इस अवसर पर माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एक मिनट । सात निश्चय की योजना की घोषणा के बारे में हमने जो कहा था, वह 2014 में नहीं बल्कि 2015 में घोषणा हुई थी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी के वक्तव्य में सात निश्चय योजना की घोषणा का वर्ष जो 2014 बताया गया था, उसे 2015 माना जायेगा ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की माँग 10 रूपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

टर्न–26/आजाद/15.07.2019

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :–

''ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 88,94,31,85,000/– (अट्ठासी अरब चौरानवे करोड़ एकतीस लाख पचासी हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15 जुलाई, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 46 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिये जायं ।

(सभा की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 2019 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

.....

परिशिष्ट

बजट भाषण हेतु Talking Points - 2019

1. उत्पादन

चौसा (बक्सर) में 2X660 मेगावाट ग्रीन फील्ड तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड (SJVNL) द्वारा निविदा के उपरांत **मे० लार्सन एण्ड टुब्रो** को कार्य आवंटित किया गया है। प्रथम ईकाई का निर्माण वित्तीय वर्ष 2023–2024 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

बिहार के उत्पादन इकाईयों से सस्ता उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने BTPS के स्वामित्व को पूर्णतः NTPC को सौंप दिया। साथ ही KBUNL (काँटी बिजली उत्पादन निगम लि0) एवं NPGCL (नबीनगर पावर जेनरेटिंग कं0 लि0), जो NTPC एवं बिहार सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, इन दोनों उपक्रमों में बिहार सरकार के हिस्सा पूंजी को NTPC को सौंप दिया।

2. संचरण

संचरण के क्षेत्र में हमलोगों ने उत्साहवर्द्धक उपलब्धि हासिल की है जो निम्नलिखित आंकड़ों से प्रमाणित होता है:–

वर्ष	पीक–लोड
2015–16	3459 मेगावाट
2016–17	3769 मेगावाट
2017–18	4535 मेगावाट
2018–2019	5139 मेगावाट
2019–2020 (25 जून, 2019)	5598 मेगावाट ✓

विगत वर्षों में हमलोगों ने **65 नये ग्रिड उपकेन्द्र** निर्माण की स्वीकृति दी जिसमें **55 ग्रिड उपकेन्द्र** बनकर तैयार है तथा **10 निर्माणाधीन** है। वर्तमान में राज्य में कुल कार्यरत ग्रिड उपकेन्द्रों की संख्या **148 है जो 2019–20 तक बढ़कर 153** हो जायगी। वर्तमान में कार्यरत ग्रिड सब स्टेशनों से विद्युत

निकासी (**Evacuation**) **क्षमता 10,930 मेगावाट** है जो वर्ष 2019–20 के अंत में बढ़कर **11,346 मेगावाट** हो जायगी।

राज्य सरकार के द्वारा पहली बार राज्य योजना की राशि से **400/220/132 के०वी०** का जी०आई०एस० ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण **बख्तियारपुर** में कराया जाना है। निविदा अंतिम चरण में है। इस कार्य को मार्च 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं पावर ग्रिड कम्पनी के संयुक्त उपक्रम **बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (BGCL)** द्वारा भी **400/220/132 के०वी०** के दो जी०आई०एस० ग्रिड उपकेन्द्र **जक्कनपुर** एवं **नौबतपुर** का निर्माण कराया जा रहा है।

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा **400/220/132 के०वी०** के तीन ग्रिड उपकेन्द्र का निर्माण **सहरसा, सीतामढ़ी एवं चंदौती (गया)** में किया जा रहा है।

3. वितरण

- **ग्रामीण विद्युतीकरण** – राज्य सरकार द्वारा संकल्पित सात निश्चयों में से एक **"हर घर बिजली"** के तहत राज्य के सभी अविद्युतीकृत गाँवों एवं सभी **1,06,249 टोलों/बसावटों** को निर्धारित लक्ष्य क्रमशः **दिसम्बर 2017 एवं अप्रैल 2018** तक ऊर्जान्वित करते हुए सभी इच्छुक परिवारों को विद्युत संबंध देने के कार्य को **दिसम्बर 2018** के लक्ष्य से दो महीने से भी **पहले 25 अक्टूबर, 2018 को पूर्ण कर लिया गया।**

  वैसे इच्छुक उपभोक्ता जो नये टोलों या बसावटों में बस रहे हैं उन्हें भी सरल तरीके से एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत विद्युत संबंध प्रदान करने के लिए हम संकल्पित हैं एवं इस हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** – इस योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि (रू० 3496.33 करोड़) केन्द्रांश के रूप में एवं 40 प्रतिशत (रू० 2330.90 करोड़) राज्यांश के रूप में प्राप्त होगी। कुल **1312 कृषि हेतु अलग फीडर** तथा **295 शक्ति उपकेन्द्र** के निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिसमें से **826 फीडर** एवं **136 शक्ति उपकेन्द्र** का निर्माण किया जा चुका है। हमने यह दृढ़ निश्चय किया है कि **दिनांक 26.06.2019** तक कृषि के पटवन हेतु प्राप्त वैध आवेदनों को मिशन मोड में **दिसम्बर 2019** तक **विद्युत संबंध** दे दिया जाएगा।

  मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं गया जिला में पूर्व के फ्रेंचाइजी क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत मुख्यतः कृषि कार्य हेतु डेडीकेटेड फीडर के निर्माण, नये शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण, एवं नये वितरण केन्द्र के निर्माण हेतु कुल **582.59 करोड़ रूपये** की योजना स्वीकृत की गयी है। एजेंसी का चयन करते हुए कार्य प्रारंभ हो गया है। कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य वर्ष **मार्च 2021** है।

- **रिकंडक्टरिंग** – राज्य योजनान्तर्गत **71,672 सर्किट किलोमीटर पुराने एवं जर्जर तारों को चरणबद्ध** तरीके से बदलने के लिए **2,827.51 करोड़ रूपये** लागत का कार्य प्रगति पर है एवं अभी तक **31,582 सर्किट किलोमीटर** जर्जर तारों को बदला जा चुका है। इस कार्य के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के जर्जर **LT** तार को **Aerial Bunched Cable** के माध्यम से बदला जा रहा है। सम्पूर्ण कार्य को मिशन मोड में किया जा रहा है जिसे माह दिसम्बर 2019 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- **इंटिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट सिस्टम (आई.पी.डी.एस.)** – राज्य के 2011 जनगणना के आधार पर कुल चयनित **139 शहरों** में **133** शहरों में काम कराया जा रहा है जिसे पूरा करने का लक्ष्य **दिसम्बर 2019** है। 2018 में फ्रेंचाइजी के समाप्ति के उपरांत शेष **छः शहरों** के डी.पी.आर.

की स्वीकृति कराते हुए कार्य का आवंटन कर दिया गया है एवं कार्य प्रारंभ हो गया है। कार्य को मिशन मोड में शुरू किया गया है एवं इसे पूर्ण करने का लक्ष्य वर्ष 2020 है। इसके अतिरिक्त बिहार के विभिन्न शहरों हेतु उच्च तकनीक पर आधारित 20 जी.आई.एस./ई. हाउस शक्ति उपकेन्द्र बनाये जायेंगे।

- **मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना** – राज्य सरकार द्वारा अनुदान के लिए दी जाने वाली राशि हेतु **मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना** की शुरूआत की गयी जिसके अन्तर्गत विभिन्न श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत खपत में प्रति यूनिट अनुदान दिया जा रहा है एवं इस राशि को विद्युत विपत्र में अंकित भी किया जा रहा है।
- **स्पेशल प्लान योजना (BRGF)** के तहत मुख्य रूप से **53 नये पावर सब स्टेशनों** का निर्माण, **387 पावर सब स्टेशन के क्षमता वृद्धि** का कार्य, **21494 सर्किट किलोमीटर** नये तार लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- <u>राजस्व</u>

  - **AT&C Loss** में क्रमवार कमी –

वर्ष	**AT&C Loss**
2013–14	46.33 प्रतिशत
2014–15	43.82 प्रतिशत
2015–16	43.54 प्रतिशत
2016–17	39.74 प्रतिशत
2017–18	30.22 प्रतिशत
2018–19 (औपबंधिक)	27.39 प्रतिशत ✓

  - **Billing Efficiency में क्रमवार सुधार** :– शहर के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए भी **स्पॉट बिलिंग** करायी जा रही है।

इस सॉफ्टवेयर के उपयोग से उपभोक्ताओ को उनके घर पर ही मीटर आधारित सही विद्युत विपत्र की प्राप्ति होने लगी है।

वर्ष	**Billing Efficiency**
2014–15	58.74 प्रतिशत
2015–16	60.65 प्रतिशत
2016–17	66.68 प्रतिशत
2017–18	69.78 प्रतिशत
2018–19 (औपबंधिक)	75.67 प्रतिशत

❖ **राजस्व संग्रहण में बढ़ोत्तरी –**

वर्ष	राशि
2014–15	4933.08 करोड़ रूपये
2015–16	5538.78 करोड़ रूपये
2016–17	5808.44 करोड़ रूपये
2017–18	8001.00 करोड़ रूपये
2018–19	9071.31 करोड़ रूपये

वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रति माह औसतन **756 करोड़** रूपये की राशि की वसूली हुई है।

4. नई पहल

➢ सुविधाः–

विद्युत उपभोक्ताओं एवं नये आवेदकों के लिए राज्य में **"सुविधा"** नामक सिंगल विंडो हेल्पडेस्क की शुरूआत पेसू क्षेत्र के 12 प्रमण्डलों में की गयी है। शेष विद्युत आपूर्ति प्रमण्डलों में भी लागू कराया जायेगा।

कोई भी व्यक्ति या उपभोक्ता अपने विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के **"सुविधा"** सिंगल विंडो हेल्पडेस्क पर पहुँच कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगा या सेवाओं हेतु आवेदन दे सकेगा।

- **विद्युत भवन–3 एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड कॉलोनी के आवासीय परिसर में सामुदायिक भवन एवं ऑडिटोरियम का निर्माण :–**

  विद्युत भवन परिसर में **विद्युत भवन–3 (लागत 84.73 करोड़ रूपये)** एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड कॉलोनी परिसर में एक **ऑडिटोरियम (लागत 22.30 करोड़ रूपये)** तथा एक **Pre fabricated सामुदायिक भवन (लागत 8.31 करोड़ रूपये)** का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

- **ओडिशा में विद्युत संरचना का पुनर्स्थापन –**

  चक्रवाती तूफान (फेनी) ने ओडिशा राज्य में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। विद्युत आपूर्ति, संचार प्रणाली एवं जलापूर्ति व्यवस्था ध्वस्त हो गई। इस घड़ी में **बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड** द्वारा अपने **14 विद्युत अभियन्ताओं** को बिहार में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के कर्मियों के साथ **दो टीम** बनाकर भेजा गया। विद्युत अभियन्ता एवं एजेंसियों की टीम ने दिन रात काम कर तटीय इलाकों में विद्युत आपूर्ति बहाल कराया।

5. सौर ऊर्जा

सरकार राज्य में अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए दृढ़संकल्प है। इसी दिशा में राज्य में 250 मेगावाट सौर ऊर्जा के परियोजना के अधिष्ठापन हेतु ब्रेडा द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी है। इससे राज्य में लगभग 1250.00 करोड़ रूपये के निवेश के साथ स्थानीय निवासियों को भी रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। वितरण कम्पनियों को भी अपने RPO (Renewable Purchase Obligation) लक्ष्य को प्राप्त करने में सुविधा होगी।

नए ग्रिड उपकेन्द्रों की घोषणा

1. 400/220/132 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, छपरा
2. 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बरारी (भागलपुर)
3. 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, दाउद नगर (औरंगाबाद)
4. 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बाराचट्टी (गया)
5. 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, मानपुर (भोरे), गया
6. 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, मुरलीगंज (मधेपुरा)
7. 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र, बगहा (पश्चिमी चम्पारण)